[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय सूची

दशम माला, खंड 14, चौथा स्त्र, 1992 / 1914 (सक)

अंक 13, शुक्रवार, 24 जुलाई, 1992/2 अगस्त, 1914 (सक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर:	1-170
तारांकित प्रश्न संख्या: 245 से 250, 252 से 259, 261, 263 और 264	1-12
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2527 से 2586, 2588 से 2594, 2596 से 2620, 2622 से 2627, 2629 से 2666 और 2668 से 2713	13-170

लोक सभा

शुक्रवार, 24 जुलाई, 1992/2 श्रावण, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे मन्पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

श्री सत्यगोपाल मिश्र (तामलुक): महोदय, प्रधान मंत्री कहां हैं? (व्यवधान)
इस समय श्री सुदर्शन राय चौधरी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये।

अध्यक्ष महोदय: आप सभी कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप मुझे सुनना चाहते हैं या नहीं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं किसी को भी बिल्कुल नहीं सुन पा रहा हूँ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप मुझे सुनने को तैयार हैं या नहीं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप मुझे सुनना चाहेंगे या नहीं?

(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

“एड इंडिया कंशोरियम” से सहायता

*245. श्री जार्ज फर्नांडीज:

श्री पी० एम० सर्जद:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेरिस में 24 जून, 1992 तक आयोजित “एड कंशोरियम” की बैठक में उच्च-स्तरीय भारतीय शिष्टमंडल ने भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो उसमें दिए गए सुझावों और सिफारिशों का ब्यौर क्या है और भारत को सहायता के रूप में कितनी धनराशि मिलने की संभावना है; और

(ग) भारत को यह धनराशि कब तक दी जाएगी और अब तक कितनी धनराशि प्राप्त हो चुकी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) जी, हां। भारत सहायता संघ की बैठक 25-26 जून, 1992 को पेरिस में हुई थी।

(ख) अनेक दाता देशों और बहुपक्षीय संस्थानों के प्रतिनिधियों ने सरकार द्वारा शुरू किए गए आर्थिक

सुधारों के लिए समर्थन व्यक्त किया। सुधारों की व्यापक सफलता पर पूरा समर्थन देते हुए उन्होंने यह आशा व्यक्त की कि मध्यावधि में भी इन सुधारों पर आगे क्रूरवाई की जाएगी। संघ के सदस्यों ने वर्ष 1992-93 के लिए 7.2 अरब अमेरिकी डालर की सहायता-वचनबद्धता दर्शाई जिसमें शीघ्र संवितरण सहायता के संबंध में 3.4 अरब अमेरिकी डालर शामिल हैं। शीघ्र संवितरण सहायता के आंकड़ों में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 1.6 अरब अमेरिकी डालर की राशि शामिल है जो 7.2 अरब अमेरिकी डालरों के आंकड़े में शामिल नहीं की गई है।

(ग) सहायता की इस वचनबद्धता संबंधी मात्रा की उपलब्धता निम्नलिखित पर निर्भर होगी:—

- (i) दाता देशों/संस्थाओं के वैधानिक/प्रशासनिक अनुमोदन;
- (ii) उपयुक्त परियोजनाओं की पहचान, उनका निरूपण और तत्संबंधी बातचीत;
- (iii) समुचित बजटीय प्रावधानों के बाद परियोजनाओं के अधीन व्यय; और
- (iv) परियोजना व्ययों के लिए दाता अभिकरणों से प्रतिपूर्तियां प्राप्त करना।

वस्त्र उद्योग में पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी

*246. श्री श्रवण कुमार पटेल: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हथकरघा और विद्युतकरघा सहित वस्त्र उद्योग में पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी अपनाने पर खर्च होने वाली राशि के बारे में कोई अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसमें विदेशी मुद्रा का अंश कितना होगा; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसी प्रौद्योगिकी अपनाने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) जी नहीं,

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार वस्त्र क्षेत्र में अनुकूल प्रौद्योगिकी अपनाने को प्रोत्साहन दे रही है जिसमें अनुसंधान व विकास के क्रियाकलाप भी शामिल हैं।

[हिन्दी]

वस्तु-विनिमय व्यापार

*247. श्री राजेश कुमार: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1988—90 के दौरान किन-किन देशों के साथ वस्तु-विनिमय व्यापार किया गया था;

(ख) उक्त अवधि के दौरान भारत द्वारा आयात और निर्यात किये गये सामान का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी व्यापार व्यवस्था से भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन और लाभ मिला है; और

(घ) यदि हां, तो और अधिक देशों के साथ वस्तु-विनिमय व्यापार शुरू करने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रो० पी० जे० कुरियन: (क) और (ख) वर्ष 1988 से 1990 के दौरान भारत का किसी भी देश के साथ वस्तु-विनिमय व्यापार नहीं था।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तम्बाकू उद्योग को ऋण सुविधा

*248. प्रो० उम्पारेड्डि वेंकटेश्वरलु:

श्री अन्बारासु इरा:

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या तम्बाकू उद्योग को दिए जाने वाले संस्थागत ऋण की राशि में कमी आई है;
- (ख) क्या तम्बाकू व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल इस संबंध में उनसे मिला था;
- (ग) क्या ऋण सुविधाओं संबंधी उनके अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन): (क) से (घ) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी नहीं। वास्तव में तो, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार तम्बाकू उद्योग को मिलने वाले ऋण में वृद्धि हुई है।

(ख) जी हां। कुछ निर्यातकों का प्रतिनिधि मंडल अन्य बातों के साथ-साथ मुख्य रूप से यह बताने के लिए जून, 1992 के पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री महोदय से मिला था कि रूसी प्राधिकारियों द्वारा 15000 मीट्रिक टन तम्बाकू के लिए साख पत्र (एल सी) खोलने में विलम्ब हुआ है और उन्हें धन की कमी का सामना करना पड़ रहा है, अतः वे अपने बैंकों से वित्तीय सुविधा-समायोजन चाहते हैं।

(ग) और (घ) इस मामले को भारतीय रिजर्व बैंक तथा संबंधित बैंकों के साथ तत्काल ठठया गया था और उसके जवाब में बैंकों ने सकरात्मक रुख अपनाकर वास्तविक आवश्यकता वाले सभी मामलों में आवश्यक ऋण सुविधाएं प्रदान की थीं। इसके अलावा, रूसियों को उनके निश्चित अनुरोध पर तकनीकी ऋण की पहली किस्त दी जा चुकी है ताकि वे, अन्य अनेक मदों के साथ, तम्बाकू भी खरीद सकें। संविदागत राशि के कुछ भाग के लिए रूस द्वारा अब ऋण पत्र खोले जा चुके हैं। सरकार तकनीकी ऋण के लिए रूस के और अनुरोध पर भी अनुकूल विचार करेगी बशर्तें उसका उपयोग तम्बाकू की उपर्युक्त रोच मात्रा के निर्यात के लिए किया जाए।

सरकार रूस पर भारत के संबंध में उनके निर्यात लक्ष्य पूरे करने के लिए दबाव डालती रही है ताकि व्यापार संलेख में निहित भारतीय निर्यातों के लक्ष्य पूरे करने के लिए 'बर्षांत' धन जुटाया जा सके।

भारतीय कंपनियों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शेयर

*249. श्री राम नरेश सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उनके द्वारा प्रमोट की गई भारतीय कंपनियों में अपने शेयर बढ़ाने की अनुमति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या शर्तें रखी गई हैं तथा अतिरिक्त शेयरों के लिए दिया जाने वाला मूल्य निर्धारित करने हेतु क्या प्रक्रिया/मानदंड अपनाये गये हैं;

(ग) क्या कुछ मामलों में इस प्रकार निश्चित किये गये शेयरों के मूल्य बाजार मूल्यों से कम हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई/करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) से (ङ) भारतीय कंपनियों में विदेशी इक्विटी में वृद्धि करने की प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय द्वारा 29.6.92 को जारी की गई प्रेस टिप्पणी 13 में निर्धारित की गई है। इसमें कहा गया है कि 11 और 17 जून, 1992 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के जारी होने के बाद, 51 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी जुटाने की इच्छुक मौजूदा कंपनियां शेयरों के तरजीही आवंटन के माध्यम से ऐसा कर सकती हैं बशर्ते कि शेयर धारकों द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 81(1) (क) के अन्तर्गत विशेष प्रस्ताव में इसका अनुमोदन किया गया हो। नए निर्गमों के मूल्य निर्धारण करने पर नियंत्रण समाप्त कर देने से ऐसे नियमों के मूल्य का निर्धारण शेयर धारकों द्वारा किया जाता है और इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। ये अनुदेश अल्पजन धारित कंपनियों के साथ-साथ उन कंपनियों पर भी लागू होते हैं जिनमें अभी तक कोई विदेशी शेयर धारिता नहीं है।

एल०आई०सी० हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा ऋण देना

*250. श्री हाराधन राय: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लाइफ इन्श्योरेंस कारपोरेशन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का प्रस्ताव "ओन युअर होम स्कीम" के अंतर्गत बड़े पैमाने पर आवासीय ऋण देने हेतु पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों में केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और ये केन्द्र किन-किन स्थानों में खोले जायेंगे; और

(ग) जीवन बीमा निगम द्वारा इस प्रयोजनार्थ दिए जाने वाले ऋणों का ब्यौरा क्या है

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ख) जी हां। जीवन बीमा निगम आवास वित्त लिमिटेड पश्चिम बंगाल में हावडा और सिलीगुड़ी में क्षेत्रीय कार्यालय तथा आसनसोल में एक एकक कार्यालय खोलेगा। निगम द्वारा सारे देश में 16 और क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है।

(ग) चालू वर्ष के दौरान, कम्पनी द्वारा अपने कार्यालयों के माध्यम से पश्चिम बंगाल में लगभग 30 करोड़ रुपये की राशि के 4000 अलग-अलग ऋण मंजूर किए जाने की आशा है। कम्पनी द्वारा सारे देश भर में 75000 अलग-अलग ऋण दिए जाने का अनुमान है जिनकी कुल राशि 650 करोड़ रुपये बैठती है।

बैंक आफ मदुरा लिमिटेड

*252. श्री अन्ना जोशी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रिजर्व बैंक ने अप्रैल-मई, 1992 में बैंक आफ मदुरा लिमिटेड के परिसमापन की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस बैंक के शेयरधारकों, जमाकर्ताओं और खाताधारियों के हितों की रक्षा किस प्रकार की जाएगी; और

(घ) बैंक की देनदारियों को किस रकार पूरा करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंक की वित्तीय स्थिति संतोषजनक है।

भुगतान न करने वाले खातेदारों के खातों का बैंकों द्वारा नवीकरण

*253. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सहकारी बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंक वसूल नहीं हुई ऋण-रशि का प्रतिशत कम दिखाने के लिए उन खातेदारों के खातों (डिफाल्टिड अकाउन्ट्स) का नवीकरण कर देते हैं जिन्होंने ऋण की अदायगी नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस प्रकार के कदाचारों को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रकार नियंत्रण करता है; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा चूककर्ता खातों का नेमीरूप से नवीकरण नहीं किया जाता है। नकद उधार, ओवरड्राफ्ट, खरीदे गए/भुनाए गए बिलों जैसी सुविधाएं उधारकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए आवश्यक वित्तीय आंकड़ों के आधार पर तथा आंतरिक निरीक्षण टिप्पणियों, बाह्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों और भारतीय रिजर्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्टों में बताई गई सभी अनियमितताओं को ध्यान में रखने के बाद वार्षिक समीक्षा/नवीकरण के अधीन होती हैं। अधिक चूकों वाले खातों का नवीकरण नहीं किया जाता है। लेकिन, जिन अग्रिमों में केवल प्रक्रियात्मक अनियमितताएं होती हैं, उनका नवीकरण करने या उनकी वापसी अदायगी अनुसूचियों को पुनः निर्धारित करने पर विचार किया जाता है। सहकारी बैंक सामान्यतया अनियमित खातों का नवीकरण नहीं करते।

सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण किया जाता है। प्रमुख निष्कर्षों

की सूचना संबंधित बैंकों को दे दी जाती है और उनके प्रबंधन के साथ उन पर चर्चा भी की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से अत्यधिक अवरोध उधार खातों पर बारीकी से नजर रखने के लिए अधिकारियों को पदनामित करने के लिए भी कहा जाता है।

युद्ध में मारे गये सैनिकों की विधवाओं के लिए गुजरात में पुनर्वास केन्द्र

*254. डा० ए० के० पटेल:

श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) युद्ध के दौरान मारे गये सैनिकों की विधवाओं के लिए गुजरात राज्य में कितने-कितने और कहाँ-कहाँ पुनर्वास केन्द्र स्थापित किये गये हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इन केन्द्रों को आवंटित की गई धनराशि तथा इनके कार्यकारणों का ब्यौर क्या है;

(ग) क्या सरकार को इन केन्द्रों के उचित ढंग से कार्य न करने के संबंध में कोई शिकायतें/अप्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार): (क) युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों के लिए गुजरात में कोई पुनर्वास केन्द्र नहीं खोला गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

खोप कर

*255. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तर-राज्यीय माल खोप पर कर लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की सम्भावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) जी, हां।

(ख) और (घ) सार्वजनिक वित्त तथा नीति संबंधी राष्ट्रीय संस्थान, जिसे इस मुद्दे की विशेषतया सौदों के स्वरूप तथा उन चिन्तनों की श्रेणियों की जांच करने का अनुरोध किया गया था, जिन्हें प्रस्तावित शुल्क से छूट दी जानी थी, ने अक्टूबर, 91 को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी। डाक्टर राजू केलैया की अध्यक्षता वाली कर सुधार समिति ने सरकार को पेश की गई अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में परेकण कर के संबंध में कतिपय टिप्पणियाँ भी की थीं। कर सुधार समिति की इन टिप्पणियों के साथ-साथ सार्वजनिक वित्त तथा नीति संबंधी राष्ट्रीय संस्थान की रिपोर्ट की सभी राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों को उनकी टिप्पणियों हेतु भेज दिया गया है। अब तक संबंधित सभी केन्द्रीय मंत्रालयों और 12 राज्य सरकारों से टिप्पणियाँ प्राप्त हो गई हैं। बाकी राज्य

सरकारों की टिप्पणियां भी जैसे ही प्राप्त हो जाती हैं, इस मामले में अन्तिम निर्णय लेने के लिए संबंधित सभी पक्षों की एक बैठक बुलाए जाने का प्रस्ताव है।

रूस को तम्बाकू का निर्यात

*256. श्री दत्तात्रेय बंडाकर: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फरवरी, 1992 में रूस राष्ट्रकुल (फेडरेशन) के साथ तम्बाकू तथा सिगरेटों के निर्यात हेतु व्यापार करार पर हस्ताक्षर किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या रूस ने तदनु रूप तम्बाकू तथा सिगरेटों का आयात किया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और रूस ने अब तक वास्तव में तम्बाकू तथा सिगरेटों का कितना-कितना आयात किया है;

(घ) क्या बाजार में तम्बाकू और सिगरेटों के अधिक मात्रा में जमा हो जाने के फलस्वरूप तम्बाकू की कीमतें गिर गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का तम्बाकू उत्पादकों के हितों की रक्षा हेतु क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन): (क) से (ङ) एक विवरण-पत्र सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) और (ग) रूस ने मार्च, 1992 में 15000 टन तम्बाकू के लिए क्रयादेश दिया है जबकि व्यापार योजना में 25000 टन का प्रावधान है। सिगरेट के संबंध में लगभग 2500 मिलियन सिगरेट के लिए क्रयादेश दिए गए थे लेकिन संबंधित निर्यातकों द्वारा अभी तक संविदाओं का पंजीकरण नहीं कराया गया है। तम्बाकू और सिगरेटों का जून, 1992 तक कोई निर्यात नहीं किया गया था, क्योंकि संविदागत मात्राओं के लिए भी साख पत्र नहीं खोले गए थे। जून के अन्तिम सप्ताह तथा जुलाई के पहले सप्ताह में 25 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के साख पत्र खोले गए। इनमें 9600 टन तम्बाकू कवर होता है। इस 9600 टन तम्बाकू का निर्यात किया जा रहा है।

(घ) पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष तम्बाकू की कीमतों में गिरावट आई है।

(ङ) सरकार ने तम्बाकू बोर्ड को पहले ही सलाह दे दी है कि फसल की मात्रा का निर्धारण व्यापारियों तथा तम्बाकू उपजकर्ताओं के प्रतिनिधियों के परामर्श से मांग तथा बाजार स्थिति की आवश्यकताओं का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने के बाद किया जाए।

सोने के आभूषणों का निर्यात

*257. श्रीमती गीता मुखर्जी: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या गत कुछ महीनों से सोने के आभूषणों का निर्यात व्यापार बंद हो गया है;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है और उसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या प्रतिभूति घोटाले के बाद सोना प्राप्ति के स्रोतों में कमी आ जाने के कारण भारतीय स्टेट बैंक निर्यातकों को पर्याप्त सोने की आपूर्ति नहीं कर पा रहा है;
- (घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है; और
- (ङ) इस संबंध में क्या उपाय करने का प्रस्ताव है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन): (क) और (ख) जी नहीं। वस्तुतः अप्रैल से जून, 1992 तक सोने के आभूषणों का निर्यात पिछले वर्ष की उसी अवधि के दौरान हुए निर्यात से अधिक था।

(ग) और (घ) भारतीय स्टेट बैंक ने बताया है कि टकसाल द्वारा आयातित सोने को परिवर्तित करने से संबंधित समस्याओं की वजह से कुछ समय के लिए आपूर्ति में कुछ बाधा आई थी। सोने की आपूर्ति में कमी का कारण भारतीय स्टेट बैंक के पास संसाधनों की कमी नहीं था।

(ङ) भारतीय स्टेट बैंक को अब अनुमति दे दी गई है कि वह 0.995 शुद्धता वाले सोने का आयात करे और उसकी आपूर्ति सोने के आभूषणों के निर्यातकों को सीधे ही करे। इसके अतिरिक्त, भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम को भी चरेलू टैरिफ क्षेत्र में आभूषणों के निर्यातकों को सोने की आपूर्ति करने के लिए एक अभिकरण के रूप में अधिसूचित किया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग

*258. श्री के० डी० सुस्तानपुरी:

श्री० वी० राजेश्वरन:

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जिन सड़कों / राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव है, उनका राज्यवार ब्यौर क्या है;
- (ख) वर्ष 1992-93 के दौरान किन-किन सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव है; और
- (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एवं वर्ष 1992-93 में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों के निर्माण के प्रस्तावों का ब्यौर क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) और (ख) विभिन्न राज्य सरकारों ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग 37,566 कि०मी० की लम्बाई वाले नये राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किये जाने के लिये कुल 135 प्रस्ताव भेजे हैं। निर्धारित मानदंड के अनुसार प्रस्तावों की विस्तृत जांच करने के लिये, राज्य सरकारों को, निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक प्रस्ताव के पूरे ब्यौर / औचित्य आदि देते हुये सूचना भेजने के लिये अनुरोध किया गया था। अनेक राज्यों से अभी यह सूचना आनी शेष है। निधियों का

भी अपाव्य है। इसलिये वर्ष 1992-93 सहित आठवीं योजना में नौ राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में अभी से कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता।

(ग) विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर 141 पुलों की संस्वीकृति के प्रस्तावों को वर्ष 1992-93 के वार्षिक कार्यक्रम में शामिल किया गया है। 500 लाख रु० और इससे अधिक अनुमानित लागत के पुलों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

वर्ष 1992-93 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों के निर्माण के लिए प्रस्ताव

क्रम सं०	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (लाख रु०)
दिल्ली		
1.	र० र० 24 पर निजामुद्दीन पुल को चौड़ा करना गोवा	3000.00
2.	जुआरी पुल को मजबूत करना गुजरात	600.00
3.	र० र० 8 पर 192/0-198/0 कि० मी० के बीच जदेश्वर के निकट नर्मदा नदी पर पहुंच मार्गों सहित अतिरिक्त लेन वाले पुल का निर्माण।	4000.00
हिमाचल प्रदेश		
4.	र० र० 20 पर चाक्री खंड पर पुल का निर्माण कर्नाटक	2000.00
5.	र० र० 17 पर सरस्वती नदी पर नये पुल और इसके पहुंच मार्गों का निर्माण	2000.00
6.	र० र० 17 सरस्वती नदी पर मौजूदा पुल का पुनर्निर्माण। केरल	500.00
7.	र० र० 17 पर 431-437 कि० मी० पर वाराणसी पुल	2220.00
8.	र० र० 17 पर कालीकट बाईपास पर आरापूजा पुल	600.00
9.	र० र० 17 पर त्रिवेन्द्रम बाईपास पर अकुलम पुल। मध्य प्रदेश	600.00
10.	र० र० 6 पर 318/8 कि०मी० में सिओनाथ पुल	500.00
महाराष्ट्र		
11.	र० र० 8 पर 497/0 कि०मी० में बेसिन ब्रीक पुल	1800.00

क्रम सं०	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (लाख रु०)
पंजाब		
12.	ए० ए० 21 पर 56 कि०मी० में सिरसा नदी	790.00
राजस्थान		
13.	ए० ए० 12 के 346 कि०मी० में काली सिंधु पुल	900.00
उत्तर प्रदेश		
14.	ए० ए० 27 पर इलाहाबाद में नैनी में यमुना पुल।	9000.00

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश सरकार को ऋण

*259. श्री अर्जुन सिंह यादव: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना-कितना ऋण किस-किस प्रयोजन हेतु मांगा?

(ख) राज्य सरकार को उक्त अवधि में कितना-कितना ऋण मंजूर किया गया;

(ग) क्या राज्य सरकार को मंजूर किया गया ऋण उसकी मांग से काफी कम था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतखे): (क) से (घ) विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) उत्तर प्रदेश सरकार ने नवें वित्त आयोग की दूसरी रिपोर्ट के पैरा 7.31 के अनुसरण में राजस्व खाते में संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए 1990-91 में 500 करोड़ रुपए का तथा 1991-92 में 787 करोड़ रुपए की दीर्घकालीन योजनागत ऋण मांगा था। उन्होंने 1991-92 के लिए, जापान से सहायताप्राप्त अनपाड़ा "बी" ताप विद्युत परियोजना की 254 करोड़ रुपए की अप्रतिपूर्तिकारी लागत के 50% के रूप में 127 करोड़ रुपए की विशेष ऋण सहायता भी मांगी थी।

(ख) नवें वित्त आयोग ने अपनी दूसरी रिपोर्ट के पैरा 7.31 में सुझाव दिया था कि केन्द्र को उत्तर प्रदेश सहित दस राज्यों की समग्र कमी को अंशतः पूरा करना चाहिए। आयोग के इस सुझाव को, जोकि सिफारिश नहीं थी, सरकार ने स्वीकार नहीं किया था। अतः इस प्रयोजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को कोई भी राशि रिलीज किए जाने का प्रश्न नहीं उठता था। इसलिए 1990-91 में 500 करोड़ रुपए तथा 1991-92 में 787 करोड़ रुपए के दीर्घकालीन ऋण दिए जाने के अनुरोधों को स्वीकार नहीं किया गया था।

तथापि, भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने 1990-91 के दौरान उत्तर प्रदेश में अल्प बचत पत्रों में 267 करोड़

रुप की अतिरिक्त राशि का निवेश किया जिसके प्रति राज्य को 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अल्प बचत ऋण प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश को उसकी लम्बे समय से चली आ रही कुछ विशेष समस्याओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 1990-91 में 150 करोड़ रुपए भी दिए गये थे।

1991-92 के दौरान, एक विशेष मामले के रूप में अप्रतिपूर्तिकारी स्थानीय लागत के 50% के रूप में 127 करोड़ रुपए की ऋण सहायता हेतु राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया था तथा राज्य सरकार को 127 करोड़ रुपए की राशि विभिन्न बन्दरगाहों में पड़े हुए मशीनरी उपकरण पर देय सीमा शुल्क के प्रति बही में समायोजन के जरिए विद्युत विभाग ने रिलीज कर दिए थे।

(ग) राज्य सरकार द्वारा 1990-91 में मांगे गए 500 करोड़ रुपए के ऋण तथा 1991-92 में मांगे गए 914 करोड़ रुपए के ऋण के प्रति राज्य सरकार को 1990-91 तथा 1991-92 में क्रमशः 350 करोड़ रुपए और 127 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त राशि प्राप्त हो गई थी।

(घ) केन्द्र के पास संसाधनों की भारी कमी के कारण इन दो वर्षों के दौरान राज्य सरकार को और कोई वित्तीय सहायता देना संभव नहीं था।

[अनुवाद]

अफीम की खेती

*261. श्री झरद बाहद्वः क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में किन्-किन् स्थानों पर तथा कुल कितने क्षेत्र में अफीम की खेती की जाती है;

(ख) इन क्षेत्रों में वर्ष 1991-92 के दौरान अफीम का कितना उत्पादन हुआ;

(ग) उक्त अवधि में देश में अफीम का अवैध उत्पादन कितना हुआ;

(घ) वैध रूप से हुए अफीम के उत्पादन में से अनुमानतः कितनी अफीम का स्वापक पदार्थ बनाने के लिए प्रच्छन्न रूप से उपयोग किया जाता है; और

(ङ) अफीम का अवैध व्यापार रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न निवारक उपायों में क्या कमियाँ हैं तथा विद्यमान उपायों को सशक्त बनाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

अफीम-पोस्त की खेती केवल मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यों में अधिसूचित भू-क्षेत्रों में ही की जाती है। वर्ष 1991-92 के दौरान, लगभग 14, 214 हेक्टेयर भू-क्षेत्र पर पोस्त की खेती करने के लिए लाइसेंस दिए गए थे। वर्ष 1991-92 के दौरान 90° संसक्ति वाली 4,68,494 किलोग्राम (अनन्तिम) अफीम का उत्पादन किया गया था।

चूंकि अफीम का अवैध उत्पादन और स्वापक औषध द्रव्यों के रूप में परिवर्तित करने के उद्देश्य से वैध रूप से उत्पादित अफीम को अन्यत्र भेजने का कार्य एक चोरी-छिपे किए जाने वाला धन्धा है, इसलिये उसके ठीक-ठीक परिमाण का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

इस बात पर विचार करते हुए कि अफीम-पोस्त की खेती 14,214 हेक्टेयर भूमि पर और 6560 गांवों में की

जाती है, वैध खेती में से अफीम की कुछ मात्रा की चोरी होने की बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अफीम और अन्य स्वापक पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए, स्वापक औषध द्रव्य तथा मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 तथा स्वापक औषधि और मनःप्रभावी अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 जैसे कठोर कानूनों का अधिनियमन किया गया है जिनमें सख्त दण्ड और निवारक नजरबन्दी की व्यवस्था की गई है। पोस्त की खेती वाले क्षेत्रों में और उसके आस-पास निवारक तथा आसूचना तन्त्र को सुदृढ़ कर दिया गया है। नशीले औषध द्रव्यों के प्रवर्तन संबंधी कार्य में लगी एजेंसियां कड़ी निगरानी रखती हैं और अफीम की खेती, लासिंग करने और इसको एकत्रित करने की पूरी अवधि के दौरान प्रवर्तन संकायों में तेजी लाती हैं। नशीले औषध द्रव्यों के अवैध व्यापार को कारगर ढंग से रोकने के लिए सभी केन्द्रीय और राज्य प्रवर्तन एजेंसियों के बीच घनिष्ठ तालमेल रखा जाता है।

वस्त्र निर्यात क्षेत्र

*263. श्री धर्मगणा मोडय्या सादुल: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान देश के विभिन्न भागों में उत्पादन केन्द्रों के रूप में वस्त्र निर्यात क्षेत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है; और

(ग) ऐसे केन्द्र कहाँ-कहाँ स्थापित किए जाएंगे?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय पटसन वस्तु निर्माण निगम द्वारा प्रस्तुत योजना

*264. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद:

श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय पटसन वस्तु निर्माण निगम ने पटसन उद्योग को अर्थक्षम बनाने के लिए एक विस्तृत योजना केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए भेजी है;

(ख) क्या सरकार ने इस निगम में हुए घाटे के कारणों का पता लगा लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) जी हां।

(ख) और (ग) एन जे एम सी में घाटे होने के कारण अन्य बातों के साथ-साथ, अप्रचलित मशीनों के कारण कम क्षमता उपयोग, फलतः जनशक्ति, कम उत्पादकता तथा संचित नगदी घाटों पर ब्याज का भार माने जा सकते हैं।

(घ) सरकार ने एन जे एम सी के प्रस्ताव पर अभी विचार नहीं किया है।

आवेदन पत्र धनराशि का वापस न मिलना

2527. श्री राम नाईक: क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निवेशकों की ओर से शेयरों/ऋण पत्रों की प्राप्ति हेतु आवेदन पत्रों की अन्तिम तिथि के दस सप्ताह पश्चात् आवेदन पत्र धनराशि तथा उस पर ब्याज के वापस न मिलने के संबंध में सरकार को 1990-91 और 1991-92 के दौरान कितनी शिकायतें मिलीं;

(ख) क्या सरकार ने दोषी कम्पनियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर, कम्पनी-वार क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज): (क) और (ख) कम्पनी कार्य विभाग तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों को अनेक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं जिनमें आवेदन शुल्क तथा उस पर ब्याज वापस न करने से संबंधित शिकायतें भी शामिल हैं। तथापि, ऊपर लिखित स्वरूप की शिकायतों के संबंध में केन्द्र द्वारा अलग से कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। किसी कम्पनी के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होने पर कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत आगामी यथोचित कार्यवाही शुरू करने हेतु वास्तविक स्थिति का पता लगाने तथा कम्पनी का उत्तर प्राप्त करने के लिए मामलों पर कार्रवाई की गई थी।

(ग) और (घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 73(2क) के निबन्धनों के अनुसार कम्पनी कार्य विभाग के निर्देशों के अधीन कम्पनी रजिस्ट्रारों द्वारा संबंधित न्यायालयों में तीन कम्पनियों के संबंध में अभियोजन के लिए कार्यवाही की गई है।

[हिन्दी]

सड़क/एक्सप्रेस मार्गों का निजीकरण

2528. श्री ललित उरांव: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 में संशोधन करके चुने हुए रूटों पर लेव्य लगा करके सड़कों और एक्सप्रेस मार्गों के निजीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु संसाधनों में वृद्धि करने के लिए निजी क्षेत्र को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 में संशोधन जो दिनांक 27.2.1992 को लोकसभा में पेश किया जा चुका है, इसके लिए एक पूर्व-अपेक्षा है, ताकि राष्ट्रीय राजमार्गों के अधिसूचित खण्डों पर शुल्क वसूल किया जा सके।

विकसित देशों में फूलों की मांग

2529. श्री गोविन्दराव निकाम: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विकसित देशों में फूलों की मांग काफी बढ़ गई है;
 (ख) यदि हां, तो इस मांग को पूरा करने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है;
 (ग) क्या सिंगापुर में फूल नीलामी केन्द्र स्थापित किए जाने की संभावना है;
 (घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इससे लाभ कमाने हेतु कोई योजना तैयार करने का है; और
 (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) जी हां।

(ख) पुष्प कृषि को ध्रष्ट क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात किया गया है और बढ़ती हुई विश्व मांग का लाभ उठाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

(ग) से (ङ) बताया जाता है कि सिंगापुर 1993 तक पुष्प नीलामी केन्द्र आरम्भ कर देगा। जैसे ही सिंगापुर में इस प्रकार का नीलामी केन्द्र स्थापित हो जाएगा, निर्यातकों को उनके उत्पाद की बिक्री तथा बाजार जानकारी आदि के जरिए लाभ मिलने लगेगा।

[अनुवाद]

लौह अयस्क निर्यात कोटा

2530. श्री लोकनाथ चौधरी: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या धातु और खनिज व्यापार निगम ने पारदीप पत्तन द्वारा किए जाने वाले लौह अयस्क के निर्यात में कमी करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इससे पारदीप पत्तन की अर्थव्यवस्था के कितना प्रभावित होने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) जापानी इस्पात कारखानों में अधिक सामान होने तथा जापान में वर्ष 1992-93 में बहुत कम उत्पादन होने के पूर्वानुमान के कारण जापान ने पारदीप पत्तन में अनुबंधित मात्रा को 1991-92 के लिए 17 लाख मी० टन से कम करके 1992-93 के लिए 11 लाख मी० टन कर दिया है।

(ग) पारदीप पत्तन के जरिए होने वाले कुल व्यापार में से 25% लौह-अयस्क होता है। पारदीप पत्तन के जरिए वर्ष 1992-93 के दौरान लौह-अयस्क के निर्यातों में कमी से न केवल पत्तन के राजस्व पर ही प्रभाव पड़ेगा अपितु कोकिंग कोयला का व्यापार भी कम होगा क्योंकि कोकिंग कोल के प्रेषण के लिए खाली लौह-अयस्क बैगन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होंगे।

विदेशी ऋण

2531. श्री सैयद शाहाबुद्दीन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 अप्रैल, 1992 को विशेष आहरण अधिकारों और रुपयों में विदेशी मुद्रा संतुलन की स्थिति क्या थी;

(ख) 1991-92 के दौरान विशेष आहरण अधिकारों तथा रुपयों के संदर्भ में देश पर कितना अतिरिक्त विदेशी ऋण था;

(ग) अदृश्य राशि सहित वर्ष 1991-92 के व्यापार संतुलन की घनराशि कितनी है; और

(घ) 1992-93 के दौरान विदेशी ऋण अदायगी पर कितनी घनराशि व्यय होने का अनुमान है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) एक अप्रैल, 1992 को विदेशी मुद्रा शेष 41050 लाख एस०डी०आर० के बराबर 14578 करोड़ रुपए था।

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान देश पर हुआ अतिरिक्त विदेशी ऋण 49330 लाख एस०डी०आर० के बराबर 15901 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

(ग) अनन्तिम अनुमान दर्शाते हैं कि वर्ष 1991-92 के लिए व्यापार संतुलन की राशि जिसमें अदृश्य राशि भी शामिल है, लगभग 8200 करोड़ रुपए विपरीत है।

(घ) वर्ष 1992-93 के विदेशी ऋण की वापसी अदायगी की अनुमानित राशि 9424 करोड़ रुपए है।

सैन्तला स्थित रक्षा उत्पादन एकक

2532. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सैन्तला, उड़ीसा स्थित रक्षा उत्पादन एकक में कितने स्थानीय लोगों को रोजगार देने का विचार है; और

(ख) उनमें से परियोजना के क्रियान्वयन के कारण विस्थापित हुए व्यक्तियों की संख्या कितनी है?

रक्षा मंत्री (श्री झरद घवार): (क) और (ख) विस्थापित हुए 1020 परिवारों में से, अब तक 241 व्यक्तियों को रोजगार दिया जा चुका है। रोजगार की व्यवस्था संबंधित परियोजना की आवश्यकताओं और उम्मीदवारों की नौकरी की शर्तों को पूरा करने पर निर्भर करती है, अतः इस समय यह बताना संभव नहीं है कि बाकी परिवारों में से कब और कितने को रोजगार दिया जा सकेगा।

अमिताभ घोष समिति की सिफारिशें

2533. श्री सनत कुमार मंडल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंकों के लिए संशोधित तुलन-पत्र के प्ररूप के संबंध में अमिताभ घोष समिति की सिफारिशों को अस्वीकृत कर दिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ख) घोष समिति की सिफारिशों को कठेक संशोधनों के साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वीकार कर लिया है। तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखे के

फार्मेटों को तदनुसार सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिए 31 मार्च, 1992 को समाप्त वर्ष से लागू कर दिया गया है।

[हिंदी]

बिहार में चाय बागानों का विकास

2534. श्री सूर्य नारायण यादव: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के तराई क्षेत्रों में चाय बागानों का विकास करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये चालू वर्ष के दौरान किन्-किन स्थानों को प्राथमिकता दी जायेगी?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) हालांकि सरकार बिहार में चाय की खेती के तहत क्षेत्र बढ़ाना चाहती है, परन्तु चाय की खेती के लिये क्षेत्र लेने के संबंध में राज्य भूमि सीमा कानूनों से छूट देने का मामला अभी तक बिहार सरकार के विचारधीन है।

[अनुवाद]

चमड़े के सामान का जर्मनी को निर्यात

2535. श्री सुबास चन्द्र नायक: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जर्मनी को किये जाने वाले चमड़े के सामान के निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो किस वर्ष से और गत दो वर्षों की तुलना में वर्ष 1991-92 के दौरान कितनी

वृद्धि

हुई है;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्ष 1992-93 के दौरान जर्मनी को किये जाने वाले चमड़े के सामान के निर्यात में और अधिक वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो इसके लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ङ) लक्ष्य की प्राप्ति के लिये क्या कदम उठाने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) जी हां।

(ख) पिछले कुछ वर्षों में जर्मनी को चमड़ा और चमड़े की वस्तुओं के निर्यात में रुपये के रूप में लगातार वृद्धि हुई है और जो वृद्धि हुई है वह नीचे दर्शाई गई है:

वर्ष	निर्यात (करोड़ रुपये में)
1988-89	253.14
1989-90	356.28
1990-91	630.81
1991-92	700.35

स्रोत: चमड़ा निर्यात परिषद।

(ग) जी, हां।

(घ) चमड़ा निर्यात परिषद् ने वर्ष 1992-93 के लिये जर्मनी को 973 करोड़ रुपये का चमड़ा और चमड़े की वस्तुओं के निर्यात का लक्ष्य रखा है।

(ङ) जर्मनी में विशेषीकृत चमड़ा मेलों में भागीदारी सहित व्यापक बाजार संवर्धन उपायों और भारत की चमड़े से निर्मित वस्तुओं को प्रतियोगी बनाने के लिये उत्पाद विकास प्रयासों से हमारे निर्यात को बढ़ाने में मदद मिली है और इन उपायों को जारी रखने और इनमें तेजी लाने का प्रस्ताव है।

पंजाब और जम्मू तथा कश्मीर में बैंकों का लूट जाना

2536. डा० डी० बेंकटेश्वर राव: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनवरी 1990 से अब तक, जम्मू तथा कश्मीर राज्य में उपद्रवादियों ने बैंकों, बैंकिंग कंपनियों तथा वेतन-पत्रकों से 80 लाख रुपये लूटे हैं;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त अवधि के दौरान जम्मू तथा कश्मीर और पंजाब में उपद्रवादियों ने बैंकों से कुल कितनी घनराशि लूटी है; और

(ग) भविष्य में इस लूट को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कैब का निर्यात

2537. श्री पी० सी० धामस: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष निर्यात किये गये कैब और चालू वर्ष के दौरान किये जाने वाले निर्यात की मात्रा और मूल्य क्या है; और

(ख) कैबों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्रूद्दी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किये गये केकड़ों की मात्रा और मूल्य नीचे दिये गये हैं:

(मात्रा: मी टन)

(मूल्य: लाख रुपये)

	1991-92	1990-91	1989-90
मात्रा	1166	1699	1260
मूल्य	464.33	551.14	333.12

चालू वर्ष के दौरान इस मद का 550 लाख रुपये मूल्य के 1500 मी० टन का निर्यात होने का अनुमान है।

(ख) केकड़ों के निर्यात के लिए कोई विशेष प्रोत्साहन उपलब्ध नहीं है।

खाद्यान्नों की तस्करी

2538. श्री बी० राजरविवर्मा:

श्री राम विलास पासवान:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवंटित किये गये खाद्यान्नों की देश से बाहर तस्करी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान तथा 1992 में अब तक का तत्संबंधी ब्यौर क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) और (ख) प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि उत्तर-पूर्वी राज्यों से बांग्लादेश को अनाज की तस्करी की जा रही है। तथापि, चूंकि तस्करी एक चोरी-छिपे किये जाने वाला धंधा है, इसलिये इस तरह अवैध रूप से बाहर भेजे जाने वाले अनाज की मात्रा तथा उस मात्रा का भी आकलन करना संभव नहीं है, जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में से निकालकर चोरी-छिपे बाहर भेज दिया जाता है।

तथापि, गत 3 कैलेण्डर वर्षों के दौरान उत्तर-पूर्वी राज्यों से बांग्लादेश को अवैध रूप से निर्यात करने की कोशिशों के सिलसिले में सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के तहत पकड़े गये खाद्यान्नों (चावल तथा धान) की मात्रा और उसके मूल्य का ब्यौर नीचे दिया गया है:—

वर्ष	मात्रा (मीट्रिक टन में)	मूल्य (लाख रुपयों में)
1990	21.4	0.83
1991	120.6	3.37
1992 (मई तक)	18.3	0.84

(ग) सीमा सुरक्षा बल सहित तस्करी रोधी कार्य में लगी सभी एजेन्सियां खाद्यान्नों सहित तस्करी की गतिविधियों की रोकथाम के लिये चौकस रहती हैं। तस्करी की गतिविधियों की रोकथाम के लिये आसूचना तंत्र को सुदृढ़ कर दिया जाता है और तस्करी का पता लगाने और उसकी रोकथाम के कार्य में लगी सभी एजेन्सियों के बीच घनिष्ठ तालमेल रखा जाता है।

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा केरल को वित्तीय सहायता

2539. श्री झाङ्गल जॉन अंजलोज: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा केरल को विभिन्न परियोजनाओं के लिये कितनी वित्तीय सहायता दी गई; और

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम किन-किन परियोजनाओं के लिये सहायता देगी? वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क)

(करोड़ रुपये)

वर्ष	वित्तीय सहायता
1990-91	96.42
1991-92	96.42

(ख) चालू वित्तीय वर्ष 1992-93 के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम का अपनी समाजोन्मुखी योजनाओं अर्थात् राज्य सरकार सामाजिक आवास योजनाओं, राज्य विद्युत बोर्ड, राज्य सड़क परिवहन निगम, जल-आपूर्ति एवं मल निकासी संबंधी योजनाओं के तहत केरल राज्य में निवेश करने का प्रस्ताव है।

वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना

2540. कुमारी पुष्पा देवी सिंह: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इन न्यायालयों का गठन किस पद्धति पर किये जाने की संभावना है;

(ग) इन न्यायालयों के मुख्य कार्य क्या होंगे; और

(घ) इन न्यायालयों की स्थापना पर कितनी धनराशि खर्च होगी?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीदि): (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

मानव विकास सूचकांक पर भारत का स्थान

2541. श्री बी० एन० रेड्डी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा आंकलित मानव विकास सूचकांक पर दर्ज 160 देशों में भारत का स्थान 121वां है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का विचार इस संबंध में क्या उपचारक कदम उठाने का है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) जी, हाँ। तथापि मानव विकास रिपोर्ट में

उल्लिखित विचार जरूरी तौर पर यू०एन०डी०पी० उसकी शासी परिषद् और यू०एन०डी०पी० की अन्य सदस्य सरकारों के विचारों को नहीं दर्शाते हैं क्योंकि यह रिपोर्ट एक स्वतंत्र व्यवसायिक दल की रिपोर्ट है।

(ख) मानव विकास सूचकांक की गणना करते समय जिन कारकों को ध्यान में रखा गया है, वे निम्नलिखित हैं:—

(i) दीर्घ आयु (ii) प्रौढ़ साक्षरता (iii) स्कूली आयु के औसत वर्ष और (iv) प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद। स्वतंत्रता के बाद से देश के विभिन्न भागों में उल्लेखनीय सामाजिक-आर्थिक प्रगति के बावजूद पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है क्योंकि हमने स्वतंत्रता के समय बहुत कमजोर आर्थिक-सामाजिक आधार से शुरुआत की है। बढ़ती हुई जनसंख्या की आर्थिक-सामाजिक आवश्यकताओं के लिये अपेक्षित निवेश योग्य अधिशेष भी अपर्याप्त ही रहा है। निवेश योग्य अधिशेष की अपर्याप्तता स्वयं विकास के निम्नस्तर का एक परिणाम है और बढ़ती हुई जनसंख्या वाली विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के सामने यह स्थिति उत्पन्न होती है।

(ग) दीर्घ आयु, प्रौढ़ साक्षरता, स्कूली आयु के औसत वर्षों और प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के संबंध में हमारे निष्पादन में सुधार लाने के लिये आठवीं पंचवर्षीय योजना में कारगर और समन्वित प्रयास किये जाने का प्रस्ताव है।

रक्षा प्रतिष्ठानों में कृषि विकास

2542. डा० कार्तिकेश्वर पात्र: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने रक्षा प्रतिष्ठानों के कृषिगत विकास के लिये विशेष अभियान शुरू किया है;
(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ रक्षा प्रतिष्ठानों के किन-किन क्षेत्रों का चयन किया गया है; और
(ग) इस संबंध में पेश किये गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार): (क) ऐसी कोई नीति नहीं है कि रक्षा मंत्रालय की भूमि का कृषि प्रयोजनों के लिये विकास किया जाये क्योंकि रक्षा भूमि का उपयोग मुख्यतः रक्षा प्रयोजनों के लिये किया जाना होता है। तथापि, रक्षा मंत्रालय की जो भूमि अस्थायी तौर पर फालतू है, उसे अल्पकालिक आधार पर भूतपूर्व सैनिकों, उनकी सहकारी समितियों तथा अन्य पात्र व्यक्तियों को कृषि प्रयोजनों के लिये पट्टे पर दिया जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

विभिन्न देशों में अवरूद्ध निर्यात आय

2543. श्री शरत चन्द्र पटनायक: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) राजनैतिक उथल-पुथल के कारण विभिन्न देशों में निर्यात आय की कितनी राशि रुकी पड़ी है;
(ख) क्या निर्यात आय की प्राप्ति हेतु ई० सी० जी० ने कोई प्रयास किए हैं; और
(ग) यदि हां, तो प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) से (ग) ई० सी० जी० ने मूल्यांकन किया

है कि 31.3.1992 को विभिन्न देशों में लगभग 371 करोड़ रुपए की राशि रुकी पड़ी है। इन देयताओं (निधियों) की प्राप्ति न होने का कारण मुख्यतः संबंधित देशों की आर्थिक समस्याएं हैं। निधियों का प्रत्यावर्तन प्राप्त करने की दृष्टि से ई० सी० जी० सी० सीधे और राजनयिक माध्यमों आदि के जरिए प्रयास कर रहा है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण

2544. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे बबूल आदि जैसे फल विहीन वृक्षों के स्थान पर आम, जामुन, इमली, रोजवुड, सागोन नीम आदि जैसे वृक्ष लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान क्या कार्य किया गया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्ष लगाना सरकार की पिछले कई वर्षों से स्वीकृत नीति है तथा यह एक सत्त क्रियाकलाप है जो मार्ग के साथ जमीन की उपलब्धता जहां वृक्षारोपण किया जा सके, निधियों की पर्याप्तता इत्यादि पर निर्भर करती है। राष्ट्रीय राजमार्गों के एक बड़े भाग पर पहले ही वृक्षारोपण किया जा चुका है।

अधिकांश राज्यों में वृक्षारोपण, वन/बागवानी विभागों के माध्यम से अथवा उनके परामर्श से कराया जाता है। वृक्षों की प्रजाति का निर्णय स्थानीय वर्षा, जलवायु, क्षेत्र, भूमि की किस्म इत्यादि को ध्यान में रख कर किया जाता है। जहां तक संभव हो फलदार वृक्ष लगाने के निदेश दिए गए हैं।

स्वापक औषधों का जब्त किया जाना

2545. प्रो० राम कापसे: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश में विशेषकर मुम्बई में कितनी मात्रा तथा कितने मूल्य के स्वापक औषध पकड़े गए; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश में विशेषकर मुम्बई में इस मामले में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी क्रमशः विवरण-"क" और "ख" पर दी गई है।

विवरण 'क'

वर्ष 1990 तथा 1991 के दौरान भारत तथा विसेबकर बावर्ड में पकड़े गए नशीले पदार्थों की मात्रा तथा मूल्य

क्र. सं०	नशीले पदार्थ का नाम	पकड़े गए नशीले पदार्थों की मात्रा तथा मूल्य											
		1990						1991					
		भारत में		बावर्ड में		भारत में		बावर्ड में		भारत में		बावर्ड में	
मात्रा कि०घ्रा० में	मूल्य रु० में	मात्रा कि०घ्रा० में	मूल्य रु० में	मात्रा कि०घ्रा० में	मूल्य रु० में	मात्रा कि०घ्रा० में	मूल्य रु० में	मात्रा कि०घ्रा० में	मूल्य रु० में	मात्रा कि०घ्रा० में	मूल्य रु० में		
1.	अफीम	2114.000	*—	शून्य	*—	2145.000	*—	160.000	*—				
2.	मारफीन	6.000	—	2.000	—	6.000	—	3.000	—				
3.	हेरोइन	2193.000	—	990.000	—	622.000	—	326.000	—				
4.	गंजा	39090.000	—	40.000	—	52633.000	—	1123.000	—				
5.	इसीरा	6388.000	—	1478.000	—	4413.000	—	1530.000	—				
6.	कोकीन	1.000	—	शून्य	—	0.008	—	शून्य	—				
7.	मैथाक्वालीन	2141.000	—	2119.000	—	4415.000	—	4415.000	—				

* नशीले पदार्थों का मूल्य स्थान-स्थान पर तथा समय-समय पर गुप्त बाजार में बदलता रहता है, अतः सही आंकड़े देना सम्भव नहीं है।

विवरण 'ख'
नशीले पदार्थ संबंधी अपराधों के लिए वर्ष 1990 तथा 1991 के दौरान
गिरफ्तार तथा दोषसिद्ध व्यक्तियों की संख्या

		गिरफ्तार तथा दोषसिद्ध व्यक्तियों की संख्या				टिप्पणी
		1990		1991		
		भारत में	बम्बई में	भारत में	बम्बई में	
गिरफ्तार किए गए	दोषसिद्ध	गिरफ्तार किए गए	दोषसिद्ध	गिरफ्तार किए गए	दोषसिद्ध	
4302	511	194	330	5300	855	425 पिछले वर्षों में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति अगले वर्षों में दोषसिद्ध हो सकते हैं, अतः वर्ष 1990 तथा 1991 में बम्बई में दोषसिद्ध व्यक्तियों की संख्या, उन वर्षों में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या से अधिक है।

दलहन का निर्यात

2546. श्री के० पी० रेड्डय्या यादव: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1991 के दौरान दलहन का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया; और

(ख) इस निर्यात से वर्ष 1990 की तुलना में कितनी अतिरिक्त धनराशि अर्जित की गयी?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) भारत दालों का आयात करता है। अतः सामान्यतया दालों के निर्यात की अनुमति नहीं दी जाती है। तथापि अग्रिम लाइसेंसिंग योजना/पास बुक के तहत या अनुमोदित शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख एकक द्वारा आयातित दालों में से संसाधित दालों की कुछ मात्रा का निर्यात करने की अनुमति दी जाती है। ऐसे निर्यात के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजनाओं का कार्यनिष्पादन

2547. श्री विजय नवल पाटील: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक द्वारा भारत में राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजनाओं को दी गई सहायता का समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो भारी पूंजीनिवेश के बावजूद रेशम उत्पादन परियोजनाओं के खराब कार्यनिष्पादन के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने रेशम उत्पादन परियोजनाओं के कार्यकरण की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति स्थापित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है; और

(ङ) रेशम उत्पादन परियोजनाओं के कार्यनिष्पादन को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाये पए हैं/उठाने का विचार है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) और (ख) जी नहीं। राशि का सही ढंग से इस्तेमाल किया जा रहा है तथा परियोजना की जटिलता के बावजूद इसके क्रियान्वयन की प्रगति कुल मिलाकर संतोषजनक रही है।

(ग) से (ङ) समस्त राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना की समय-समय पर समीक्षा/मानीटरी करने के लिए वस्त्र सचिव की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति का गठन किया गया है। परम्परागत राज्यों में राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना की समीक्षा संबंधित राज्यों की संचालन समितियों द्वारा की जा रही है। इस प्रयोजन के लिए प्रादेशीय राज्यों में जिला स्तर पर मानीटरींग समितियों का गठन किया गया है।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अनुसंधान व विकास परियोजनाओं/कार्यक्रमों की समीक्षा/मानीटरी विख्यात वैज्ञानिक की अध्यक्षता में गठित अखिल भारतीय रेशम उत्पादन अनुसंधान समन्वय समिति (ए०आई०एस०आर०सी०सी०) द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र के लिए ए०आई०एस०आर०सी०सी० के अधीन अनुसंधान सलाहकार समितियों का गठन भी किया गया है। राज्यों के कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा गठित रेशम उत्पादन संचालन समितियां भी संबंधित राज्यों में राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना की प्रगति की समीक्षा कर रही है।

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं/कार्यक्रमों की समीक्षा केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा समय-समय पर होने वाली बैठकों में भी की जाती है।

चाय के लिए पैकिंग सामग्री

2548. श्री विजय कृष्ण हाण्डिक: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चाय की पैकिंग के लिए प्लाईवुड के विकल्प के रूप में नई पैकिंग सामग्री खोज निकालने का है ताकि वनों और वृक्षों की लकड़ी का इस्तेमाल न करना पड़े;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में एक समयबद्ध अनुसंधान कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) चाय की बल्क पैकेजिंग के लिए लकड़ी के विकल्प के रूप में पोलिलाइड पटसन वोरों, मल्टीवाल कागज़ के बोरो जैसे सामान को उपयुक्त पाया गया है और उनका इस्तेमाल हो रहा है।

(ग) और (घ) सी०टी०सी० चाय की पैकेजिंग के लिए उपयुक्त वैकल्पिक बल्क पैकेजिंग प्रणालियों का पता लगाने हेतु इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ पैकेजिंग (आई०आई०पी०), बम्बई ने चाय बोर्ड की ओर से वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 के दौरान एक दो-वर्षीय परियोजना आरंभ की थी। इस इंस्टीट्यूट ने फुटकर बिक्री वाले पैकेटों में चाय की पैकेजिंग के लिए उपयुक्त विकल्प का पता लगाने के उद्देश्य से वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान एक दो-वर्षीय परियोजना चलाई है।

[हिन्दी]

पंजाब सरकार से देय राशि

2549. श्री मोहन सिंह (देवरिया): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्र सरकार से इससे देय 6600 करोड़ रुपये की राशि माफ करने का आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शांता राम पोतदुखे): (क) जी हां।

(ख) असम, जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब जिन वित्तीय असंतुलों का सामना कर रहे हैं उनको जांच करने के लिए अधिकारियों का एक दल गठित किया गया है जिसमें वित्त और गृह मंत्रालयों तथा योजना आयोग के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह निर्णय लिया गया है कि पंजाब को दिए गए विशेष योजना ऋणों (जिनकी वापसी ऋण स्यागन अवधि के समाप्त होने पर 1.7.1992 से शुरू होनी थी) की वसूली को उक्त दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक आस्थगित रखा जाए।

पेंशन संबंधी लंबित मामले

2550. प्रो० प्रेम धूमल: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) मंत्रालय के पास भूतपूर्व सैनिकों के पेंशन संबंधी राज्यवार कुल कितने मामले लंबित हैं;
- (ख) क्या सरकार का विचार इन मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु कदम उठाने का है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है; और
- (घ) सभी लंबित मामलों को कब तक निपटा दिया जाएगा?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (घ) पेंशन को स्वीकृत करने वाले प्राधिकारियों, अर्थात् मुख्य रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन), इलाहाबाद, रक्षा लेखा नियंत्रक (नौसेना), बम्बई और रक्षा लेखा नियंत्रक (वायुसेना), नई दिल्ली द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के पेंशन के दावों के संबंध में राज्य-वार ब्यौर नहीं रखे जाते।

रक्षा मंत्रालय में ऐसे कोई मामले लंबित नहीं हैं। पेंशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारियों के पास 30.6.92 की स्थिति के अनुसार अंतिम निर्णय के लिए लंबित पड़े पेंशन दावों की संख्या नीचे दिए अनुसार है:—

	सेवानिवृत्त/सेवा पेंशन दावे	निशक्तता पेंशन दावे
(1) सेना	253	
(2) वायुसेना	78	1680
(3) नौसेना	—	
कुल	331	1680
कुल योग:	2011	

सेवानिवृत्ति/सेवा पेंशन के लंबित पड़े 331 मामलों में से 249 मामलों में पेंशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारियों द्वारा आदेश जारी किए जा रहे हैं। जहां तक शेष 82 मामलों का संबंध है, उन मामलों में संबंधित सेना मुख्यालय/अभिलेख कार्यालय से कागजात/सूचना आदि प्राप्त न होने के कारण अंतिम आदेश जारी नहीं किए जा सके हैं।

निशक्तता पेंशन के 1680 लंबित मामलों में से, 423 मामलों में आदेश जारी किए जाने वाले हैं और शेष 1257 मामलों में रिकार्ड कार्यालय/अस्पताल आदि से सूचना/दस्तावेज न मिलने के कारण अंतिम आदेश जारी करने में विलम्ब हो रहा है।

पेंशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारियों द्वारा पेंशन दावा रजिस्ट्रियों के माध्यम से पेंशन के लंबित पड़े मामलों के निपटान पर पूरी निगरानी रखी जाती है।

[अनुवाद]

भारतीय श्रम कानून में परिवर्तन

2551. श्री जे० चोह्ला राव: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी पूंजी निवेशकों, विशेषकर जापान ने भारत में अपने धन के त्वरित निवेश हेतु भारतीय श्रम कानूनों में कुछ परिवर्तन करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है; और

(ग) इस संबंध में केर सरकार की परतिक्रिया क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) से (ग) उद्योगपतियों के एक जापानी आर्थिक मिशन ने भारत का दौरा किया था और अपने दौर के दौरान उन्होंने भारत में जापानी निवेश अवसरों में सुधार लाने के लिए अनेक सुझाव दिए जिनमें श्रम सम्बद्ध कानून (नियोजक और कर्मचारियों के हितों में सुसंतुलित नीतियों का प्रारम्भ) की समीक्षा सम्मिलित थी। उन्हें यह बताया गया कि भारत में कर्मचारियों के हितों की रक्षा और स्वच्छ नियोजक-कर्मचारियों के संबंधों के संबर्द्धन की दृष्टि से समय-समय पर श्रम सम्बद्ध कानूनों की समीक्षा की जाती है।

शेयर जब्त करना

2552. श्री हरि किशोर सिंह:

डा० कार्तिकेश्वर पात्र:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयकर अधिकारियों ने धारा 132(5) के अन्तर्गत कौन-कौन सी कम्पनियों के शेयर जब्त किए हैं और चालू वर्ष में विभिन्न अधिकारियों ने अब तक किन-किन दलालों/छोटे दलालों के शेयर/सम्पत्ति जब्त की है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्टॉक बाजार के लेन-देन पर ऐसी कार्रवाई के गंभीर परिणाम होंगे जिससे कुछ प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों के बन्द होने की नौबत भी आ सकती है;

(ग) सरकार ने जब्त किए गए इन शेयरों के लेन-देन की औपचारिकताएं घोषित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) स्टॉक बाजारों में विश्वास बहाल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है/करने का विचार किया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) विशेष न्यायालय (ट्रायल आ फ आ फेन्सेज रिस्ट्रिग टू ट्रंज़ैक्शन्स इन सिक्योरिटिज) अध्यादेश, 1992 के अन्तर्गत नियुक्त किए गए अभिरक्षक ने संलग्न विवरण 'क' पर सूचीबद्ध 39 व्यक्तियों के बारे में दो अधिसूचनाएं दिनांक 8-6-1992 तथा 13-6-1992 को तथा दो अधिसूचनाएं दिनांक 2-7-1992 को जारी की थीं और इसलिए उक्त अध्यादेश की धारा 3(3) के तहत इन 39 व्यक्तियों की सभी चल तथा अचल सम्पत्तियों की तत्काल कुर्की कर ली गई थी। भविष्य में जारी होने की संप्रवना वाली कर-मांगों के संबंध में राजस्व के हितों की रक्षा के प्रयोजनार्थ कर-निर्धारण अधिकारियों द्वारा संलग्न विवरण 'ख' पर सूचीबद्ध 25 व्यक्तियों के शेयरों/सम्पत्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम की

धारा 281-बी के अन्तर्गत अनंतिम कुर्की भी कर ली गई है। धारा 132(5) के अन्तर्गत शेयरों की कुर्की करने की व्यवस्था नहीं है।

(ख) से (घ) यह मामला इस समय न्यायाधीन है तथा बम्बई, कलकत्ता एवं दिल्ली के स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा दायर की गई विविध याचिकाओं के आधार पर माननीय न्यायाधीश एस०एन खरियावा के विशेष न्यायालय द्वारा इस पर सुनवाई की जा रही है।

विवरण-क

1. मै० हर्षद एस० मेहता, प्रोप्राइटरी कंसर्न
2. मै० अश्विन एस० मेहता, प्रोप्राइटरी कंसर्न
3. मै० जे०एच० मेहता, प्रोप्राइटरी कंसर्न
4. श्री हर्षद एस० मेहता
5. श्री अश्विन एस० मेहता
6. श्री हितेश एस० मेहता
7. श्री सुधीर एस० मेहता
8. श्रीमती ज्योति एच० मेहता
9. श्रीमती दीपिका ए० मेहता
10. श्रीमती प्रमिला एच० मेहता
11. हर्षद एस० मेहता, हि०अ०प०
12. अश्विन एस० मेहता, हि०अ०प०
13. हितेश एस० मेहता, हि०अ०प०
14. मै० सनराइज एन्टरप्राइजेज
15. ग्रोमोर रिसर्च एंड एसेट्स मैनेजमेंट लि०
16. ग्रोमोर लीजिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्रा० लि०
17. ग्रोमोर एक्सपोर्ट्स प्रा० लि०
18. आतुर होल्डिंग्स प्रा० लि०
19. हर्ष एस्टेट्स प्रा० लि०
20. कास्वेड होल्डिंग प्रा० लि०
21. ओरियन ट्रेवल्स प्रा० लि०
22. फोरच्यून होल्डिंग्स प्रा० लि०
23. ट्रेजर होल्डिंग्स प्रा० लि०
24. वेलवेट होल्डिंग्स प्रा० लि०
25. एमीनेट होल्डिंग प्रा० लि०
26. पल्लवो होल्डिंग प्रा० लि०
27. जेस्ट होल्डिंग प्रा० लि०
28. टोपास होल्डिंग प्रा० लि०
29. डिवाइन होल्डिंग प्रा० लि०
30. श्री अभय धर्म सिंह नरोत्तम

31. श्री हितेन प्रसन्न दलाल
32. श्री सी० एल० खेमानी
33. श्री ए० एन० बावदेकर
34. श्री आर० सीतारामन
35. श्री भूपेन दलाल
36. श्री जे० पी० गान्धी
37. श्री टी० बी० रुइया
38. फेयरप्रोथ फाइनेंसियल सर्विसेज लि०
39. श्री आर० गणेश

विवरण-रुख

1. श्री भूपेन दलाल
2. श्री मिलन बी० दलाल
3. सिफ्को प्रोपरटीज लि०
4. चम्पक लाल इन्वे० एंड फाइनेंसियल कन्सलटेसी लि०
5. सिफ्को फाइनेंस लि०
6. एस० रामदास एंड कम्पनी
7. आरकेडिया इन्वे० कं० लि०
8. ओशियनिक इन्वे० लि०
9. जय कृष्णा (प्रा०) लि०
10. अपूर्व इन्वे० लि०
11. एशियन होल्डिंग्स (प्रा०) लि०
12. फूड्स एंड इंस लि०
13. मिलन इन्वे० लि०
14. अपात्गामेटेड इलैक्ट्रीसिटी कं० लि०
15. ट्रापिकल इन्वे० कं० लि०
16. सिफ्को स्टॉक ब्रोकर्स
17. श्री हर्षद एस० मेहता
18. श्रीमती ज्योति एच० मेहता
19. श्री अश्विन एस० मेहता
20. श्री सुधीर एस० मेहता
21. श्रीमती दीपिका ए० मेहता
22. सुश्री प्रतिमा मेहता
23. श्रीमती नरसीला मेहता
24. श्री हितेश एस० मेहता
25. केसुडे इन्वे० एंड ट्रेडिंग कम्पनी (प्रा०) लि०

महाराष्ट्र की एकाधिकार रुई क्रय योजना

2553. श्री रामचन्द्र घंगारे:

श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र की एकाधिकार रुई क्रय योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है और यदि हां, तो यह स्वीकृति कब तक के लिए दी गई थी;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को महाराष्ट्र सरकार तथा कपास उत्पादकों से यह अनुरोध प्राप्त हुआ है कि अनुदान कम से कम पांच वर्षों के लिए दिया जाये; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार ने 1 जुलाई, 1990 से दस वर्ष की अवधि के लिए राज्य में कपास की एकाधिकार खरीद योजना को बढ़ाने का अनुरोध किया था। सरकार ने मौजूदा शर्तों पर इस योजना को 1 जुलाई, 1990 से तीन वर्ष की अवधि तक बढ़ाने की अनुमति दी है।

रबड़ में आत्मनिर्भरता

2554. श्री रवि मल्लू: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रबड़ बोर्ड, रबड़ के उत्पादन में आत्मनिर्भरता कब तक प्राप्त कर लेगा;

(ख) क्या रबड़ बोर्ड ने इसके लिए विश्व बैंक से सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) आठवीं पंचवर्षीय योजनावाधि के अन्त तक प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने रबड़ बोर्ड के जिन विभिन्न क्रियाकलापों को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता तथा अन्य सहायता देने के लिए विश्व बैंक ग्रुप से सहायता मांगी है, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:—

- (1) रबड़ उपजकर्ताओं को विभिन्न सहायता;
- (2) संसाधन-फैक्टरियां स्थापित करना और अनुसंधान एवं प्रशिक्षण सुविधाओं में सुधार करना;
- (3) केरल एवं तमिलनाडु के परम्परागत क्षेत्रों में 40,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में पुनरोपण;
- (4) 30,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में नया रबड़ रोपण (केरल और तमिलनाडु के परम्परागत क्षेत्रों में 23,000 हेक्टेयर, त्रिपुरा में 5,000 हेक्टेयर और अन्य चुनीदा गैर-परम्परागत क्षेत्रों में 2,000 हेक्टेयर)।
- (5) 60,000 हेक्टेयर की छोटी जोतों में उत्पादकता बढ़ाना।
- (6) लैटेक्स फैक्टरियों, क्रम्ब रबड़ फैक्टरियों आदि जैसी आधुनिक रबड़ संसाधन फैक्टरियों का वित्त-पोषण।

- (7) रबड़ बोर्ड की बुनियादी संरचना संबंधी सुविधाओं जैसे अनुसंधान, प्रशिक्षण, विस्तार सेवाओं आदि को सुदृढ़ बनाना।
- (8) रबड़ के नए पौधे लगाने और पुनरोपण कार्यक्रमों में महिलाओं और अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को शामिल करने के अलावा इस परियोजना में त्रिपुरा में मधुमक्खी पालन तथा रेशम के कीड़ों का पालन, बीच-बीच में होने वाली फसलों की खेती, मसाले एवं जड़ी-बूटी की खेती आदि जैसे कई आय देने वाले क्रियाकलाप बढ़ाने में सायता दी जायेगी।

66.4 मिलियन (92 मिलियन अमरीकी डालर के बराबर) विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) के अन्तर्गामी विकास संघ (आईडीए) ऋण की सहायता राशि देने के लिए समझौता हुआ है।

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा विमानों की सर्विसिंग

2555. श्री जी० माडेगौडः क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान और इस वर्ष में मई के अंत तक हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा कुल कितने भारतीय और विदेशी विमानों की ओवरहालिंग की गई; और

(ख) इन विमानों की सर्विसिंग और ओवरहालिंग से हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड ने कुल कितनी धनराशि अर्जित की?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार): (क) ब्यौरे प्रकट करना लोक हित में नहीं है।

(ख):	वर्ष	करोड़ रुपये में
	1990-91	80.82
	1991-92	108.67

राजसहायता के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय भुद्राकोष/विश्व बैंक के निर्देश

2556. श्री अजय मुखोपाध्यायः

श्री दिलीप भाई संघानीः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय भुद्रा कोष और विश्व बैंक ने कुछ आवश्यक वस्तुओं पर से राजसहायता हटाने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार इन वस्तुओं पर से राजसहायता हटाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा क्रियान्वित राजकोषीय सुधार एवं समेकन कार्यक्रम के लिए आर्थिक सहायता को युक्तिसंगत बनाना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, निर्यात के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता

बदलती परिस्थितियों के कारण बंद कर दी गई है। एक संसदीय समिति इस समय उर्वरक मूल्यों और आर्थिक सहायता के ढांचे की जांच कर रही है।

रुई निर्यात नीति

2557. श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि संबंधी स्थाई सलाहकार समिति में कुछ समय पहले यह सिफारिश की थी कि रुई का निर्यात 5 लाख गांठ प्रति वर्ष से कम नहीं होना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) और (ख) कृषि मंत्रालय की कृषि संबंधी स्थाई सलाहकार समिति (एस०ए०सी०) ने जुलाई, 1990 में यह सिफारिश की थी कि प्रत्येक वर्ष कपास की 10 लाख गांठों का न्यूनतम निर्यात कोटा रिलीज किया जाये।

(ग) सरकार ने इस सिफारिशों पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

मुद्रास्फीति-दर

2558. श्री चन्द्रजीत यादव: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले वर्ष सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रास्फीति-दर को किस सीमा तक कम करने का वचन दिया था और मुद्रास्फीति-दर वास्तव में कितनी कम हुई है; और

(ख) भारत में चालू वर्ष के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को मुद्रास्फीति-दर को किस सीमा तक कम करने का वचन दिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) और (ख) जैसा कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को सूचित किया गया है, पिछले वर्ष और चालू वर्ष के लिए निर्धारित मुद्रास्फीति की दरों सहित पिछले वर्ष की वार्षिक दर नीचे दी गई है:—

बोका मूय सूचकांक के अनुसार मुद्रास्फीति की दरें

(अवधि-समाप्ति)

(आधार: 1981-82 = 100)

वर्ष	प्रारंभिक कार्यक्रम	वास्तविक
1991-92	9.0	13.6
1992-93	8.0	—

[हिन्दी]

मकान खरीदने के लिए जीवन बीमा निगम से ऋण

2559. श्रीमती शीला गौतम:

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम फ्लैट/मकान खरीदने के लिए ऋण उपलब्ध कराता है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय जीवन बीमा निगम की उक्त सुविधा दिल्ली में दी जा रही है ताकि दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों तथा निजी फ्लैटों की खरीद की जा सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जीवन बीमा निगम की एक सहायक कम्पनी अर्थात् जीवन बीमा निगम आवास वित्त लिमिटेड अपनी दो योजनाओं अर्थात् जीवन निवास और जीवन कुटीर के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण और निजी भवन निर्माताओं से फ्लैट खरीदने के लिए ऋण प्रदान करती है। मकान के निर्माण या विस्तारण के लिए भी ऋण उपलब्ध है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कुचलि बाड़ी के विकास के लिए धनराशि

2560. श्री पवन कुमार बंसल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के कुचलि बाड़ी ब्लाक के विकास के लिए, जिसमें तीन बीघा गलियारा क्षेत्र आता है जहां बंगलादेश-वासियों को आने जाने का अधिकार दिया गया है, कतिपय धनराशि जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त धनराशि से शुरू किए गए कार्यों में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे): (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को तीन बीघा गलियारा क्षेत्र में विकासात्मक कार्य करने के लिए 3.14 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की है। राज्य सरकार को 1991-92 के दौरान 2 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं तथा शेष 1.14 करोड़ रुपए 1992-93 में रिलीज किए जाएंगे।

(ग) एक विवरण पत्र संलग्न है।

विवरण

3.14 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से शुरू की गई विकासात्मक योजनाओं का ब्यौरा तथा उपर्युक्त निधि से शुरू किए गए कार्यों को पूरा करने में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा यथासूचित प्रगति को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

विकास योजनाएं	निधियों का आबंटन (लाख रु० में)	पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा योजनाओं की यथासूचित प्रगति
1. सती नदी पर पक्का पुल बनाना तथा कुछ सड़कों का निर्माण	100.00	सती नदी पर पक्का पुल बनाने के बारे में निर्माण कार्य-आदेश जारी कर दिया गया है।
2. कुछ जिला परिषद सड़कों का निर्माण तथा फ्रीडर सड़क पर लकड़ी के पुल की जगह पक्का पुल बनाना	70.00	जिला परिषद ने काम शुरू कर दिया है।
3. तिस्ता नदी पर कुचलीबाड़ी पुरते को मजबूत करना	22.00	यह कार्य लगभग 22 लाख रु० की लागत से पूरा कर दिया गया है।
4. कुचलीबाड़ी में छः बिस्तरों वाला सांस्वांके० का निर्माण	40.00	निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है।
5. पुलिस थाना, रिहायशी मकान तथा संचार सुविधाओं का निर्माण	60.00	भूमि अधिग्रहण कार्य शुरू हो गया है। कार्य शीघ्र ही शुरू हो जाने की आशा है।
6. पूर्व-पश्चिम में सड़क का निर्माण, ड्राप गेट्स तथा गलियारों में बाड़ लगाना	161.81	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने काम पूरा कर दिया है।
7. रोशनी की व्यवस्था तथा लोक प्रसार प्रणाली	05.01	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने कार्य पूरा कर दिया है।
जोड़	313.82	
अर्थात्	314.00	

[हिन्दी]

रामगढ़ छावनी क्षेत्र में जलपूर्ति योजना

2561. श्री धुवनेश्वर प्रसाद मेहता: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रामगढ़ छावनी क्षेत्र के लिए जल सप्लाई योजना वित्तीय अभाव के कारण काफी लम्बे समय से अधूरी पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो क्या छावनी बोर्ड ने अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए निश्चित धनराशि की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार का विचार धनराशि को कब तक मंजूर करने का है?

रक्षा मंत्री (श्री झरद पवार): (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

रामगढ़ छवनी के वार्ड संख्या 2 से 5 में जल की आपूर्ति में सुधार लाने के लिए सरकार ने 69.66 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर जल आपूर्ति की एक योजना के लिए स्वीकृति प्रदान की थी और तदनुसार छवनी बोर्ड को विशेष अनुदान सहायता के रूप में 69.66 लाख रुपये उपलब्ध कराये गये थे। इस योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके बाद छवनी बोर्ड ने 148.66 लाख रुपये की एक संशोधित योजना प्रस्तुत की है ताकि कुछ और क्षेत्रों की जल आपूर्ति में सुधार लाया जा सके और उन्होंने इसके लिए 79 लाख रुपये की अतिरिक्त अनुदान सहायता के लिए अनुरोध किया है। वित्तीय कठिनाइयों के कारण अपेक्षित राशि उपलब्ध कराना संभव नहीं हो पाया है।

हथकरघा क्षेत्र हेतु आरक्षित मदें

2562. डा० महादीपक सिंह शाक्य:

श्री नीतीश कुमार:

क्या बस्म मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 मई, 1992 के "इकनामिक टाइम्स" में "सेन्टर अर्जित टु रिजर्व 22 आइटम्स फर हैडलूम विवर्ज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो आरक्षित किए जाने वाली प्रस्तावित मदों का ब्यौर क्या है;

(ग) क्या अखिल भारतीय बुनकर सम्मेलन ने अपनी मांग में सरकार से 22 किस्मों के कपड़ों को केवल हथकरघा क्षेत्र के लिए आरक्षित करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

बस्म मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) जी हां।

(ख) हथकरघा क्षेत्र के लिए आरक्षित 22 मदों की सूची परिशिष्ट "क" में संलग्न है।

(ग) जी हां,

(घ) अखिल भारतीय बुनकर संघ ने सरकार से अनुरोध किया है कि हथकरघा (उत्पादन के लिए आरक्षित मद) अधिनियम 1985 और इसके अंतर्गत जारी आदेशों जिसमें विवरण "क" में दर्शाये गये 22 मदों को अनन्य रूप से हथकरघों पर उत्पादन के लिए आरक्षित किया गया है, के संचालन के लिए जारी स्थगन आदेशों को समाप्त करवाया जाये।

(ङ) एक नीति के अनुसार सरकार हथकरघों पर उत्पादन के लिए आरक्षण हेतु वचनबद्ध है और उच्चतम यायालय में लंबित मामले पर शीघ्र सुनवाई करवाने और निर्णय लेने के लिए सभी संभव प्रयत्न कर रही है।

विवरण

क्र० सं०	मद	हथकरघा क्षेत्र में आरक्षित मदों की किस्में
1.	साड़ी	वे साड़ियां जिनमें बाँडर अथवा पल्लू बुना जाता है और साड़ी में कहीं भी अतिरिक्त ताने अथवा अतिरिक्त बाने का प्रयोग किया गया हो (100% सिंथेटिक फाइबर से तैयार की गई हैं साड़ियां तथा जिन साड़ियों में 45% (भार में) से अधिक मानव निर्मित फाइबर का प्रयोग किया गया हो वे इसमें शामिल नहीं होंगी।
2.	कोट्टा डोरिया साड़ी	वे साड़ियां जो सूती अथवा सूती प्रधानता के साथ-साथ किसी अन्य रेशे के विश्रण से तैयार की जाती हैं और जिनमें घारीदार अथवा चारखानों के नमूने में डोरी का रूप दिया जाता हो।
3.	बांधन और रंजित साड़ी तथा रंजित सामान	सभी प्रकार की बांधन और रंजित साड़ी तथा रंजित सामान।
4.	घोती	ऐसी घोटियां जिनमें बुनाई में बाँडर हो और बाँडर में अधिक ताने का प्रयोग किया गया हो (100% सिंथेटिक फाइबर से तैयार की गई साड़ियां तथा जिन साड़ियों में 45% (भारत में) से अधिक मानव निर्मित फाइबर का प्रयोग किया गया हो वे इसमें शामिल नहीं होंगी।
5.	गमछा और अंगवस्त्र	(क) केवल सूती गमछे जो बुनाई में तैयार किये जाते हैं। (ख) सादी बुनाई में किसी भी फाइबर से (स्पन रेशम को छोड़कर) तैयार किया गया अंगवस्त्र जिसमें बाँडर हो और बाँडर में अतिरिक्त ताने का प्रयोग हो।
6.	लुंगी	सादी बुनाई में चारखानों के डिज़ाइन वाली लुंगियां जिनमें स्पन सिल्क को छोड़कर किसी भी फाइबर का प्रयोग किया गया हो।
7.	कमीज का कपड़ा	केवल 100% सूती चारखानों के डिज़ाइन का, कमीज का कपड़ा।
8.	क्रेप वस्त्र	अच्छी तरह ऐंठे सूत के प्रयोग से केवल 100% सूती क्रेप वस्त्र।
9.	तौलिए	सूती अथवा सूत से मिश्रित घागे (टेरी टॉवल को छोड़कर) के प्रयोग से तैयार किए गए तौलिए जिनमें बाँडर अथवा शीर्ष हो।

क्र० सं०	मद	हथकरघा क्षेत्र में आरक्षित मदों की किस्में
10.	(क) खेस	डबल क्लाथ बुनाई में तैयार किया गया ताने में 2/17 एस से 2/22 एस और बाने में 8 एस से 12 एस के धागे के प्रयोग से सूती अथवा कृत्रिम रेशम खेस।
	(ख) पलंग की चादर	सूती अथवा कृत्रिम रेशम की पलंग की चादरें जिनमें रंगीन सूत से बॉर्डर अथवा शीर्ष (हैडिंग) तैयार किया गया हो।
	(ग) बैड कवर	सूती अथवा रेशम के बैड कवर जिन में सजावटी अथवा रंगीन सूत से बॉर्डर अथवा शीर्ष (हैडिंग) तैयार किया गया हो।
	(घ) पलंग पोश	सूती अथवा कृत्रिम रेशम के पलंग पोश जिनमें उमपी हुई आकृतियों में बुने हुए बॉर्डर अथवा शीर्ष हों।
	(ङ) साज-सज्जा का सामान	दोहरे कपड़े की बुनाई अथवा पीक बुनाई से तैयार किया गया सूती अथवा कृत्रिम रेशम साज-सज्जा का सामान (दीवार दरी सहित)।
11.	टेबल क्लाथ, टेबल मैट और नैपकिन्स	सूती अथवा कृत्रिम रेशम से तैयार की गईं मदें जिनमें चारों ओर बॉर्डर बुना जाता है।
12.	डस्टर और बस्ता	सादे अथवा टुइल रूप से बुने हुए सूती-डस्टर और बस्ते जिनमें मोटे धागे (10 एस काउंट से अधिक नहीं) का प्रयोग किया गया हो।
13.	चादर	सूती अथवा मिश्रित धागे के प्रयोग से चारखानों अथवा स्ट्रैप नमूने में तैयार की गई चादरें।
14.	जामाकाल दरी अथवा झूरेट	सूती अथवा कृत्रिम रेशम अथवा ऊनी धागे के मिश्रण से ताने और बाने में 4 एस से 12 एस की रेंज के मोटे काउंट के प्रयोग से तैयार किया गया माने रंग में तैयार की गई दरी व झूरेट।
15.	बक़्रम कपड़ा	ताने और बाने में 8 एस से 12 एस के काउंट के सूती ऊनी जूट अथवा इनके मिश्रण धागे से तैयार किया गया बक़्रम कपड़ा।
16.	मशरू क्लाथ	ताने में रेशमी अथवा कृत्रिम रेशम और बाने में सूती धागे के प्रयोग से रंगीन स्ट्रिपो वाला साटिन बुनाई में तैयार किया गया मशरू कपड़ा।

क्र० सं०	प्रश्न	हथकरघा क्षेत्र में आरक्षित मर्दों की किस्में
17.	लौ रीड पिड क्लाँथ	<p>(1) सूती कपड़ा जिसके ताने व बाने में 20 एस काउंट के धागे का प्रयोग किया गया हो और रीड व पिक क्रमशः 36 व 32 से कम हो।</p> <p>(2) सूती कपड़ा जिसमें ताने व बाने में 22 एस से 40 एस के काउंट से अधिक का सूत प्रयोग किया गया हो और रीड व पिक क्रमशः 44 और 40 से कम हो।</p> <p>(3) सूती कपड़ा जिसमें ताने व बाने में 40 एस के काउंट से अधिक का सूत प्रयोग किया गया हो और रीड व पिक क्रमशः 44 और 40 से कम हो।</p> <p>नोट: इस दिशा में इनके लिए कुछ भी लागू नहीं होगा:—</p> <p>(क) धोती और साड़ी</p> <p>(ख) सुसीज</p> <p>(ग) मच्छरदानी का कपड़ा</p> <p>(घ) लंबा कपड़ा</p> <p>(ङ) जालीदार कपड़ा</p> <p>(च) रंजित और छपा हुआ कपड़ा और</p> <p>(छ) कोटिड वस्त्र।</p>
18.	रेशम	<p>(1) सभी रेशमी साड़ियां जिनमें बार्डर व पल्लू बुना हुआ हो और 25% से अधिक शुद्ध रेशम (भार में) के मिश्रण का प्रयोग किया गया हो इनमें जां रजट, शिफॉन और क्रेप साड़ियां शामिल नहीं हैं।</p> <p>(2) सभी रेशमी धोतियां जिनमें बार्डर व पल्लू बुना हुआ हो और 25% से अधिक शुद्ध रेशम (भार में) के मिश्रण का प्रयोग किया गया हो।</p>
19.	कंबल अथवा कम्बली	औसत 34 माईक्रेन की ऊन और परिष्कृत की गई मोटी ऊन जिसका वजन 300-450 ग्राम वर्ग मीटर है के प्रयोग से तैयार किया गया कंबल जिसकी रेशोदार सतह हो और माइलिंग व रेशिंग द्वारा तैयार किया गया हो (इसमें शाँडी ऊनी यार्न से कंबल शामिल नहीं हैं)।

क्र० सं०	मद्द	हथकरषा क्षेत्र में आरक्षित मर्दों की किस्में
20.	बैरक कंबल	औसत 34 माईकोन और उसमें मोटे ऊनी प्राकृतिक सफेद/काली ऊन धागे से बने माईलिंग और रंजिंग द्वारा तैयार किए गए रेशेदार सतह वाले बैरक कंबल (इसमें शाँड़ी ऊनी यार्न से बने कंबल शामिल नहीं हैं)
21.	शाँल, लोई, मफूलर, पंखी आदि	केवल ऊनी धागे अन्य किसी रेशे के मिश्रण से डिजाइन में तैयार किये जाने वाली सभी इस प्रकार की मर्दें।
22.	ऊनी ट्खीड़	100% शुद्ध ऊनी धागे से टुइल बुनाई में तैयार किया गया ऊनी कपड़ा जो चारखाने अथवा स्ट्रिप डिजाइन में तैयार किया गया हो और ताने और बाने में 7 एनएम से 9 एनएम कार्डट के धागे का प्रयोग किया गया हो।

[अनुवाद]

पटसन पैकिंग का उपयोग

2563. प्रो० मालिनी भट्टाचार्य:
डा० असीम बाला:
श्री जायनल अबेदिन:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पटसन पैकिंग के वैकल्पिक पदार्थों के स्थान पर कुछ उद्योगों के लिए पटसन पैकिंग के प्रयोग को अनिवार्य बना दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है;

(ग) इस प्रयोजन के लिए कुल कितनी मात्रा में पटसन पैकिंग की आवश्यकता पड़ेगी; और

(घ) उद्योगों द्वारा इस समय वास्तव में कितनी मात्रा में पटसन पैकिंग का प्रयोग किया जा रहा है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गह्लोत): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पैकेजिंग के लिए जरूरी पटसन की मात्रा पैक की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन पर निर्भर करती है।

(घ) वर्ष 1991-92 के दौरान खाद्यान्न, चीनी उर्वरक तथा सीमेंट की पैकिंग के लिए 6.99 ₹. पटसन की सामग्री के इस्तेमाल किए जाने का अनुमान है।

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रम

2564. श्री निर्मल कान्ति घटर्जी:

श्री तरित घरण तोपदार:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के लम्बे समय से रुग्ण 47 उपक्रमों को बन्द करने का है जैसा कि 19 मई, 1992 के 'बिजिनेस स्टैंडर्ड' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में परस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) से (ग) चूंकि सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक कंपनियां भी अब रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत आती हैं, अतः अब सरकारी क्षेत्र की रुग्ण औद्योगिक कंपनियों को भी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी०आई०एफ०आर०) के पास संदर्भ भेजना पड़ेगा। लम्बे असें से रुग्ण केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 47 उपक्रमों को बन्द करने का कोई पृथक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सड़क निधि की सहायता से राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत

2565. श्री राम टहल चौधरी:

मोहम्मद अली अशरफ फातमी:

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल:

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि से आवंटित धनराशि से राज्य-वार किन-किन राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत/निर्माण किया गया; और

(ख) उपरोक्त निधि से आवंटित धनराशि से वर्ष 1992-93 के दौरान किये जाने वाले निर्माण कर्मों का ब्यौरा क्या है और उस पर राज्य-वार कितनी धनराशि व्यय होगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) संसद द्वारा 13.5.1988 को पारित संशोधित संकल्प के अनुसार केन्द्रीय सड़क निधि में अभी वृद्धि नहीं हुई है जिसमें निधि को प्राप्त होने वाली राशि में से 35^{1/2}% धन राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए इस्तेमाल किए जाने का प्रावधान है। इसलिए गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और मरम्मत के लिए किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को निधि में से कोई राशि आवंटित नहीं की जा सकी।

(ख) केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत मंजूर किए जाने वाले प्रस्ताव तथा 1992-93 के दौरान उन पर होने वाला संचालित व्यय, अन्य बातों के साथ-साथ निधि में वास्तविक वृद्धि प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए उपलब्ध शेष मुक्त धनराशि तथा राज्य सरकारों द्वारा अनुशासित प्रस्तावों पर निर्भर करेगा।

भारत—बांग्लादेश सीमा पर तस्करी की वारदातें

2566. श्री साराचंद खण्डेलवाल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या भारत बांग्लादेश सीमा पर गत कुछ महीनों से तस्करी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं; (ख) यदि हां, तो इस प्रकार की तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है;

(ग) गत तीन महीनों के दौरान भारत बांग्लादेश सीमा पर मारे गये छापों/जम्त किये गये तस्करी सामान का बयौर क्या है; और

(घ) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) और (ख) प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि भारत-बांग्लादेश सीमा तस्करी के लिए बराबर आकर्षण का क्षेत्र बनी हुई है। तस्करी की गतिविधियों की रोकथाम के लिए तस्करीरोधी एजेन्सियां चौकस रहती हैं। तस्करी पर निगरानी रखने के लिए आसूचना तंत्र को सुदृढ़ कर दिया जाता है और तस्करी का पता लगाने और उसकी रोकथाम में लगी सभी एजेन्सियों के बीच घनिष्ठ तालमेल रखा जाता है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का निर्यात

2567. श्री सतदेव सिंह: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है; और

(ग) इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय में उय मंत्री (श्री सलमान खुर्रिद): (क) जी, हां।

(ख) इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा निर्धारित निर्यात लक्ष्य के ब्यौर नीचे दिए गए हैं:-

(करोड़ रुपए)

वर्ष	निर्यात लक्ष्य
1992-93	1550
1993-94	2200
1994-95	3200
1995-96	4600
1996-97	6500
योग: 18050	

(ग) लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित उपायों में अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भारतीय उद्योगों की भागीदारी, नए क्षेत्रों, विशेषकर सभ्य मुद्रा क्षेत्र के देशों में बाजार सर्वेक्षण करना, सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए आंकड़ों के बारे में तेजी से सूचना भेजने की सुविधाएं बढ़ाना आदि शामिल है।

[अनुवाद]

ट्रेडिंग (गाढ़ निकालने के कार्य) कार्यों के लिए प्रशिक्षण संस्थान

2568. श्री अनन्तराव देशमुख: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ट्रेडिंग कार्यों के लिए प्रशिक्षण देने हेतु प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) और (ख) ट्रेडिंग तकनीक के लिए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना करना इच्छे-इच्छे द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रम के अधीन चुनी गई स्कीमों में से एक है।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अभी तैयार की जानी है।

पटसन मिलें

2569. श्री जितेन्द्र नाथ दास: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार पटसन मिलों का ब्यौर क्या है;

(ख) उनमें से राज्य-वार कितनी मिलें बन्द हो गई हैं;

(ग) इन मिलों के बन्द होने के मिल-वार कारण क्या हैं;

(घ) क्या सरकार के पास इन मिलों को पुनः चालू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) और (ख) 15.7.1992 की स्थिति के अनुसार पटसन मिलों और बन्द पड़ी पटसन मिलों के राज्य-वार ब्यौर निम्नोक्त अनुसार हैं:

राज्य का नाम	मिलों की संख्या	बन्द बड़ी मिलों की संख्या
पं बंगाल	59	7
आन्ध्र प्रदेश	4	2
बिहार	3	1
उत्तर प्रदेश	3	1
मध्य प्रदेश	1	—
उड़ीसा	1	—
असम	1	—
त्रिपुरा	1	1

(ग) इन मिलों की बन्द होने के कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं: वित्तीय/द्रवता संकट तथा उससे उत्पन्न ऋणिक असंतोष।

(घ और ङ) सरकार ने इन मिलों का पुनरुद्धार करने के लिए अनेक उपाय किए हैं जिनमें शामिल हैं: पटसन आधुनिकीकरण निधि का सृजन, विशेष पटसन विकास निधि की स्थापना, खाद्यान्न, चीनी, सीमेंट और

उर्वरक के लिए पटसन पैकिंग का अनिवार्य प्रयोग, लागत जमा आधार पर बी० टिक्सल बोरों की खरीद, वित्तीय, राजकोषीय तथा बाजार सहायता प्रदान करके विविधीकरण को प्रोत्साहन। इसके अतिरिक्त सरकार ने पटसन मिलों सहित रुग्ण औद्योगिक कंपनियों का पुनरुद्धार करने के उद्देश्य से निवेद्यत्मक, उपकारी तथा सुधारत्मक उपायों का पत्र लगाने तथा उन्हें लागू करने के लिए औद्योगिक तथा वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना भी की है।

सूती वस्त्रों का निर्यात

2570. डा० असीम बाला: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सूती वस्त्रों का कितना निर्यात किया गया; और

(ख) मूल्य वर्धित निर्यात और उपर्युक्त अवधि में कच्चे माल के रूप में सूत के निर्यात की मात्रा और मूल्य का पृथक-पृथक ब्यौरे क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलौत): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान सूती वस्त्र उत्पादों के मूल्यवर्धित निर्यात निम्न अनुसार रहे हैं:—

(आंकड़े मिलियन में)

वर्ष	फैब्रिक		यार्न/घागे		मेड-अप	कुल
	मात्रा (वर्ग मी०)	मूल्य (₹०)	मात्रा (कि०ग्रा०)	मूल्य (₹०)	मूल्य (₹०)	
1989-90	840	8282	62	3643	2888	14813
1990-91	974	10738	91	5163	4609	20511
1991-92	1120	15194	126	9890	6342	31427

स्रोत: टैक्स प्रोसिल, बम्बई।

पिछले तीन वर्षों के दौरान कपास के निर्यात नीचे दिए गए हैं:-

कपास वर्ष	मात्रा (लाख गाठों में प्रत्येक गांठ 170 कि०ग्र०)	मूल्य (मिलियन रु० में)
1989-90	13.71	6105
1990-91	11.90	6205
1991-92	0.44	220

(17/7/92 की स्थिति के अनुसार)

बैंकों में जमाराशि

2571. डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्दरम: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मई 1992 में राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमाराशि में कमी आई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों की कुल अनन्तिम जमाराशि जो पहली मई 1992 को 200874 करोड़ रुपए थी 29 मई 1992 को बढ़कर 202040 करोड़ रुपए हो गई है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए इस अवधि के दौरान 1166 करोड़ की सीमान्तक वृद्धि की छोटक है।

साक्ष्य अधिनियम में संशोधन

2572. श्री मदन लाल खुराना: क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री 13 दिसंबर, 1991 के अतारंकित प्रश्न संख्या 3598 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस बीच सरकार ने निर्णय का अध्ययन कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इंसरराज भारद्वाज): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) निर्णय के अध्ययन के पश्चात् ही इस संबंध में कार्रवाई, यदि कोई है, की जाएगी।

पटसन उद्योग को कार्यक्षम बनाने की योजना

2573. श्री सुदर्शन राय चौधरी: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने पटसन उद्योग को और अधिक कार्यक्षम बनाने हेतु कोई योजना तैयार की है; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौर क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) और (ख) सरकार ने रूग्ण मिलों का पुनरूद्धार करने के लिए अनेक उपाय किए हैं जिनमें शामिल हैं पटसन आधुनिकीकरण निधि का सृजन, विशेष पटसन विकास निधि की स्थापना, खाद्यान्न, चीनी, सीमेंट, उर्वरक के लिए पटसन पैकिंग का अनिवार्य प्रयोग, लागत जमा आधार पर बी टिवल बोरो की खरीद, वित्तीय, राषकोषीय तथा बाजार सहायता प्रदान करके विविधीकरण को प्रोत्साहन। इस उद्देश्य के लिए सरकार ने उच्च शक्ति प्राप्त समिति का भी गठन किया है।

वायुसेना की दक्षिण कमान का स्थानान्तरण

2574. प्रो० (श्रीमती) रीता वर्मा: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वायुसेना की दक्षिण कमान के मुख्यालय को त्रिवेन्द्रम से हटा कर मदुरै ले जाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या मदुरै में वायुसेना की दक्षिण कमान के विस्तार के लिये आवश्यक भूमि तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौर क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री झरद पवार): (क) जी, नहीं

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

जीवन बीमा निगम का कदाचार

2575. श्री विजय कुमार यादव:

श्री गुरुदास कामत:

प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम में एल०आई०सी० पालिसियों पर नकद अभ्यर्पण मूल्य की अपेक्षा अधिक भुगतान करने और चिकित्सा शुल्क का दुरुपयोग किए जाने के कथित मामलों का पता लगाया गया है जैसा कि 30 जून, 1992 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौर क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) से (ग) कलकत्ता में कुछ पालिसियों के संबंध

में 3.46 लाख रुपए अभ्यर्पण मूल्य की कुछ फालतू अदायगी ध्यान में आई थी परन्तु जीवन बीमा निगम द्वारा सम्पूर्ण राशि वसूल कर ली गई थी। वास्तविक स्थिति यह है कि पालिसी धारक को अपनी बीमा पालिसी अभ्यर्पित करने और पालिसी की शर्त और जीवन बीमा निगम के मौजूदा मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार अभ्यर्पण मूल्य प्राप्त करने का अधिकार है। इसलिए पालिसीधारकों को अभ्यर्पण मूल्य की अदायगी करने में जीवन बीमा निगम कार्यालयों में कुछ भी अनियमितता नहीं है। चिकित्सा शुल्कों के दर्विनियोजन का कोई मामला ध्यान में नहीं आया है।

भूतपूर्व सोवियत संघ के साथ व्यापार समझौता

2576. डा० वसंत पवार:

प्र० रासा सिंह रावत:

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) भूतपूर्व सोवियत संघ के साथ उसके विखंडन के समय तक लागू व्यापार समझौतों का ब्यौर क्या है;
- (ख) क्या उस देश में हुए नवीन परिवर्तनों से व्यापार समझौते प्रभावित हुए हैं; और
- (ग) यदि हाँ, तो सरकार ने उस देश के साथ व्यापार संतुलन को किस प्रकार व्यवस्थित किया है अथवा करने का विचार किया है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्रिदि): (क) और (ख) भारत गणराज्य तथा सोवियत समाजवादी गणराज्य के बीच व्यापार करार 31 दिसंबर, 1995 तक वैध था भूतपूर्व सोवियत संघ के विघटन के बाद इस करार की वैधता स्वतः ही समाप्त हो गई।

(ग) व्यापार में असंतुलन के फलस्वरूप भारत को भूतपूर्व सोवियत संघ को तकनीकी ऋण प्रदान करना पड़ा भूतपूर्व सोवियत संघ द्वारा देय भुगतान लेखागत ऋण सेवा के माध्यम से समायोजित किया जा रहा है। इसके अलावा, भूतपूर्व सोवियत संघ के कई गणराज्यों के साथ करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं और अन्यो के साथ इन पर कार्यवाई हो रही है। यह उम्मीद है कि इससे व्यापार अपने पहले के स्तर पर पहुंच जाएगा।

मूल्य आधारित अग्रिम आयात लाइसेंसिंग योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदन

2577. श्री छीतूभाई गामित: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अप्रैल, मई और जून, 1992 के दौरान मुख्य आयात और निर्यात नियंत्रक को मूल्य आधारित अग्रिम आयात लाइसेंसिंग योजना के अंतर्गत कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) इनमें से कितने आवेदन-पत्रों को स्वीकार कर लिया गया है, कितने आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया गया है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या निर्यात घरनों, व्यापार घरनों तथा प्रमुख व्यापार घरनों से प्राप्त आवेदन-पत्रों को विशेष महत्व दिया जा रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार पत्तन कार्यालयों तथा मुख्यालयों में प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या 1037 है।

(ख) उपर्युक्त आवेदन-पत्रों में से 527 स्वीकार कर लिए हैं, 168 खारिज कर दिए गए हैं और 342 आवेदन-पत्र लंबित पड़े हैं, क्योंकि उनमें जानकारी/दस्तावेज त्रुटिपूर्ण है, मूल्यवर्धन कम है तथा पात्रता मानदण्ड पूरे नहीं कर पाए हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रत्नों का निर्यात

2578. श्रीमती सरोज दुबे: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान रत्नों के निर्यात में कितने प्रतिशत की कमी हुई;

(ख) रत्नों के निर्यात में कमी आने के क्या कारण हैं;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्हें इनका निर्यात किया गया और प्रत्येक मामले में रत्नों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई; और

(घ) सरकार का रत्नों का निर्यात बढ़ाने तथा नये बाजारों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) रत्न यानि कि रंगीन रत्न, पत्थर (हीरा, मोती तथा सिन्थेटिक पत्थरों को छोड़कर) के पिछले तीन वर्षों के निर्यात नीचे दिए गए हैं:—

वर्ष	मूल्य (मूल्य करोड़ रु० में)	रुपए में % वृद्धि	अमरीकन डालर में % वृद्धि
1989-90	194.82	+6	-0.85
1990-91	207.70	+6.6	-0.85
1991-92	257.02	+23.75	-10.34

स्रोत: जी चे ई पी सी

रत्न तथा आभूषणों के मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में सामान्य रूप से मंदी के कारण, डालर के रूप में रत्नों के निर्यात में गिरावट आई है।

(ग) रंगीन रत्न-पत्थरों का देशवार निर्यात नीचे दिया गया है:—

(मूल्य करोड़ रुपए में)

देश	1990-91	1991-92
सं० रा० अमेरिका	42.38	64.23
हंगकांग	39.92	47.78
थाइलैण्ड	35.81	49.62
पश्चिम जर्मनी	22.26	26.18
स्वीटजरलैंड	17.73	24.82
अन्य	49.60	44.39
कुल	207.70	257.02

(घ) रत्न तथा आभूषण मर्दों के निर्यातकों को, रत्न तथा आभूषण का निर्यात बढ़ाने के लिए, आयात-निर्यात नीति में अधिसूचित विभिन्न योजनाओं के जरिए कच्चा माल प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है। निर्यातकों को मेलों तथा प्रदर्शनियों में सहभागिता करने तथा विदेशी बाजारों में बाजार सर्वेक्षण के लिए प्रतिनिधिमण्डल भेजने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

भारत और तिब्बत के बीच पुराने व्यापारिक मार्ग को पुनः खोलना

2579. मेजर जनरल (सेवा निवृत्त) भुवन चन्द्र खन्कूरी: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का भारत और तिब्बत के बीच पुराने व्यापारिक मार्गों को पुनः खोलने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो इन मार्गों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन मार्गों को व्यापार हेतु पुनः कब तक खोले जाने का विचार है;

(घ) क्या उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में माणा हो कर जाने वाला मार्ग भी पुनः खोले जाने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस पुराने और पारम्परिक व्यापारिक मार्ग को पुनः न खोले जाने के क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सलमान खुर्रिदी): (क) जी, हाँ।

(ख) से (ङ) चीन के अधिकारीगण अभी सिर्फ उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले के लपुलेख से व्यापार को पुनः आरंभ करने पर सहमत हुए हैं। यह रास्ता प्रत्येक वर्ष जून और सितम्बर के मध्य खुला रहेगा।

[हिन्दी]

आंध्र प्रदेश में फायरिंग रेंज

2580. श्री मृत्युन्जय नायक: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश के नलगोंडा और रंगारेड्डी जिलों में फायरिंग रेंज की स्थापना करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इससे कितने व्यक्तियों के विस्थापित होने की सम्भावना है;

(ग) क्या सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास अथवा उन्हें मुआवजा देने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

2581. प्रो० रासा सिंह रावत: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और मरम्मत के लिए पिछले दो वर्षों के दौरान किये गये कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन कार्यों पर, परियोजना-वार, कितनी धनराशि खर्च की गयी है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) और (ख) प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव के लिये निधियां राष्ट्रीय राजमार्ग-वार नहीं बल्कि राज्य में समस्त राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली के लिए जारी की जाती हैं। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव के लिये वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान क्रमशः 1064.87 लाख रु० और 1212.62 लाख रु० आवंटित किए गए थे।

वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान संस्वीकृत नये कार्यों और इन पर व्यय करने के लिये किए गए आवंटन के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 1990-91, 1991-92 के दौरान संस्वीकृत कार्य तथा किया गया आवंटन

(राशि करोड़ ₹ में)

श्रेणी	संख्या	संस्वीकृत वर्ष 1990-91 लागत के दौरान आवंटन	1991-92 के दौरान आवंटन	टिप्पण
1. वर्ष 1990-91				
I. चौड़ा करके चार लेन बनाना	—	—	—	—
II. चौड़ा करके 2 लेन बनाना	1	3.09	0.20	0.12
III. मौजूदा दो लेनों को मजबूत करना	13	26.48	0.18	3.16
IV. विविध	21	9.97	0.08	2.91
जोड़:	35	39.54	0.46	6.19
V. पुल कार्य	8	5.31	—	1.44
जोड़:	43	44.85	0.46	7.63
2. वर्ष 1991-92				
I. चौड़ा करके चार लेन बनाना	1	93.66	—	—
II. चौड़ा करके दो लेन बनाना	—	—	—	—
III. मौजूदा दो लेनों को मजबूत करना	8	12.06	—	—
IV. विविध	13	1.61	—	—
जोड़	22	107.33	—	—
V. पुल कार्य	5	3.59	—	—
जोड़:	27	110.92	—	—
1990-91 और 1991-92 के लिए कुल जोड़				
	70	155.77	0.46	7.63

कांडला पत्तन में सातवें कार्गो बर्थ का निर्माण

2582. श्री काशीराम राणा: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या कांडला पत्तन में सातवें कार्गो बर्थ का निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है;
 (ख) यदि हां, तो अब तक कितने प्रतिशत कार्य हुआ है; और
 (ग) निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) से (ग) प्रारंभ में इस परियोजना के पूरा होने की तारीख अक्टूबर, 1991 थी। कार्य निष्पादन के दौरान पेश आई तकनीकी समस्याओं के कारण विलम्ब हुआ है और अब इन समस्याओं को हल कर लिया गया है। लगभग 85% कार्य पहले ही पूरा हो चुका है और इस पूरी परियोजना को मार्च, 1993 तक पूरा करने की योजना है। इस तारीख तक इसे पूरा करने के लिए परियोजना पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

[अनुवाद]

केरल में नेशनल सेरीकल्चर प्रोजेक्टों को सहायता

2583. श्री बी० एस० विजयराघवन: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार केरल के पलक्कड और इटुबकी जिलों में स्थापित नेशनल सेरीकल्चर प्रोजेक्ट को सेंट्रल सिल्क बोर्ड ने कितनी सहायता दी है;

(ख) क्या सरकार का विचार चालू योजना अबाध के दौरान राज्य में और अधिक परियोजनाएं शुरू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल में विश्व बैंक और स्विस् की सहायता से राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना के क्रियान्वयन पर खर्च की गई राशि/किया गया निवेश निम्नोक्त अनुसार है:

(लाख रु० में)

वर्ष	प्रदान की गई सहायता (खर्च)
1989-90	6.25
1990-91	35.18
1991-92	132.87

(ख) जी नहीं, केरल में चल रही राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना 1985-96 तक क्रियान्वित की जाएगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

रेशम का उत्पादन/निर्यात

2584. श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कुल उत्पादित रेशम में से उसका कितने प्रतिशत भाग का निर्यात किया गया और यह निर्यात किन-किन देशों को किया गया; और

(ख) सरकार ने देश में रेशम का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) भारत केवल रेशम के उत्पादों का निर्यात करता है न कि कच्चे रेशमी यार्न का। पिछले 3 वर्षों के दौरान निर्यात किए गए रेशमी वस्त्र उत्पादों का प्रतिशत अनुमानित रेशमी वस्त्र उत्पादों के उत्पादन के संबंध में निम्नोक्त अनुसार है:—

वर्ष	रेशमी वस्त्र उत्पादों के निर्यात का प्रतिशत
1989-90	20.0
1990-91	17.3
1991-92	22.0

भारत 100 से अधिक देशों को अपने रेशमी वस्त्र उत्पादों का निर्यात करता है। प्रमुख देश निम्नोक्त अनुसार है:—

1. सं० रा० अमरीका	11. स्वित्जरलैंड
2. संयुक्त जर्मनी	12. हांगकांग
3. ब्रिटेन	13. जापान
4. इटली	14. आस्ट्रिया
5. स्पेन	15. बेल्जियम
6. फ्रांस	16. ओमन
7. कनाडा	17. मारीशस
8. आस्ट्रेलिया	18. नीदरलैंड
9. सिंगापुर	19. लेबनान
10. यू० ए० ई०	20. न्यूजीलैंड

(ख) देश में रेशम उत्पादन को प्रोत्साहन/बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड अनुसंधान, विस्तार तथा प्रशिक्षण एकाइयों के अपने देश-व्यापी नेटवर्क के जरिए आवश्यक सहायता प्रदान करके विभिन्न राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा कर रहा है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रमों के जरिए प्रति हैक्टेयर उत्पादकता में सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय रेशम बोर्ड किसानों को रेशम

उत्पादन शुरू करने में प्रोत्साहन देने के लिए अनेक सहायता कार्यक्रम/योजनाएं भी क्रियान्वित कर रहा है। इसके अलावा 17 राज्यों में क्रियान्वित राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना में देश में शहतूती एकड़ क्षेत्र बढ़ाने तथा क्वालिटी की कच्ची रेशम का उत्पादन बढ़ाने की भी व्यवस्था है।

[अनुवाद]

पारादीप बंदरगाह पर प्रारम्भिक पूंजी निवेश की प्रतिपूर्ति

2585. श्री अर्जुन चरण सेठी: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री 6 दिसम्बर, 1991 के अतारंकित प्रश्न संख्या 2529 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पारादीप बंदरगाह न्यास द्वारा उड़ीसा सरकार को प्रारम्भिक पूंजीगत व्यय की अदायगी की शर्तों को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उड़ीसा सरकार द्वारा प्रारम्भिक पूंजीगत निवेश का प्रतिपूर्ति कब तक की जायेगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस मामले पर निर्णय तभी लिया जा सकता है जब सभी महापत्तनों के पूंजीगत पुनर्गठन तथा महापत्तन न्यासों की गठन-पूर्व ऋण राशियों को प्रतिपादित करने संबंधी तरीके को अंतिम रूप दे दिया जाए।

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974 को समाप्त करना

2586. श्री रवि राय: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 का निरसन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

असम में बैंकों का कामकाज

2588. श्री प्रबोीन डेका: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम में विशेषरूप से दारंग, कामरूप और बारपेटा जिलों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और राष्ट्रीयकृत बैंकों का कामकाज संतोषजनक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि मार्च, 1991 और 1992 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बारपेटा, दारंग और कामरूप जिलों

तथा असम राज्य में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) की कुल जमा राशियां और कुल ऋण राशि निम्नलिखित हैं:

(राशि करोड़ रुपए)

जिला / राज्य	मार्च, 1991			मार्च, 1992		
	जमा राशि	ऋण	ऋण जमा अनुपात	जमा राशि	ऋण	ऋण जमा अनुपात
बारपेटा	45.49	26.23	57.66	51.10	30.98	60.63
दरांग	42.92	20.41	47.55	50.79	30.99	61.02
कामरूप	751.63	433.63	57.69	829.52	444.23	53.55
असम	2178.36	1117.13	51.28	2424.02	1190.64	49.12

जबकि मार्च, 1991 की तुलना में मार्च, 1992 में असम राज्य के साथ-साथ सभी तीन जिलों में जुटाई गई जमा राशियों और ऋण संवितरण में वृद्धि हुई है, ऋण जमा अनुपात में समग्र रूप से असम के साथ-साथ कामरूप जिले के मामले में कुछ गिरावट आई है। तथापि, किसी क्षेत्र विशेष में स्थानीय रूप से जुटाई गई जमा राशियों की तुलना में ऋण संवितरण के लिए ऋण जमा अनुपात ही एक मात्र सूचक नहीं है। इसे कई बातें प्रमाणित करती हैं जैसे कि:— आधारभूत सुविधाएं, स्थानीय सरकार के प्राधिकारियों आदि का सहयोग इन तत्वों के न होने से ऋण कार्यक्रम पर विपरीत प्रभाव पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप ऋण जमा अनुपात प्रभावित होती है। असम में बैंकों का कार्य निष्पादन, कानून और व्यवस्था की असंतोषजनक स्थिति, संदर्भाधीन तीन जिलों का बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र होना, निवेश वितरण प्रणाली के कमजोर होने और उन्नत तकनीक के कम स्पष्टान्तरण आदि के कारण भी प्रभावित हुआ है।

(ग) क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए योजनाबद्ध रूप में ऋण संवितरण की आवश्यकता हेतु बैंकों से कहा गया है। बैंकों से आशा की जाती है कि वे विभिन्न क्षेत्रों में सभी उत्पादन और पहचान किए गए अर्थक्षम कार्यों के लिए ऋण दें और विभिन्न क्षेत्रों में ऋण संवितरण की व्यापक असमानताओं को कम करना सुनिश्चित करें। बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे अपनी ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं के मामले में अलग-अलग 60% ऋण जमा अनुपात बनाए रखें।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 पर भूमिगत मार्ग (सब-वे) का निर्माण

2589. श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 पर पुणे और कोल्हापुर के बीच भूमिगत मार्ग का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में हलद्वानी में उपमार्ग सड़क का निर्माण

2590. श्री अष्ट भुजा प्रसाद शुक्ल: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से उत्तर प्रदेश के नैनीताल जिले में हलद्वानी में एक उपमार्ग सड़क के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) और (ख) जी, हां। बड़ी हुई केन्द्रीय सड़क निधि के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित 500.00 लाख रु० की अनुमानित लागत वाले हलद्वानी बाईपास के निर्माण के प्रस्ताव पर अनुमोदन हेतु विचार नहीं किया जा सका क्योंकि संसद द्वारा 13.5.1988 को पारित संशोधित संकल्प अभी कार्यान्वित नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा फर्मों का पंजीकरण

2591. श्री के० तुलसिएया वान्डायार: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्यात संवर्धन परिषदें विभिन्न फर्मों के उत्पादों का निर्यात करने के लिए उनका पंजीकरण करती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा इन निर्यात करने वाली फर्मों को कितनी सहायता दी जा रही है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्रिद): (क) जी हां।

(ख) निर्यात संवर्धन परिषदें निर्यात करने वाली फर्मों की कई तरह से सहायता करती हैं। परिषदों के प्रमुख कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

- (1) निर्यातों का विकास करने तथा उनमें वृद्धि करने के लिए अपने सदस्यों को वाणिज्यिक रूप से लाभप्रद जानकारी तथा सहायता प्रदान करना;
- (2) प्रौद्योगिकी उन्नयन, गुणवत्ता और अभिकल्प (डिजाइन) में सुधार, मानक और विशिष्टियां, उत्पाद विकास, नवीकरण, आदि जैसे क्षेत्रों में अपने सदस्यों को व्यावसायिक सलाह देना;
- (3) विदेश में संभावनाओं का पता लगाने के लिए अपने सदस्यों के प्रतिनिधिमंडलों के दौरे आयोजित करना;

- (4) भारत तथा विदेश में व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों तथा क्रेता-विक्रेता बैठकों में सहभागिता आयोजित करना; और
- (5) निर्यात करने वाले समुदाय और सरकार के बीच परस्पर विचार-विनिमय को बढ़ाना।

[हिन्दी]

राज्यों को जनता कपड़े के आबंटन का लक्ष्य

2592. श्री श्रीकान्त जेना:

श्री अर्जुन सिंह यादव:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों को जनता कपड़े का आबंटन-लक्ष्य केवल राज्यों में चल रहे हथकरघों की संख्या और इसके पिछले उत्पादन के आधार पर निर्धारित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इस संबंध में विशेषकर उड़ीसा और उत्तर प्रदेश का पृथक-पृथक कार्यनिष्पादन क्या रहा है;

(ग) उपर्युक्त राज्यों को विगत दो वर्ष के दौरान प्रतिवर्ष आबंटित जनता कपड़े का लक्ष्य क्या था और वर्ष 1992-93 के लिए लक्ष्य क्या है; और

(घ) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं कि जनता कपड़ा देश के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों को आसानी से उपलब्ध हो?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) जी हां,

(ख) गत 2 वर्षों में उत्तर प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में जनता कपड़े का उत्पादन इस प्रकार है:—

(मिलियन वर्ग मीटर में)

वर्ष	उड़ीसा	उत्तर प्रदेश
1990-91	31.92	119.14
1991-92	26.74	100.00

(ग) गत 2 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उपरोक्त राज्यों को आबंटन किये जाने के लिए जनता कपड़े का लक्ष्य इस प्रकार है:—

(मिलियन वर्ग मीटर में)

वर्ष	उड़ीसा	उत्तर प्रदेश
1990-91	33.00	132.00
1991-92	27.00	100.00
1992-93	30.00	100.00

(घ) लक्षित समूह में जनता कपड़े की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायित्व राज्य सरकारों को भारत सरकार द्वारा निदेश दिये गये हैं कि गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों को जनता कपड़े का वितरण सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाये जायें। जनता कपड़े के वितरण के लिए जारी मार्गदर्शिका में यह प्रावधान है कि कम से कम 75% कपड़ा ग्रामीण क्षेत्रों के लक्षित समूह को बेचा जाये। ग्रामीण पंचायतों और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे अभिकरणों का पता लगाया जाये जिनके अपने वितरण विक्रय केन्द्र हैं।

[अनुवाद]

कोचीन शिपयार्ड का आधुनिकीकरण

2593. श्री रमेश चेत्रितला: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा कोचीन शिपयार्ड के आधुनिकीकरण के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) और (ख) 1984 में मुख्य परियोजना कार्य पूरा हो जाने के पश्चात कोचीन शिपयार्ड लि० के आधुनिकीकरण के लिए 7वीं योजनावधि 1985—90 तथा वार्षिक योजना 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान 40.48 करोड़ रु० की राशि दी गई। ब्यौरा इस प्रकार है:—

व्यय (करोड़ रु०)

7वीं पंचवर्षीय योजना	1985-90	1990-91	1991-92
1. अतिरिक्त जहाज निर्माण सुविधाएं	4.02	0.43	—
2. क्वे-1 का विस्तार	12.20	4.85	—
3. डिजायन संबंधी परामर्श	5.94	0.43	—
4. उत्पादन संबंधी परामर्श	2.45	—	—

5. नवीनीकरण तथा रिप्लेसमेंट	4.30	—	—
6. जहाज निर्माण सुविधाओं का आधुनिकीकरण	—	—	5.86
योग:	28.91	5.71	5.86

उपर्युक्त के अतिरिक्त कोचीन शिपयार्ड लि० में निवेश के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992—97) में अनन्तिम रूप से 47.80 करोड़ रु० की राशि का प्रावधान किया गया है। विवरण इस प्रकार है:—

आठवीं पंचवर्षीय योजना प्रावधान (करोड़ रु०)

(क) जहाज परम्पत सुविधाओं का आधुनिकीकरण	8.00
(ख) क्षमता उपयोग में सुधार	11.20
(ग) नवीनीकरण एवं रिप्लेसमेंट	3.60
(घ) अतिरिक्त जहाज परम्पत सुविधाएं	25.00
योग:	47.80

[हिन्दी]

औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों को बैंकों से ऋण

2594. श्री राजवीर सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रत्येक राज्य में वर्ष 1991 के दौरान तथा चालू वर्ष में 31 मई, 1992 तक औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों को दी गई ऋण राशियों का पृथक-पृथक ब्यौर क्या है;

(ख) उपर्युक्त अवधि में दोनों क्षेत्रों से वसूल की गई ऋण राशियों का पृथक-पृथक क्या ब्यौर है; और

(ग) इस समय प्रत्येक राज्य में बैंकों से ऋण प्राप्त करने हेतु कितने आवेदन पत्र लंबित हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार 22 मार्च, 1991 और 20 मार्च, 1992 के अंत की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उद्योग और कृषि को दिए गए अग्रिमों की बकाया राशि नीचे दी गई है:—

(करोड़ रुपए)

क्षेत्र	की स्थिति के अनुसार बकाया	
	22 मार्च 1991	20 मार्च 1992
कृषि	10,658	11,524
उद्योग (लघु मध्यम और बड़े)	34,208	36,374

अलबत्ता, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कृषि अग्रिमों का राज्य-वार ब्यौर सितम्बर, 1990 के अंतिम शुक्रवार, तक का उपलब्ध है। औद्योगिक क्षेत्र के मामले में लघु उद्योग क्षेत्र के ही राज्य-वार आंकड़े सितम्बर, 1990 के अंतिम शुक्रवार तक के उपलब्ध हैं।

जहां तक ऋण की वसूली का सम्बन्ध है केवल कृषि को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता देने से संबंधित राज्य-वार सूचना ही उपलब्ध है। औद्योगिक अग्रिमों की वसूली के मामले में आंकड़ा सूचना प्रणाली से राज्य-वार सूचना

प्राप्त नहीं होती है। अलबत्ता, मार्च 1991 के अंत तक की स्थिति के अनुसार (अद्यतन उपलब्ध) औद्योगिक क्षेत्र में बकाया अग्रिमों की तुलना में अतिदेय राशियों की प्रतिशतता 33.65% थी।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि और लघु क्षेत्र के उद्योगों के अग्रिमों के संबंध में सितम्बर, 1990 के अंत तक (अद्यतन उपलब्ध) और जून 1990 (अद्यतन उपलब्ध) के अंत तक की स्थिति के अनुसार कृषि को दी गई प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता की राज्य-वार वसूली की सूचना अनुबन्ध में दी गई है।

(ग) बैंकों से ऋण प्राप्त करने के इच्छुक लोगों से प्राप्त लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या के संबंध में वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से सूचना प्राप्त नहीं होती है।

विवरण

जून, 1990 के अंत की स्थिति के अनुसार प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की वसूली तथा सितम्बर, 1990 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार कृषि एवं लघु उद्योगों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिमों का अलग-अलग राज्यवार दर्शाने वाला विवरण:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अग्रिमों की बकाया धनराशि (करोड़ रुपए)		कृषि अग्रिमों की वसूली की प्रतिशतता (प्रत्यक्ष वित्त पोषण)
	कृषि	लघु उद्योग	
हरियाणा	652	439	48.7
हिमाचल प्रदेश	78	86	37.3
जम्मू व कश्मीर	30	63	37.8
पंजाब	1143	893	64.0
राजस्थान	682	383	38.0
चण्डीगढ़	200	86	24.8
दिल्ली	212	1199	31.6
असम	130	152	24.1
मणिपुर	7	15	9.4
मेघालय	13	7	18.2
नागालैण्ड	23	16	19.7
त्रिपुरा	23	13	16.5
अरुणाचल प्रदेश	3	3	56.2
मिजोरम	2	4	20.9
सिक्किम	2	3	35.1
बिहार	761	512	42.5
उड़ीसा	328	238	37.0
पश्चिम बंगाल	590	1092	40.7
अण्डमान और निकोबार	2	2	17.1
मध्य प्रदेश	1126	654	42.5

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अग्रिमों की बकाया धनराशि (करोड़ रुपए)		कृषि अग्रिमों की वसूली की प्रतिशतता (प्रत्यक्ष वित्त पोषण)
	कृषि	लघु उद्योग	
उत्तर प्रदेश	1631	1381	48.5
गुजरात	821	1199	48.0
महाराष्ट्र	1564	2637	43.8
दमन और दीव	1	7	45.3
गोवा	34	62	48.3
दादरा और नागर हवेली	1	2	59.5
आन्ध्र प्रदेश	1933	922	48.3
कर्नाटक	1375	951	42.9
केरल	637	490	57.6
तमिलनाडु	1907	1800	61.4
पाण्डिचेरी	50	22	51.5
लक्षद्वीप	0.3	0.04	55.8

उत्तर प्रदेश में बैंकों द्वारा निवेश

2596. श्री गद्य प्रसाद कोरी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में निवेश करने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कुल कितना निवेश किया गया; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय निवेश औसत की तुलना में उक्त निवेश का प्रतिशत कितना था?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) से (ग) सम्भवतः माननीय सदस्य राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का हवाला दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योजना अवधि के दौरान जून, 1989 तक (अद्यतन उपलब्ध) सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा औद्योगिक क्षेत्र को दिए गए अग्रिमों

की वर्ष-वार कुल बक़्क्या धनराशि तथा अखिल भारतीय स्तर की तुलना में उसका प्रतिशत नीचे दिया गया है:—

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	अखिल भारत	उत्तर प्रदेश	अखिल भारत के मुकाबले में उत्तर प्रदेश की प्रतिशतता
दिसम्बर, 1986	23305	1206	5.2
जून, 1987	24347	1556	6.4
जून, 1988	32617	2016	6.2
जून, 1989	38906	2511	6.5

बैंकों द्वारा औद्योगिक क्षेत्र को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। तथापि, बैंकों को अपने निवल ऋणों का 40 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र को उपलब्ध कराने के लिए परामर्श दिया गया है, जिसमें लघु उद्योग भी शामिल है।

उत्तर प्रदेश में अफीम पर आधारित औषधों की तस्करी

2597. श्री अयूब खान: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के बाणबंकी तथा लखनऊ जिले में अफीम से तैयार की गई औषधों के उपयोग और इनकी तस्करी के बारे में अप्रैल, 1992 में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन शिकायतों की केन्द्रीय अन्वेषण ब्यौरे अथवा स्वापक नियंत्रण ब्यौरे द्वारा जांच कराए जाने के अनुदेश जारी कर दिये हैं;

(घ) यदि हां, तो कब और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) से (ङ): सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन प्रटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

आयकर अधिनियम की धारा 80-एल के अन्तर्गत कर रियायतों के कारण राजस्व की हानि

2598. श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-एल के अंतर्गत कर रियायतें देने के कारण केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को कोई राजस्व घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार राज्यों के घाटे को पूरा करने के लिए उन्हें कोई सहायता अनुदान देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) और (ख) वित्त विधेयक, 1992 में, जैसाकि इसे लोक सभा में पुरः स्थापित किया गया था, धारा 80-एल के अध्यक्षीन मौजूदा कटौती को वापस लिए जाने का एक प्रस्ताव निहित था। लेकिन, एक सरकारी संशोधन के द्वारा धारा 80-एल के अध्यक्षीन उक्त कटौती को वापस लिए जाने के प्रस्ताव में संशोधन करके कटौती को पूर्ण रूप से वापस लिए जाने के पूर्ववर्ती प्रस्ताव की बजाय 7000/- की एक आर्थिक-सीमा तक कटौती को बरकरार रखा गया था।

धारा 80-एल के अध्यक्षीन कटौती को पूर्ण रूप से वापस लिए जाने के संबंध में वित्त विधेयक में निहित उक्त प्रस्ताव के संदर्भ में इस कटौती को आंशिक रूप से बरकरार रखने के परिणामस्वरूप 225 करोड़ रुपये की राजस्व हानि होने का अनुमान है। इससे राज्यों को लगभग 190 करोड़ रुपये की तथा केन्द्र को 35 करोड़ रुपये की आनुपातिक हानि होगी।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। ऊपर-उल्लिखित आनुपातिक हानि के होते हुए भी आयकर में राज्यों की हिस्सेदारी वर्ष 1992-93 के बजट-अनुमानों में बढ़कर 5868 करोड़ रुपये हो जायेगी, जबकि वर्ष 1991-92 के बजट अनुमानों में यह राशि 4565 करोड़ रुपये थी। कुल मिलाकर, राज्यों के करों तथा शुल्कों की हिस्सेदारी, जिसमें संघ सरकार के उत्पादन शुल्क भी शामिल हैं, वर्ष 1992-93 के बजट-अनुमानों में बढ़कर 19992 करोड़ रुपये हो जायेगी जबकि वर्ष 1991-92 के बजट अनुमानों में यह राशि 16255 करोड़ रुपये थी।

मादक द्रव्यों का अवैध व्यापार

2599. श्री प्रतापराव बी० भोंसले: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मादक द्रव्यों का अवैध व्यापार बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में गत दो वर्षों के दौरान कितने व्यक्ति पकड़े गए; और

(घ) इस अवैध व्यापार को रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) और (ख) "मादक द्रव्य" जिसमें शराब एवं औषध दोनों शामिल हैं तथा शराब की विक्रय नीति राज्य सरकार के क्षेत्र के अन्तर्गत आती है। अधिकांश राज्यों में शराब की बिक्री वैध है। जहां तक स्वापक औषध एवं मनः प्रभावी पदार्थों का सम्बंध है ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि उनका अवैध व्यापार बढ़ रहा है।

(ग) स्वापक औषध एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या निम्नप्रकार है—

1990	4,302
1991	5,300

(घ) नशीले पदार्थों के दुरुपयोग को नियंत्रण में करने के लिए वर्ष 1985 में एक कठोर एवं व्यापक कानून

अर्थात् स्वापक औषध एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम बनाया गया था। वर्ष 1988 में संशोधन करके इस कानून को और भी अधिक सख्त बना दिया गया। स्वापक औषध एवं मनः प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा गहन एवं समन्वित प्रयास किए जाते हैं।

हौजरी के वस्त्रों का निर्यात

2600. श्री सी० के० कुप्पुस्वामी: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विश्व बाजार में हौजरी की वस्त्रों के कुल खरीद में भारत का हिस्सा कितना प्रतिशत है; और
(ख) सरकारी ने हौजरी के वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये क्या उपाय किये हैं ताकि निर्यात में इसका भाग अधिक हो सके?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) वर्ष 1990 में विश्व के क्लोटिंग के निर्यात में, जिनमें हौजरी परिधान भी शामिल है, भारत का अंशदान 2 प्रतिशत था (स्रोत-गाट)।

(ख) सरकार ने हौजरी परिधानों सहित सिले-सिलाए परिधानों का निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जैसे कि नई परिधान मशीन मर्दों को निशेधात्मक सूची के बाहर रख करके उनके आयात को सुकर बनाना, उदार निर्यात संवर्धन (पूँजीगत माल), योजना, ट्रिपिंग और एम्बेलिशमेन्ट की अतिरिक्त मर्दों को रियायती शुल्क के लाभ प्रदान करना, टैग, लेबल आदि की आयात सीमा को बढ़ाना, मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस योजना के साथ-साथ मात्रा आधारित अग्रिम लाइसेंस योजना के जरिए शुल्क मुक्त कच्चे माल को सुकर बनाना, उदार विनिमय दर प्रबंध पद्धति शुरू करना आदि। इसके अतिरिक्त तिरुपुर में अपरेल प्रशिक्षण तथा डिजाइन केन्द्र की स्थापना के अलावा विशेषज्ञता प्राप्त निटवीयर प्रतिनिधिमेंडल भेजने आदि जैसे उपाय भी किए गए हैं।

पारादीप पत्तन में नये कारगो/मशीनीकृत कोयला-बर्थों का निर्माण

2601. श्री के० प्रधानी:

श्री लोकनाथ चौधरी:

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के पारादीप पत्तन में एक बहुदेशीय कारगो बर्थ तथा मशीनीकृत कोयला बर्थ का निर्माण करने के लिये 24.94 करोड़ रुपये और 511.25 करोड़ रुपये के पूँजी निवेश के संबंध में कोई निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) और (ख) 26.36 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर एक बहु-प्रयोजनीय कारगो बर्थ के निर्माण तथा 559.89 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर यांत्रिक कोयला बर्थों के निर्माण के लिए पारादीप पत्तन के प्रस्तावों के संबंध में सरकार द्वारा अभी निर्णय लिया जाना है।

पंजाब से रूई का निर्यात

2602. श्री कमल चौधरी: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्र सरकार को रूई की गांठों के निर्यात हेतु पंजाब सरकार से कोई निवेदन प्राप्त हुआ है; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य को कितनी रूई के निर्यात की अनुमति दी गई है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) जी हां,

(ख) पंजाब मार्कफेड ने मध्यम रेशे की कपास की 1 लाख गांठों के निर्यात कोटे का अनुरोध किया था।

(ग) चालू कपास मौसम के दौरान पंजाब मार्कफेड को कपास का कोई निर्यात कोटा आबंटित नहीं किया गया है

मद्रास पत्तन से क्रेनों को हटाना

2603. श्री पांडुरंग पुंडलिक फुंडकर: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मद्रास पत्तन पर साधारण क्रेनों के स्थान पर गैनेट्रि क्रेनें लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नई क्रेनों की अनुमानित लागत कितनी है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) से (ग) जी, हां। 34.50 करोड़ रु० की अनुमानित लागत वाली ऐसी तीन क्रेनों की खरीद का सुझाव दिया गया है। अभी तक इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

हस्तशिल्प हेतु नई योजनाएं

2604. श्री संदीपान भगवान धोरात: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हस्तशिल्प के पुर्नवीकरण के लिये कुछ नई योजनाएं आरंभ की हैं जैसा कि 16 जून, 1992 के "इकानामिक टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) और (ख) इकोनामिक टाइम्स दिनांक 16 जून, 1992 में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट का अभिप्राय दिल्ली प्रशासन की योजनाओं से है। हस्तशिल्प राज्य का विषय होने के नाते विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाएं संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों के क्षेत्राधिकार में आती हैं। तथापि विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के माध्यम से चलाई जा रही वस्त्र मंत्रालय की योजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

चालू और नई योजनाओं की विस्तृति और मुख्य-मुख्य बातें

क्रमांक	योजना का नाम	उद्देश्य
1.	विपणन विकास सहायता	हस्तशिल्प के विपणन/विकास में लगे संगठनों को एक मुश्त सहायता के रूप में सहायता देने की संशोधित योजना (केन्द्रीय/राज्य हस्तशिल्प विकास निगम/शीर्ष समितियाँ ऐच्छिक संगठन)।
2.	विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र और अन्य विपणन कार्यक्रम	1. विशेषकर शिल्प संकेन्द्रित क्षेत्रों में शिल्पकारों को विपणन एवं अन्य सेवाएं प्रदान करना। 2. विपणन, ऋण, कच्चा माल और डिजाइन विकास में सहायता देना।
3.	शिल्प विकास केन्द्र	1. सामान्य सुविधा केन्द्रों और कच्चा माल डिपों की पूर्ण योजना की एक संशोधित संयुक्त योजना। 2. अधिज्ञात शिल्प पार्कों में शिल्प विकास केन्द्रों को स्थापित करने में केन्द्रीय राज्य हस्तशिल्प निगमों और अन्य संगठनों को सहायता देना। 3. शिल्पकारों को उत्पादन, बाजार संबंधी और सामाजिक सेवाएं प्रदान करना।
4.	डिजाइन एवं तकनीकी विकास	1. डिजाइन विकास—विपणन योग्य बनाने के लिए परम्परागत शैली का पता लगाना और नई डिजाइनों का नवीकरण करके दोनों द्वारा शिल्पकारों को सहायता के लिए एक संशोधित योजना। 2. उत्पादों को विकसित करने/नई किस्म का तैयार करने के लिए डिजाइनकारों, तकनीकी परामर्शदाताओं को नियुक्त करने के लिए निगमों/शीर्ष/समितियों/ऐच्छिक संगठनों को सहायता देना।
5.	राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय	1. परम्परागत शिल्पों का संरक्षण एवं प्रलेखन करना। 2. उपरोक्त शिल्पों में जागरूकता का प्रसार करना। 3. लुप्त प्राय शिल्पों को पुनर्जीवित करना।
6.	पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम	1. पूर्वोत्तर क्षेत्र के शिल्पकारों के लाभ के लिए कुशलता और कच्चे माल के रूप में विशाल साधनों को काम में लाना। 2. केन्द्रीय बिन्दु के रूप में कार्य करना और कारीगरों एवं शिल्पकारों को आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करना।
7.	सर्वेक्षण एवं अध्ययन	हस्तशिल्प में आंकड़ा आधार बनाने के लिए शिल्प विशिष्ट और क्षेत्र विशिष्ट सर्वेक्षण करना।
8.	प्रदर्शनी एवं प्रचार	1. हस्तशिल्प के विपणन/विकास में लगे संगठनों (निगमों, सहाकारी समितियों, शीर्ष समितियों) को प्रदर्शनी आयोजित करने में सहायता देना।

क्रमांक	योजना का नाम	उद्देश्य
		2. विज्ञापन, प्रोडर, कैटलाग आदि सहित बाजार संबंधी प्रचार अभियान चलाना और इसे चलाने में संगठनों की सहायता करना।
9.	निर्यात संवर्धन	हस्तशिल्प के निर्यातों का संवर्धन करना।
10.	प्रशिक्षण	1. उच्च कुशलता को विकसित करना और अधिक मांग वाले/निर्यात अभिमुख शिल्पों और लुप्त प्राय शिल्पों दोनों में प्रशिक्षण देना। 2. रोजगार सुअवसरों को बढ़ाना।
11.	सामाजिक सुरक्षा और अन्य कार्यकलाप, पुरस्कार और पेंशन योजना	1. शिल्पकारों को उनकी श्रेष्ठता को मान्यता प्रदान करने और दरिद्रावस्था/दुर्बल अवस्था में अनुवर्ती वित्तीय सुरक्षा दोनों के रूप में शिल्पकारों की सुरक्षा/विश्वास को बढ़ाना। 2. शिल्पकारिता में उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए शिल्पकारों को राष्ट्रीय पुरस्कार देना।
12.	केन्द्रीय/राज्य निगमों और शीर्ष समितियों में इक्विटी भागीदारी	हस्तशिल्प के विपणन में लगे संगठनों के इक्विटी आधार को मजबूत बनाना।
13.	सामान्य सुविधा केन्द्र	यह योजना केवल विभाग द्वारा सीधे चलाए जा रहे सामान्य सुविधा केन्द्रों और उचित दर पर कच्चा माल प्राप्त करने और खरीदने/तैयार करने के लिए सुविधाएं प्राप्त करने में शिल्पकारों को सहायता देने से संबंधित है। सामान्य सुविधा केन्द्रों और कच्चा माल डिपों के लिए सहायता को शिल्प विकास केन्द्र योजना में सम्मिलित कर लिया गया है।
	(ख) नई योजनाओं	
14.	केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम द्वारा भवन का अधिग्रहण करना।	राज्य व्यापार निगम से भवन का अधिग्रहण करने के लिए केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम को निधि प्रदान करना।
15.	हस्तशिल्प भवन का निर्माण	ऐसे राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की बिक्री दुकानों को, जिनका दिल्ली में कोई एम्पोरियम नहीं है, समायोजित करने के लिए बाबा खडक सिंह मार्ग पर हस्तशिल्प भवन के निर्माण के लिए निधि का उपयोग करना।
16.	लुप्त प्रायः शिल्पों को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष कार्यक्रम (योजना आयोग के अनुमोदन की प्रतीक्षा है)।	डिजाइन विकास, प्रशिक्षण, प्रदर्शनी आदि जैसे विभिन्न उपायों के माध्यम से लुप्त प्रायः शिल्पों का पता लगाने सर्वेक्षण करने और पुनर्जीवित करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाना।

संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा हथकरघों पर आयात शुल्क लगाना

2605. श्री जार्ज फर्नांडीज: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका का विचार भारतीय हथकरघों पर आयात शुल्क लगाने का है; और
(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्रिद): (क) और (ख) एक विवरण-पत्र संलग्न है।

विवरण

विकासशील देशों के संबंध में अधिमानी टैरिफ की अमरीकी जी एस पी योजना के उपबन्धों के अधीन यदि अमरीका जी एस पी के तहत किसी लाभभोगी देश से किसी खास उत्पाद का आयात करता है और वह आयात किसी कैलेन्डर वर्ष विशेष में उस मद के कुल आयात के 50 प्रतिशत से अधिक होता है तो ऐसी स्थिति में वह मद बाद के वर्ष में जी एस पी लाभों के लिए पात्र नहीं रहेगी। किन्तु, यदि किसी देश से आयात निर्धारित न्यूनतम स्तर (जिसमें प्रति वर्ष संशोधन होता रहता है) से कम होता है तो अमरीकी राष्ट्रपति को स्वविवेक से छूट देने का अधिकार है। इस स्वविवेक का इस्तेमाल भारतीय हथकरघा के पक्ष में अमरीका के उस निर्णय में नहीं किया गया जिसकी घोषणा दिनांक 29 अप्रैल, 1992 को की गई और जो दिनांक 19 मई, 1992 से प्रभावी हुआ। इसके फलस्वरूप, प्रभावित उत्पादों का जब भारत से आयात होगा तब वे शुल्क मुक्त व्यवहार के पात्र नहीं रहेंगे। किन्तु, इन उत्पादों पर छह प्रतिशत की दर से परम मित्र राष्ट्र टैरिफ लगेगा। इसी निर्णय द्वारा अमरीका ने टैरिफ अनुसूची की सुमेलित प्रणाली के अध्याय 28—38 में विहित रसायनों और भेषजों आदि के भारतीय निर्यात पर भी जी एस पी रियायतें देना बंद कर दिया है।

यह निर्णय अमरीका के उस घोषित इरादे से जुड़े हैं जिसमें भारत की एकस्व (पेटेन्ट) प्रणाली में नीतिगत संशोधन किए जाने की अपेक्षा की गई है। सरकार ने अमरीकी प्राधिकारियों को इस आशय की सूचना दे दी है कि अमरीका द्वारा की गई उक्त कार्रवाई नाजायज, असामयिक और अवांछित है। इस पर अमरीका की यह प्रतिक्रिया रही कि यदि भारत-एकस्व-संरक्षण के विषय पर अमरीका की चिन्ताओं पर ध्यान देता है तो उक्त कार्यवाही रद्द की जा सकती है।

दिल्ली के न्यायालयों में विवाह संबंधी लम्बित पड़े मामले

2606. श्री हरिन पाठक, क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली की निचली अदालतों/उच्च न्यायालय में अदालत/न्यायालय-वार विवाह संबंधी कितने मामले पांच वर्षों से लेकर दस वर्ष पहले की अवधि से लम्बित पड़े हैं; और

(ख) सरकार इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिये क्या कदम उठा रही है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

अफीम का उत्पादन

2607. श्रीमती वसुंधरा राजे: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में हुए अफीम के उत्पादन का वर्षवार ब्यौर क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार अफीम की खेती और अधिक क्षेत्र में करने का है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1991-92 में इस बारे में क्या कदम उठाये गये; और

(घ) वर्ष 1991-92 के दौरान विशेष रूप से राजस्थान में अफीम उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) पोस्त उगाने वाले तीन राज्यों, अर्थात् मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में फार्मास्युटिकल और निर्यात प्रयोजनों के लिए गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान अफीम का उत्पादन इस प्रकार रहा:—

(90° संसक्ति वाली अफीम कि०ग्रा० में)

	1989-90	1990-91	1991-92 (अनन्तिम)
मध्य प्रदेश	225467	201147	234498
राजस्थान	156431	129474	161074
उत्तर प्रदेश	55187	61624	72922
जोड़	437085	392245	468494

(ख) इस समय ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ग) और (घ) इसलिए, ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

प्याज और लहसुन का निर्यात

2608. श्री भीम सिंह पटेल: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्याज और लहसुन किन-किन देशों को निर्यात किए जाते हैं;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान, उपर्युक्त उत्पादों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ग) इन उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार किया है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्रिदी): (क) प्याज तथा लहसुन का निर्यात

संयुक्त अरब अमीरात, बंगलादेश, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, सउदी अरब, कुवैत, बहरीन, मालदीव, मारीशस, नेपाल, पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, सेशेल्स, ओमान, जर्मनी इत्यादि को किया जाता है।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान प्याज तथा लहसुन के निर्यात से अर्जित की गई विदेशी मुद्रा नीचे दर्शायी गई है:—

(लाख रुपये में)

	1990-91*	1991-92**
प्याज और लहसुन	9286*	19000**

स्रोत: * वाणिज्यिक जानकारी और सांख्यिकी महानिदेशालय।

** निर्यातकों के विवरण पर आधारित अनन्तितम।

(ग) प्याज की पहचान अच्छी निर्यात संभावना वाली थ्रस्ट मद के रूप में की गई है तथा गुणवत्ता और पैकेजिंग में सुधार पर विशेष बल दिया गया है।

राज्यों द्वारा ओवरड्राफ्ट

2609. श्री ललित उरांव: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन राज्यों ने भारतीय रिजर्व बैंक के अपने खातों से 1988-89, 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान जमा राशि से अधिक धन निकाला और प्रत्येक राज्य ने ओवरड्राफ्ट के रूप में कितना-कितना धन निकाला;

(ख) उक्त धनराशि में से वर्षवार कितनी धनराशि का समायोजन किया गया है और कितनी धनराशि बिना समायोजन के ही रह गई है; और

(ग) सरकार ने राज्यों द्वारा ओवरड्राफ्ट लेने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे): (क) से (ग) विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) वित्त वर्ष 1988-89, 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान विभिन्न अवसरों पर भारतीय रिजर्व बैंक के पास अपने खातों में ओवरड्राफ्ट में रहे राज्य सरकारों के नाम तथा ओवरड्राफ्ट की अधिकतम राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(करोड़ रु० में)

राज्य	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92
1. आंध्र प्रदेश	—	—	—	—
2. अरुणाचल प्रदेश	7.92	2.04	15.43	5.48
3. असम	56.07	187.55	149.31	60.89

राज्य	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92
4. बिहार	—	31.20	148.56	237.28
5. गोवा	—	—	—	—
6. गुजरात	138.85	36.37	26.71	154.25
7. हरियाणा	14.73	2.77	12.56	0.64
8. हिमाचल प्रदेश	4.82	38.13	74.98	49.71
9. कर्नाटक	68.30	49.99	15.94	—
10. केरल	83.54	45.38	78.77	156.76
11. मध्य प्रदेश	39.52	177.22	95.54	212.68
12. महाराष्ट्र	—	—	—	—
13. मणिपुर	—	10.94	13.36	18.53
14. मेघालय	—	—	—	—
15. मिजोरम	19.60	19.58	4.14	19.79
16. नागालैंड	—	18.43	30.51	36.05
17. उड़ीसा	52.51	59.54	49.62	113.18
18. पंजाब	86.34	—	—	—
19. राजस्थान	77.81	89.52	21.16	40.66
20. तमिलनाडु	29.65	70.02	143.47	234.33
21. त्रिपुरा	10.21	10.73	11.28	19.31
22. उत्तर प्रदेश	—	64.00	223.85	347.95
23. पश्चिम बंगाल	—	—	5.33	259.00

(ख) ऊपर पैरा (क) में बताई गई राज्य सरकारों में से हिमाचल प्रदेश और नागालैंड की राज्य सरकारों को छोड़कर अन्य सभी के ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट विनियमन स्कीम में निर्धारित समय सीमा के अन्दर पूरे कर दिए गए थे। हिमाचल प्रदेश और नागालैंड सरकारों के संबंध में आठवें लगातार कार्य दिवस को शेष ओवरड्राफ्ट की राशि नीचे दिए गए अनुसार थी:—

1. हिमाचल प्रदेश : 13.43 करोड़ रुपए (19.7.1989 को)
2. नागालैंड : 15.40 करोड़ रुपए (28.3.1990 को)

(ग) ओवरड्राफ्ट विनियमन स्कीम के अनुसार, किसी भी राज्य सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के पास उसके खाते में लगातार सात कार्य दिवसों से अधिक समय तक ओवरड्राफ्ट में रहने की इजाजत नहीं है। यदि किसी राज्य सरकार के खाते में सात लगातार कार्य दिवसों से अधिक समय तक ओवरड्राफ्ट बना रहता है तो भारतीय रिजर्व बैंक उस राज्य सरकार की ओर से भुगतान करना बंद कर देगा। यह स्कीम भारतीय रिजर्व बैंक के साथ लेन-देन करने वाली सभी राज्य सरकारों के मामले में समान रूप से तथा बिना किसी अपवाद के लागू की जा रही है।

[अनुवाद]

आयकर विभाग द्वारा दिल्ली में अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण

2610. श्री राम नरेश सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XX-ग के उपबंधों के अधीन दिल्ली में कितनी अचल सम्पत्तियों का अधिग्रहण किया गया तथा उनका मूल्य कितना है;

(ख) इन सम्पत्तियों की बिक्री से कितनी धनराशि प्राप्त हुई; और

(ग) उन मामलों का ब्यौरा क्या है जिनके संबंध में उच्च-न्यायालयों अथवा उच्चतम न्यायालय में मुकदमों/याचिकाएं लम्बित होने के कारण अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XX-ग के अधीन खरीदी गई अचल सम्पत्तियों की संख्या तथा उनका मूल्य निम्नानुसार है:—

वित्त वर्ष	संख्या	मूल्य
1989-90	16	6,17,28,750 रुपये
1990-91	12	5,79,20,000 रुपये
1991-92	10	7,18,35,600 रुपये

(ख) पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XX-ग के अधीन दिल्ली में खरीदी गई अचल सम्पत्तियों की बिक्री से वसूल हुई धनराशि निम्नानुसार है:—

वित्त वर्ष	वसूल की गई राशि
1989-90	5,65,87,000 रु०
1990-91	1,30,00,111 रु०
1991-92	7,64,65,000 रु०

(ग) ऐसे मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण 'क' में दिया गया है, जिनमें पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान दिल्ली में की गई खरीददारी के संबंध में उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में मुकदमों के अनिर्णीत पड़े रहने के कारण क्रय-आदेश को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है।

विवरण

वित्त वर्ष 1989-90 के दौरान की गई खरीददारी

क्रम सं०	सम्पत्तियों की संख्या	क्रय-आदेश की तारीख	प्रत्यक्ष-प्रतिफल की राशि	न्यायालय, जिसमें मुकदमा अनिर्णीत पड़ा हुआ है
1	2	3	4	5
1.	3 / 3, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली	11-7-89	70 लाख रु०	दिल्ली उच्च न्यायालय
2.	फ्लैट संख्या 756, एशियन गेम्स विलेज, नई दिल्ली	27-11-89	20 लाख रु०	दिल्ली उच्च न्यायालय
3.	डी-1028, न्यू फ्रेड्स कालोनी, नई दिल्ली	14-12-89	40 लाख रु०	दिल्ली उच्च न्यायालय
4.	ई-44/10, ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली	19-1-90	23 लाख रु०	दिल्ली उच्च न्यायालय

वित्त वर्ष 1990-91 के दौरान की गई खरीददारी

1	2	3	4	5
1.	3/90, कनाट सर्कस, नई दिल्ली	20-4-90	24 लाख रु०	दिल्ली उच्च न्यायालय
2.	111, गोल्फ लिंकस, नई दिल्ली	25-5-90	1.15 करोड़ रु०	उच्चतम न्यायालय
3.	बी-26, कैलारा कालोनी, नई दिल्ली के प्रथम तल पर स्थित सम्पत्ति	25-5-90	30 लाख रु०	दिल्ली उच्च न्यायालय
4.	701, सहयोग बिल्डिंग नई दिल्ली	31-11-90	14.70 लाख रु०	दिल्ली उच्च न्यायालय
5.	6, जन्तर मन्तर रोड, (द्वितीय तल पर स्थित फ्लैट का आबंटन-1100 वर्ग फुट)	20-12-90	11 लाख रु०	दिल्ली उच्च न्यायालय
6.	ए-2, नारायणा इण्डस्ट्रियल एरिया-1, नई दिल्ली	4-2-91	70 लाख रु०	दिल्ली उच्च न्यायालय
7.	एस-1, जी-के-1, नई दिल्ली	17-1-91	75 लाख रु०	दिल्ली उच्च न्यायालय

वित्त वर्ष 1991-92 के दौरान की गई खरीददारी

1	2	3	4	5
1.	25, फ्रेडस कालोनी वेस्ट, नई दिल्ली	18-4-91	1,61,75,600 रु	दिल्ली उच्च न्यायालय
2.	फ्लैट नं० 2, नीलागिरि अपार्टमेंट्स, 9, बरखम्बा रोड, नई दिल्ली	22-8-91	29,00,000 रु जम्मा 15 प्रतिशत जम्मा अन्य प्रभार	दिल्ली उच्च न्यायालय
3.	6, अलीपुर रोड, सिविल लाइन्स, नई दिल्ली	30-12-91	1,80,00,000 रु	दिल्ली उच्च न्यायालय

[हिन्दी]

कंज्यूमैक्स, 92 में अर्जित राजस्व

2611. श्री एन.जे. राठवा: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा प्रगति मैदान, नई दिल्ली में मई, 1992 में आयोजित की गई "कंज्यूमैक्स, 92" द्वितीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सामान प्रदर्शनी में खुदरा बिक्री से कितनी धनराशि प्राप्त हुई; और

(ख) इस बिक्री से सरकार ने कितना राजस्व अर्जित किया?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्रिद): (क) कंज्यूमैक्स, 92 के भाग लेने वालों की रिपोर्ट के अनुसार कुल बिक्री 24.71 लाख रु० की हुई।

(ख) कंज्यूमैक्स, 92 में भाग लेने वालों द्वारा की गई बिक्री से भारत व्यापार संवर्धन संगठन ने कोई राजस्व अर्जित नहीं किया। तथापि आई टी पी ओ को स्थल किराया के रूप में अनुमानतः 11.20 लाख रुपये का शुद्ध राजस्व प्राप्त हुआ।

[अनुवाद]

रुई का लाभकारी मूल्य

2612. श्री माणिकराव होडल्या गावीतः

श्री धर्मीभिक्षमः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्यवार रुई का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) चालू वर्ष के दौरान रुई का पिछला बकाया स्टॉक कितना है और यह स्टॉक स्वदेशी भाग की तुलना से कितना अधिक है;

(ग) किन एजेंसियों के माध्यम से आवश्यकता से अधिक रुई का निर्यात किया जायेगा और यह निर्यात किन-किन देशों को किया जायेगा;

(घ) क्या चालू वर्ष के दौरान रुई का मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में रुई का निर्यात किया गया;

(छ) क्या किसानों को चालू वर्ष के समर्थन मूल्य की तुलना में कम मूल्य मिल रहा है; और

(ज) यदि हां, तो सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है कि किसानों को रुई का लाभकारी मूल्य मिल सके?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) कपास सलाहकार बोर्ड ने 14-2-1992 को हुई अपनी बैठक में यह अनुमान लगाया था कि घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करने के पश्चात् 31-8-1992 की स्थिति अनुसार बक़या स्टॉक संभवतः 20.39 लाख गांठ होने का अनुमान है।

(ग) सरकार ने चालू मौसम के दौरान निर्यात के लिए बंगला देशी कपास की एक लाख गांठें रिलीज की हैं जो कि सभी निर्यातकों के लिए खुली हैं तथा निर्यात के लिए कोई देश-वार प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इसके अतिरिक्त सरकार ने द्विपक्षीय करारों के परिप्रेक्ष्य में नेपाल, बंगला देश और श्रीलंका जैसे कुछ हमारे पड़ोसी देशों की 30 हजार गांठों तक की कपास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारतीय कपास निगम को भी अनुमति दी है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) चालू कपास मौसम के दौरान 17-7-1992 की स्थिति अनुसार कपास की 0.44 लाख गांठों का निर्यात किया गया है। इससे पहले के मौसम के दौरान कपास की 11.90 लाख गांठों का निर्यात किया गया था।

(छ) जी नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1989-90 से 1991-92 के कपास मौसम के दौरान कपास सलाहकार बोर्ड द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार कपास का राज्य-वार उत्पादन

राज्य का नाम	उत्पादन लाख गांठ में — प्रत्येक गांठ 170 कि०ग्रा० की		
	1989-90	1990-91	1991-92
पंजाब	25.44	17.25	25.50
हरियाणा	13.88	11.50	13.50
राजस्थान	10.67	9.50	18.50
गुजरात	17.30	15.00	14.00
महाराष्ट्र	20.17	15.00	11.00
मध्य प्रदेश	13.40	16.00	7.50
आंध्र प्रदेश	15.44	18.75	18.50
कर्नाटक	10.20	8.00	8.50
तमिलनाडु	6.25	5.00	6.00
अन्य	0.75	1.00	1.00
कुल	133.50	117.00	116.00

*कपास सलाहकार बोर्ड की दिनांक 14-2-92 की बैठक के अनुसार

महाराष्ट्र में सैनिक स्कूल खोलना

2613. श्री राम नाईक: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में सिन्धुदुर्ग जिले, टोंडावली में एक सैनिक स्कूल खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितना क्षेत्रफल भूमि अधिग्रहीत करने का विचार है तथा यह किन स्रोतों से ली जायेगी; और

(ग) इस स्कूल को शुरू करने का समयबद्ध कार्यक्रम क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ग) सैनिक स्कूल की स्थापना राज्य सरकार / संघशासित प्रशासन के विशेष अनुरोध पर की जाती है, क्योंकि इस पर आने वाले समग्र पूंजीगत व्यय और अनुवर्ती व्यय का अधिकांश भाग इन्हीं सरकारों द्वारा वहन किया जाता है। महाराष्ट्र के सिन्धुदुर्ग जिले में टोंडावली में एक नया सैनिक स्कूल शुरू करने के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विजयवाड़ा / विशाखापटनम / तिरुपति में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना

2614. श्री दत्तात्रेय बंडारू:

श्री शोभनाश्रीधर राव वाड्डे

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ समुद्र तटवर्ती जिलों के लिये विजयवाड़ा अथवा विशाखापटनम में तथा दूसरी न्यायपीठ रायलसीमा क्षेत्र के लिये कुड्डापाह अथवा तिरुपति में स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में उन उच्च न्यायालय यायपीठों का ब्यौर क्या है जो राज्यों की राजधानियों की अतिरिक्त अन्य स्थानों पर स्थित हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) आंध्र प्रदेश सरकार से, राज्य में किसी भी उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने के लिए, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र सं०	राज्य का नाम	उच्च न्यायालय का नाम	वह स्थान जहां न्यायपीठ कार्य कर रही है
1.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	म्बलियर इन्दौर
2.	महाराष्ट्र	मुंबई	नागपुर औरगाम्बाद
3.	मिझोर	फटना	रांची

खाड़ी देशों के साथ व्यापार

2615. श्री सुशील चन्द्र वर्मा: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष खाड़ी देशों के साथ कितना व्यापार हुआ;
 (ख) खाड़ी के सभी देशों के साथ व्यापार संबंध स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाये गए/उठाये जाने का विचार है; और
 (ग) इन देशों को निर्यात का स्तर बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्रिदी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खाड़ी देशों से किए गए व्यापार की मात्रा निम्नलिखित है:—

(मूल्य : करोड़ रुपयों में)

1989-90	1990-91	1991-92
6,552.34	7,885.25	12,003.37

- (ख) और (ग) इन देशों को निर्यात का स्तर बढ़ाने के लिए किए गए प्रस्तावित प्रयासों में शामिल है:— संयुक्त आयोगों/संयुक्त व्यापार समितियों के मंच पर सरकार से सरकार के साथ द्विपक्षीय विचार-विमर्श, व्यापार प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान, भारत की क्षमताओं का प्रचार करने के लिए भारत और विदेशों में प्रदर्शनियों व्यापार मेलों में भागीदारी, प्रति व्यापार प्रबंध और चुनिंदा देशों को ऋण की कुछ चुनिंदा व्यवस्था आदि।

भारतीय जीवन बीमा निगम का "ब्रिटिश सन लाइफ" के साथ सहयोग

2616. श्री गुरुदास कामत: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ने "ब्रिटिश सन लाइफ" के साथ कोई सहयोग करार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय जीवन बीमा निगम ने यूनाइटेड किंगडम में जीवन बीमा और पेंशन पालिसियों का कारोबार करने के लिए यूनाइटेड किंगडम की सनलाइफ एश्योरेंस सोसाइटी पी०एल०सी० के साथ करार निष्पन्न किए हैं। जारी की गई पालिसियों का पुनर्बीमा सनलाइफ द्वारा किया जायेगा जो आवश्यक प्रशासनिक व तकनीकी सहायता प्रदान करेगी। इससे संबंधित प्रचालन कार्य 11 जून, 1992 से आरंभ हो गए हैं।

असम-अगरतला मार्ग

2617. श्री सैफुद्दीन चौधरी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम-अगरतला मार्ग लगभग हर वर्ष अगरतला के पास टूट जाता है;

(ख) क्या इस मार्ग पर अर्ध स्थाई लकड़ी तथा बेली पुलों के स्थान पर आर०सी०सी० के पुल बना जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सड़क के कब तक पूरा हो जाने का संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) भारी वर्षा के दौरान असम-अगरतला रोड (राष्ट्रीय राजमार्ग-44) का कुछ क्षेत्र, मुख्यतः अगरतला के समीप का क्षेत्र बह जाता है। लेकिन प्रति वर्ष ऐसी स्थिति नहीं आती।

(ख) और (ग) जी, हां। लकड़ी के पक्के पुलों और बेली पुलों के स्थान पर धीरे-धीरे आर०सी०सी० पुल बनाने का काम 1994-95 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है, बशर्ते इसके लिए धन उपलब्ध होता रहे।

जापान को लौह अयस्क का निर्यात

2618. श्री लोकनाथ चौधरी: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान को निर्यात किए गए लौह अयस्क की कुछ मात्रा उसकी खराब गुणवत्ता के कारण उस देश द्वारा स्वीकार नहीं की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो जापान द्वारा कितनी मात्रा में लौह अयस्क लेने से मना कर दिया गया था और इससे एम०एम०टी०सी० को कितना घाटा हुआ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

2619. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व बैंक द्वारा 1 अप्रैल, 1991 और 1 अप्रैल, 1992 तक भारत की कितनी परियोजनाओं को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से वित्त पोषित किया गया है;

(ख) इन परियोजनाओं का, क्षेत्र-वार, उनके उद्देश्य और लक्ष्य, अनुमानित लागत, इसके शुरू होने के वर्ष, इसके पूर्ण होने के अनुमानित वर्ष तथा 31 मार्च, 1992 तक हुए वास्तविक व्यय सहित, संक्षिप्त ब्यौरा क्या है;

(ग) 1 अप्रैल, 1992 तक विश्व बैंक द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी गई और इस तिथि तक सहायता राशि का कितना उपयोग किया गया; और

(घ) सहायता राशि का पूरा उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) और (ख) विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित परियोजनाओं का उपयोग अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों जैसे कृषि, ऊर्जा, उर्वरक, उद्योग, संरचनात्मक ढांचा, सिंचाई, शहरी विकास और सामाजिक क्षेत्रों में किया जाता है। वर्ष 1990-91 तक ऐसी सभी

परियोजनाओं के लिए परियोजना-वार ब्यौरे वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित विदेशी सहायता पुस्तिका में दिए गए हैं। उक्त पुस्तिका की एक प्रतिलिपि संसद के पुस्तकालय में रख दी गई है। 1 अप्रैल, 1991 से 1 अप्रैल, 1992 के बीच कार्यान्वयन के लिए ली गई परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) 1 अप्रैल, 1992 को वचनबद्ध विश्व बैंक वित्तीय सहायता की मात्रा 36,7530 लाख अमेरिकी डालर के बराबर थी और उस तारीख तक इस्तेमाल की गई सहायता 25,6370 लाख अमेरिकी डालर के बराबर थी।

(घ) सहायता बातचीत एक सतत प्रक्रिया है और सहायता वचनबद्धता परियोजनाओं के आधार पर होती है जिसकी सामान्य समयावधि 5 से 8 वर्ष होती है। जहां पर भी आवश्यक समझा जाता है, वचनबद्ध सहायता के पूरे इस्तेमाल को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त संशोधनात्मक उपाय किए जाते हैं।

कर वसूली

2620. श्री हरीश नारायण प्रभु झांड्ये: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान देश में आयकर, धन-कर तथा उपहार कर के रूप में राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी राशि वसूल की गई है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान उन पचास करदाताओं के नाम क्या हैं जिन्होंने उक्त करों में से प्रत्येक कर के अंतर्गत सबसे अधिक राशि अदा की है तथा प्रत्येक करदाता ने कितनी-कितनी राशि अदा की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) वर्ष 1991-92 के दौरान राज्य/संघ शासित राज्य-वार आयकर (जिसमें निगम कर भी शामिल है), धनकर तथा दानकर की वसूली के बारे में विवरण-I संलग्न है।

(ख) चोटी के 20 आयकरदाताओं तथा धनकरदाताओं के बारे में सूचना, उनके कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 की विवरणीगत आय/धन के क्रमानुसार, संलग्न विवरण-II तथा विवरण-III में दी गई है। इन शीर्षस्थ 20 आयकर तथा धनकरदाताओं के बारे में इस सूचना को, जिसे प्रत्येक वर्ष समेकित किया जाता है, समेकित करने में काफी समय लगता है, क्योंकि इस सूचना को समूचे देश में फैले हुए आयकर विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों से एकत्रित किया जाना अपेक्षित होता है। वित्त वर्ष 1991-92 के लिए चोटी के 50 आयकर, धनकर तथा दानकरदाताओं के बारे में इस प्रकार की सूचना को इस स्तर पर एकत्र करने तथा उसे समेकित करने में काफी प्रयास करने होंगे, जोकि प्राप्तव्य उद्देश्यों के अनुरूप नहीं होंगे।

विवरण
विश्व बैंक की सहायता प्राप्त परियोजनाएँ (1.4.1991 से 1.4.1992 तक) विश्व बैंक के साथ हस्ताक्षरित

क्रम सं०	परियोजना का नाम	सहायता की राशि (मिलियन डालर)	संकेत व्यौरा/उद्देश्य	अनुमानित लागत	कार्य की तारीख	दावे की तारीख	31.3.92 तक किया गया इलेमाल
1.	झाँगा और मछली पालन परियोजना (सी-आर-2329-आई० एन०)	85.0 डालर	सहभागिता करने वाले राज्य आंध्र प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिमी बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में झाँगा और मछली का उत्पादन बढ़ाने।	95.0 मि०डॉ०	29.1.92	31.12.98	—
2.	मध्यम कानिकी परियोजना (सी-आर-2328-आई०एन०)	124.0 डालर	कानिकी क्षेत्र में संस्वागत, आर्थिक और पर्यावरण संबंधी सुधार प्राप्त करना।	142.0 मि०डॉ०	-तदेव-	-तदेव-	—
3.	पश्चिम बंगाल कानिकी परियोजना (सी-आर-2341-आई०एन०)	34.0 डालर	-तदेव-	39.0 मि०डॉ०	25.3.92	31.7.97	—
4.	कृषि विकास परियोजना तमिलनाडु (सी-आर-2215-आई०एन०/एल०एन०-300-आई०एन०)	107.53 डालर	(1) विकास संबंधी बाधाओं और स्थापित प्राथमिकताओं का विश्लेषण करने के लिए तमिलनाडु सरकार की क्षमता में सुधार करना।	—	17.4.92	30.9.98	6.80 मि०डॉ०

(2) किसानों को अधिक लागत प्रभावी सेवाएँ प्रदान करने के लिए शिदयतों में और सुधार करना; और

अ

के

(3) उष्य कृषि संपादनाओं में खर्चित प्राथमिकउष्य निवेश में सहायता करना।

5.	बाघ सुरक्षा परियोजना (सी०आर० 2241 / एल०एन० 3325-आई०एन०)	196.80 डालर	—	10.6.91	30.9.97	8.00 मि०डा०
6.	महापट्ट प्रमोण और पर्यावरण सफाई परियोजना	104.33	उष्य जल-आपूर्ति, सफाई	5.6.91	31.12.97	6.82 मि०डा०
7.	बाल उत्पत्तीविता और सुपुंक्षित मातृत्व	219.72	केन्द्र द्वारा प्रायोजित परिवार कल्याण	20.2.92	30.9.95	17.95 मि०डा०
8.	द्वितीय तकनीकी शिक्षा	291.54	उष्य शिक्षा	16.12.91	30.6.99	16.96 मि०डा०
9.	विद्युत उपयोगिता दक्षता सुधार परियोजना	265	ऊर्जा क्षेत्र	14.2.92	31.12.97	14.024 मि०डा०
10.	निजी विद्युत उपयोग (सी०एस०ई०एस०) परियोजना	200	ऊर्जा क्षेत्र	—	31.12.96	—
11.	गैस प्रखलन में कमी	450	गैस क्षेत्र	—	31.12.95	—
12.	औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना	155.6	औद्योगिक प्रदूषण द्वारा उत्पन्न पर्यावरण संबंधी गिण्ट का औद्योगिक क्षेत्र निवारण और उपशमन।	52.00 करोड़ 8.7.91	30.6.98	8.022 मि०डा०

विवरण-I

वित्त वर्ष 1991-92 के दौरान राज्य / संघ शासित राज्य-वार आयकर (जिसमें निगम कर भी शामिल है), धनकर तथा दानकर की वसूली

क्रम सं०	राज्य	आयकर (निगम कर सहित)	धनकर	दानकर
1.	आन्ध्र प्रदेश	381.87	9.50	0.99
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.22	—	—
3.	असम	109.10	1.64	0.06
4.	बिहार	193.81	1.90	0.08
5.	गोआ	52.82	1.99	0.02
6.	गुजरात	696.84	22.11	0.50
7.	हरियाणा	110.22	3.55	0.04
8.	हिमाचल प्रदेश	23.35	0.39	—
9.	जम्मू तथा कश्मीर	49.43	—	—
10.	कर्नाटक	460.05	15.13	0.36
11.	केरल	257.95	5.13	0.32
12.	मध्य प्रदेश	240.78	4.92	0.24
13.	महाराष्ट्र	5355.47	120.26	2.04
14.	मणिपुर	2.16	0.06	—
15.	मेघालय	4.69	0.19	0.09
16.	मिजोरम	—	—	—
17.	नागालैण्ड	2.67	0.02	0.03
18.	उड़ीसा	99.49	0.48	0.03
19.	पंजाब	338.24	9.34	0.08
20.	राजस्थान	191.95	4.78	0.18
21.	सिक्किम	0.46	—	—
22.	तमिलनाडु	1030.74	33.86	1.23
23.	त्रिपुरा	4.83	0.05	0.01
24.	उत्तर प्रदेश	712.23	9.72	0.32
25.	प० बंगाल	1297.62	20.65	1.25
संघ शासित राज्य				
1.	अंडमान तथा निकोबार	3.39	0.01	—
2.	चंडीगढ़	55.42	1.12	0.03
3.	दमन	0.89	0.02	—

क्रम सं०	राज्य	आयकर (निगम कर सहित)	धनकर	दानकर
4.	दीव	0.08	—	—
5.	दादर तथा नागर हवेली	0.25	—	—
6.	नई दिल्ली	1768.78	39.18	0.58
7.	पांडिचेरी	9.72	0.31	0.04
8.	लक्षद्वीप	—	—	—

विवरण-II

कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 के लिए विवरणीगत आय के क्रमानुसार छोटी के 20 आयकर दाता
करोड़ रु० में

क्रम सं०	नाम	घोषित आय	प्रदत्त कर
1	2	3	4
1.	भारतीय जीवन बीमा निगम, बम्बई	1523.00	161.66
2.	तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, देहरादून	609.85	47.16
3.	इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि०, बम्बई	276.38	176.30
4.	भारतीय स्टेट बैंक, बम्बई	230.49	283.65
5.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लि०, दिल्ली	221.24	125.26
6.	महानगर टेलीफोन निगम लि०, नई दिल्ली	139.27	77.06
7.	डिपॉजिटर्स इश्योरेंस एण्ड क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन, बम्बई	127.91	45.71
8.	इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी आफ इंडिया, दिल्ली	93.18	50.31
9.	केनरा बैंक, बंगलौर	86.99	63.46
10.	विदेश संचार निगम लि०, बम्बई	84.45	49.64
11.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०, बम्बई	84.39	48.00
12.	भारतीय सामान्य बीमा निगम, बम्बई	81.75	44.14
13.	टेल्को, बम्बई	78.54	45.72
14.	मीकॉन इंडिया लि०, रांची	75.14	उपलब्ध नहीं
15.	एस०एम०टी०सी० ऑफ इंडिया, दिल्ली	72.49	43.20
16.	बैंक ऑफ इंडिया लि०, बम्बई	71.12	70.22
17.	ऑयल इंडिया लि० धालियाजान, असम	68.40	44.90

1	2	3	4
18.	मफतलाल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्री, बम्बई	66.84	20.04
19.	प्रेसिम इण्डस्ट्रीज लि०, बम्बई	66.67	41.06
20.	आई०टी०सी०लि०, कलकत्ता	65.80	43.00

विवरण-III

कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 के लिए विवरणीगत धन के क्रमानुसार छोटी के 20 धनकरदाता

(करोड़ रु० में)

क्रम सं०	नाम	घोषित धन	प्रदत्त कर
1	2	3	4
1.	श्री एच०सी० कोठारी	77.98	0.70
2.	मै० जे० थॉमस एण्ड कं० (प्रा०) लि०	73.32	1.61
3.	श्रीमती माया डी० कोठारी	53.95	0.80
4.	श्री बद्रुसयाम कोठारी	53.02	0.80
5.	श्रीमती आशा थायार	46.60	उपलब्ध नहीं
6.	श्री एम०बी० सुब्बैया	38.52	0.51
7.	श्री प्रदीप पी० कोठारी	37.67	उपलब्ध नहीं
8.	श्री एम०वी० नारूगप्पुन	37.15	0.48
9.	श्रीमती इन्द्रा कोठारी	36.79	0.47
10.	श्री ए० वेलियन	25.56	उपलब्ध नहीं
11.	श्री बृज किशोर झुवार	24.07	0.21
12.	श्री बसंत कुमार झुवार	24.05	0.24
13.	मै० ईथेलवोल्ड एस्टेट्स (प्रा०) लि०	17.24	0.33

1	2	3	4
14.	श्री माहुल सी० चेकसी	16.39	0.32
15.	हिन्दुस्तान सीबा गाङ्गी लि०	16.02	0.10
16.	जॉनसन एण्ड जॉनसन लि०	13.71	0.09
17.	मै० बुश टी कं० (प्रा०) लि०	12.65	0.25
18.	श्री भरत एस० शाह	11.45	0.22
19.	मै० डालू टी कं० (आई) लि०	11.32	0.25
20.	श्री गोतम एम० जैन	10.00	0.21

पारादीप तथा गोपालपुर पत्तनों को मुक्त पत्तन निर्यात संवर्धन क्षेत्र घोषित करना

2622. श्री गोपीनाथ गजपति: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में पारादीप तथा गोपालपुर पत्तन मुक्त पत्तन का दर्जा दिए जाने अथवा निर्यात संवर्धन क्षेत्र घोषित किए जाने हेतु अर्हता प्राप्त है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन पत्तनों को मुक्त पत्तन तथा निर्यात संवर्धन क्षेत्र घोषित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ग) भारत में मुक्त पत्तन स्थापित करने की संभावना का पता लगाने के लिए गठित सलाहकार समिति ने इसको गोआ में स्थापित किए जाने की सिफारिश की है।

देश में नए निर्यात संसाधन क्षेत्र की स्थापना करने का भी इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रगति मैदान का नवीकरण

2623. श्री सुबास चन्द्र नाथक: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रगति मैदान का नवीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो नवीकरण के काम पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी केन्द्रीय सहायता दी जायेगी;

(घ) क्या नवीकरण के कार्य को पूरा करने के लिए सरकार ने विदेशी सहायता भी मांगी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ग) प्रगति मैदान सार्वजनिक क्षेत्र के एक उद्यम भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आई टी पी ओ) का है और वही इसकी व्यवस्था करता है। आई टी पी ओ प्रगति मैदान में उपलब्ध सुविधाओं में से कुछ का चरणबद्ध रूप में पुनरुद्धार करने के प्रस्तावों पर कार्य कर रहा है। जब कभी भी और जिन प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जाएगा। अनुमानित

लागत उसके अनुसार होगी। सुविधाओं के पुनरुद्धार तथा नवीकरण से संबंधित कार्य आई टी पी ओ द्वारा अपने खुद के संसाधनों के माध्यम से किया जाता है।

(घ) और (ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा किसी बाहरी मदद या सहायता की मांग नहीं की गई है। तथापि, प्रगति मैदान में कुछ हालों के पुनर्निर्माण की परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए, आई टी पी ओ ने मेसर्स नोवीआ इंटरनेशनल, डस्सेल डोर्फ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

भारत-सिंगापुर संयुक्त व्यापार परिषद की बैठक

2624. श्री बी० राजा रवि वर्मा: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-सिंगापुर संयुक्त व्यापार परिषद की हाल ही में कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो बैठक में किन-किन विषयों पर विचार-विमर्श हुआ है;

(ग) इसके या निष्कर्ष निकले हैं;

(घ) क्या रसायनों औषधों, बिजली उपकरणों, कंप्यूटर साफ्टवेयर और आटोमोबाइल उपकरणों आदि जैसी मदों का जिनका सिंगापुर अन्य देशों से आयात करता है, भारत से निर्यात करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इसमें सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्रिद): (क) जी हां।

(ख) से (घ) व्यापार, विश्वव्यापी उत्पादन के लिए भारत में विनिर्माण संभावना, सिंगापुर और इस क्षेत्र में भारतीय निवेशकों के लिए संभावना आदि समस्याओं और संभावनाओं पर विचार-विमर्श हुआ। सहयोग के लिए उल्लिखित क्षेत्रों में साफ्टवेयर, आभूषण, इलैक्ट्रानिक्स, हल्के इंजीनियरी उत्पाद, इंजेक्शन मोल्डिंग, छ: परतों वाले पी सी बी का उत्पादन और सिंगापुर के जरिए भारतीय उत्पादों का अन्तर्राष्ट्रीय विपणन आदि शामिल है।

(ङ) सिंगापुर के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में सरकारी स्तर पर द्विपक्षीय विचार-विमर्श करना, एक-दूसरे के यहां दौरे करना, और प्रतिनिधिमंडल भेजना और बुलाना तथा प्रदर्शनी/व्यापार मेलों में भाग लेना शामिल है।

केरल में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के युवकों को ऋण

2625. श्री थाइल जॉन अंजलोज: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के जिन बेरोजगार युवकों ने बड़े मझौले और लघु उद्योगों की स्थापना पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंकों से ऋण लेने हेतु आवेदन किया है, उनकी वर्ष-वार संख्या कितनी है; और

(ख) वर्ष-वार कितने व्यक्तियों को और कितनी राशि का ऋण दिया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ख) आंकड़ा सूचना प्रणाली से पूछे गए ढंग के अनुसार सूचना प्राप्त नहीं होती। अलबत्ता, दिसम्बर, 1988, सितम्बर 1989 और सितम्बर 1990 (अद्यतन — नब्ब) के अंतिम शक्रवार की स्थिति के अनुसार केरल राज्य में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों

द्वारा कृषि और लघु उद्योगों के लिए अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों को दिए गए बकाया अग्रिमों की कुल राशि और खातों की संख्या निम्नानुसार थी:—

(लाख रुपए में)

निम्नलिखित के अनुसार	केरल में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों को अग्रिम			
	कृषि		लघु उद्योग	
	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
दिसम्बर 1988	116929	2391	26509	1874
सितम्बर 1989	122553	2792	23477	956
सितम्बर 1990	130953	3407	23831	1170

सल्बोनी स्थित बैंक नोट प्रेस

2626. श्री सत्यगोपाल मिश्र: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में सल्बोनी में बैंक नोट प्रेस स्थापित करने के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) सरकार ने निर्धारित समय के भीतर इस कार्य को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) भारतीय रिजर्व बैंक पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में सल्बोनी में एक बैंक नोट प्रेस की स्थापना कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि सिविल निर्माण कार्य तीव्रगति से चल रहा है। मुख्य संयंत्र तथा उपकरणों की आपूर्ति के लिए संविदाओं पर कार्यवाही पूरी होने वाली है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि वे परियोजना को अनुसूची के अनुसार पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं। प्रारंभिक उत्पादन 1993 के मध्य में आरम्भ हो जाने की आशा है जबकि प्रेस के 1995 के मध्य तक पूरी तरह कार्य शुरू कर देने की आशा है।

नई आर्थिक नीति का पूंजीनिवेश पर प्रभाव

2627. श्री पी० सी० थामस: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की यह जानकारी है कि नई आर्थिक नीति के परिणामस्वरूप दक्षिणी राज्यों विशेषरूप से केरल में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में किया गया पूंजीनिवेश अब बम्बई तथा अन्य बड़े शहरों के पूंजीपतियों के हाथों में जा रहा है;

(ख) क्या सरकार का पूंजीनिवेश के इस प्रवाह को रोकने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) से (ख) जी, नहीं। यदि इस प्रकार के विशिष्ट उदाहरण सरकार के ध्यान में लाए जाएं तो उचित कार्यवाही करने पर विचार किया जाएगा।

भारतीय अपतटीय निधि

2629. श्री श्रवण कुमार पटेल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अपतटीय निधि (इंडियन आफ-सोर फण्ड) का अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में भारी छूट पर व्यापार किया जा रहा है जैसा कि 22 जून, 1992 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) से (ग) 30 जून, 1992 की स्थिति के अनुसार इंडिया फण्ड, इंडिया प्रोथ फण्ड, इंडिया मैग्रम फण्ड, हिमालयन फण्ड, इंडियन आफ-सोर फण्ड को उनकी निवल परिसंपत्ति पर क्रमशः 38.67 प्रतिशत, 20.34 प्रतिशत, 30.24 प्रतिशत और 33.20 प्रतिशत की छूट देते हुए कोट किया गया था। विश्व भर में कंट्री फण्डों का कारोबार नकदी विहीनता और इन फण्डों आदि की ओर निवेशकों की प्रतिकूल धारणा जैसे कारकों के कारण छूट पर होता रहा है। भारत की प्रचलित उदारीकरण की नीति से आफ-सोर फण्डों के निष्पादन में सुधार होने की आशा है।

बैंकों की शाखाएं

2630. श्री ह्याराधन राय:

श्री राजवीर सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों की राज्यवार और बैंकवार कितनी शाखाएं खोली गई हैं;

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान राज्यवार और बैंकवार कितनी शाखाएं खोलने का विचार है;

(ग) आसनसोल सब-डिवीजन में कितने और कौन कौन से बैंक कार्य कर रहे हैं;

(घ) क्या आसनसोल सब-डिवीजन में बैंकों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1989, 1990 और 1991 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा देश में खोली गई शाखाओं की राज्य-वार और जिला-वार संख्या क्रमशः संलग्न विवरण I-II में दी गई है।

(ख) वर्तमान लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाएं खोलना एक निरंतर प्रक्रिया है जो इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए लाइसेंसों से नियंत्रित होती है। इस प्रकार 1992-93 के दौरान देश में खोली जाने वाली शाखाओं की राज्य-वार और बैंक-वार संख्या का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

(ग) आसनसोल उप मंडल में कार्य कर रहे बैंकों के नाम और उनकी शाखाओं की संख्या संलग्न विवरण III में दी गई है।

(घ) से (च) 1990—95 की योजना के अंतर्गत आसनसोल में दो स्थानों का आबंटन किया गया है। इनमें एक-एक स्थान स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर और यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया को उनकी शाखाएँ खोलने के लिए आबंटित किया गया है।

विवरण-I

1989, 1990 और 1991 के दौरान देश में खोली गई बैंक शाखाओं की राज्यवार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1989	1990	1991
1. अण्डमान और निकोबार	4	—	4
2. आन्ध्र प्रदेश	95	53	27
3. अरुणाचल प्रदेश	5	2	—
4. असम	52	40	5
5. बिहार	117	188	27
6. चण्डीगढ़	—	—	1
7. दिल्ली	26	11	2
8. गोवा	2	1	—
9. गुजरात	42	28	2
10. हरियाणा	11	4	3
11. हिमाचल प्रदेश	42	31	6
12. जम्मू व कश्मीर	10	3	—
13. कर्नाटक	82	36	11
14. केरल	26	13	3
15. लक्षद्वीप	2	—	—
16. मध्य प्रदेश	185	50	14
17. महाराष्ट्र	149	85	18
18. मणिपुर	2	10	3
19. मेघालय	5	7	10
20. मिजोरम	2	2	2
21. नागालैंड	1	1	—
22. उड़ीसा	50	140	16
23. पाण्डिचेरी	1	—	—
24. पंजाब	13	4	3
25. राजस्थान	146	21	4
26. सिक्किम	2	—	1

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1989	1990	1991
27. तमिलनाडु	77	25	3
28. त्रिपुरा	3	12	1
29. उत्तर प्रदेश	230	165	55
30. पश्चिम बंगाल	146	160	31

विवरण-II

1989, 1990 और 1991 के दौरान देश में खोली गई शाखाओं की बैंक-वार संख्या

बैंक का नाम	1989	1990	1991
इलाहाबाद बैंक	88	40	10
आन्धा बैंक	46	11	3
बैंक आफ बड़ौदा	99	76	14
बैंक आफ इंडिया	90	96	21
बैंक आफ महाराष्ट्र	57	15	—
केनरा बैंक	49	39	5
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	147	94	27
कारपोरेशन बैंक	9	1	3
देना बैंक	32	13	4
इंडियन बैंक	32	10	3
इंडियन ओवरसीज बैंक	31	8	2
न्यू बैंक आफ इंडिया	11	10	4
ओरियंटल बैंक आफ कमर्स	26	7	1
पंजाब एंड सिंध बैंक	12	8	2
पंजाब नेशनल बैंक	158	144	26
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	32	2	2
भारतीय स्टेट बैंक	309	293	76
स्टेट बैंक आफ मैसूर	17	3	4
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	30	17	16
स्टेट बैंक आफ इंदौर	29	2	6
स्टेट बैंक आफ पाटियाला	15	11	2
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	8	2	2
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	10	5	—

बैंक का नाम	1989	1990	1991
सिडिकेक बैंक	36	35	5
यूको बैंक	8	16	2
यूनियन बैंक आफ इंडिया	85	28	1
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	39	101	11
विजया बैंक	23	5	—

विवरण-III

31-12-1991 की स्थिति के अनुसार आसनसोल उप मण्डल में कार्यरत बैंकों के नाम और उनकी शाखाओं की संख्या

क्रम सं बैंकों के नाम	शाखाओं की सं०
1. भारतीय स्टेट बैंक	3
2. बैंक आफ बड़ौदा	1
3. इलाहाबाद बैंक	3
4. बैंक आफ इंडिया	1
5. केनरा बैंक	1
6. देना बैंक	1
7. इंडियन बैंक	1
8. इंडियन ओवरसीज बैंक	1
9. सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	1
10. यूनियन बैंक आफ इंडिया	1
11. यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	4
12. पंजाब नेशनल बैंक	1
13. यूको बैंक	2
14. सिडिकेक बैंक	1
15. आन्धा बैंक	1
16. ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	1
17. पंजाब एण्ड सिंध बैंक	1

क्रम सं	बैंकों के नाम	शाखाओं की सं०
18.	न्यू बैंक आफ इंडिया	1
19.	विजया बैंक	1
कुल		27

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की मृत्यु

2631. श्री अन्ना जोशी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1991 में और 1992 के दौरान अब तक विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत हिरासत में हुई बताई गई मौतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन मामलों के बारे में कोई जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में जांच का क्या निष्कर्ष निकला; और

(घ) सरकार ने ऐसी मौतों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय में मृत्यु का एक मामला है। जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:—

श्री सविन्द्र सिंह उर्फ सुरेन्द्र सिंह से प्रवर्तन निदेशालय, लोक नायक भवन के कार्यालय में पूछताछ की जा रही थी। दिनांक 29-2-92 को प्रातः उन्हें निदेशालय के कार्यालय की छठी मंजिल से छलांग लगा दी। उन्हें नई दिल्ली के डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ले जाया गया। इयूटी पर तैनात डाक्टर ने घोषित किया कि श्री सविन्द्र सिंह "मृत जाए गए"।

(ख) से (घ) उच्च न्यायालय के निदेशानुसार जिला और सत्र न्यायाधीश ने श्री सविन्द्र सिंह की किन परिस्थितियों में मृत्यु हुई इसकी जांच-पड़ताल करने के लिए एक वरिष्ठ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को नियुक्त किया है। ऐसा समझा जाता है कि न्यायाधीश ने अपनी जांच पूरा कर ली है और अपनी रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत कर दी है। अतः मामला उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीन है।

प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियां

2632. डा० ए० के० पटेल: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, विशेष रूप से गुजरात में, राज्य-वार प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों की संख्या कितनी है;

(ख) पिछली तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार इन सहकारी समितियों द्वारा उत्पादित हथकरघा सामान का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन समितियों के पास कोई स्टॉक जमा हो गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) इस समय देश में 13543 प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियां हैं जिनमें से गुजरात में 1298 सहकारी समितियां हैं। इनका जिला-वार विवरण इस प्रकार है:—

क्र० सं०	गुजरात राज्य के जिलों का नाम	प्राथमिक बुनकर सह० समितियों की सं०
1.	अहमदाबाद	251
2.	अमरेली	17
3.	भावनगर	48
4.	भारूच	10
5.	बड़ोदरा	14
6.	बनास कन्था	31
7.	गांधीनगर	10
8.	जामनगर	39
9.	जूनागढ़	237
10.	कुच-भुज	16
11.	खेड़ा	62
12.	मेहसाना	30
13.	पंचमहल	26
14.	राजकोट	81
15.	सूरत	10
16.	साबर कन्ठा	48
17.	सुरेन्द्र नगर	359
18.	वालसद और डंग	9

कुल: 1298

(ख) गुजरात में गत 3 वर्षों के दौरान इन प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों द्वारा उत्पादित हथकरघा सामान का विवरण इस प्रकार है:—

वर्ष	उत्पादन (लाख रुपयों में)
1989-90	2205.37
1990-91	3277.69
1991-92	1769.57

(ग) जी हां।

(घ) गुजरात राज्य सरकार द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार 1 जुलाई, 92 को 59.43 लाख रुपये मूल्य का 402980 मीटर कम्बे का स्टॉक था।

(ङ) हथकरघा मर्दों की सामयिक बिक्री की प्रकृति को देखते हुए गुजरात में इस समय हथकरघा उत्पादों का स्टॉक संतुलित है। तथापि गुजरात राज्य सरकार इन प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों द्वारा उत्पादित सामान के विपणन में वृद्धि करने और संचित माल की शीघ्र बिक्री करने के उद्देश्य से पूरे वर्ष 5% की छूट देती है और साथ ही विशेष अवधि में विशेष रिबेट भी दी जाती है। भारत सरकार के विपणन विकास सहायता कार्यक्रम, जिसमें गुजरात राज्य सरकार भी बराबर का योगदान देती है, के अंतर्गत प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों को अपने उत्पादों का विपणन बढ़ाने हेतु नियमित वित्तीय सहायता दी जाती है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना

2633. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश की किसी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है,

(ख) यदि हां तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा अनेक तथ्यों पर निर्भर करती है जैसे राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की सिफारिशें, अखिल भारतीय आधार पर प्रत्येक सड़क की पारस्परिक प्राथमिकता, नए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए निर्धारित मापदंडों की पूर्ति और इस प्रयोजन के लिए निधियों की उपलब्धता, इत्यादि। तथापि धन की अत्यधिक कमी के कारण उत्तर प्रदेश सहित अधिकांश राज्यों में नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित नहीं किए जा सके।

[अनुवाद]

दिल्ली और महाराष्ट्र में रक्षा भूमि का वाणिज्यिक उपयोग

2634. श्रीमती गीता मुखर्जी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली और महाराष्ट्र में रक्षा मंत्रालय की भूमि की बिक्री करने/इसका वाणिज्यिक उपयोग करने संबंधी कोई निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली और महाराष्ट्र में कुल कितनी-कितनी भूमि उपलब्ध है तथा इस प्रयोजनार्थ निश्चित की गई भूमि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में अपनाई गई प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

आवश्यकता से अधिक रक्षा भूमि के निपटान की नीति जारी रखना

(क) से (ग) 1.1 सरकार की सदैव यह नीति रही है कि जो भूमि स्थायी तौर पर रक्षा आवश्यकताओं से फलतू घोषित की जाती है उसे बाजार मूल्य पर निम्नलिखित अग्रता-क्रम में दी गई एजेंसियों को बेच दिया जाएगा:—

- (1) केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालय
- (2) राज्य सरकार
- (3) स्थानीय निकाय
- (4) शैक्षणिक और धर्मार्थ संस्थान
- (5) भूतपूर्व सैनिक

1.2 यदि उपर्युक्त एजेंसियों ऐसी रक्षा भूमि को नहीं खरीदती हैं तो उसे सार्वजनिक नीलामी से बेच दिया जाता है।

साधनों की कमी सभी संभव संसाधन जुटाना

2.1 सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण और पूंजीगत निर्माण-कार्यों के लिए अपेक्षित संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए ऐसी रक्षा भूमि का पता लगाया जा रहा है जो स्थायी तौर पर रक्षा आवश्यकताओं से फलतू है। दिल्ली और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में ऐसी भूमि का पता लगा लिया गया है।

2.2 अब तक दिल्ली और महाराष्ट्र में संलग्न विवरण 1 और 2 में बताए अनुसार कतिपय क्षेत्रों में रक्षा भूमि निपटान के लिए नियत कर ली गई है। महाराष्ट्र सरकार को यह प्रस्ताव भेजा गया है कि वे इस भूमि का बाजार मूल्य अदा करने पर इसे ले सकते हैं।

2.3 जहां तक दिल्ली में फलतू पड़ी रक्षा भूमि के निपटान का संबंध है, इस बारे में संबंधित अधिकारियों से परामर्श करके समुचित कार्यविधि तैयार की जा रही है।

विवरण—I
दिल्ली में फालतू पड़ी रक्षा भूमि का ब्यौरा

क्रम सं०	भूमि	एकड़
1.	दिल्ली में बुगड़ी मैदान की भूमि	104.170 एकड़
2.	राजपुर मार्ग बंगला नं० 12	4.440 एकड़
3.	आनन्द पर्वत	264.680 एकड़
4.	छतरपुर	0.940 एकड़
5.	खानपुर	126.142 एकड़
6.	किंगसवे कैम्प	50.000 एकड़
7.	नारायणा जंक्शन	1.000 एकड़
8.	शाकूरबस्ती	240.000 एकड़
		कुल=791.372 एकड़

विवरण—II
महाराष्ट्र में सैनिक पड़ावों की फालतू पड़ी भूमि का ब्यौरा

क्रम सं०	भूमि	एकड़
1.	रहटगांव	3.350
2.	हिवाड़ा	29.975
3.	बेलूर	7.375
4.	सूरवाड़ा	6.993
5.	धमक	12.975
6.	पारातवाड़ा	402.083
7.	वारूड	1.700
8.	अमरावती	2.325
9.	सेओनी	4.400

क्रम सं०	भूमि	एकड़
10.	करंजा	30.500
11.	परगड़ी	35.175
12.	कयार	0.950
13.	बघोना	0.500
14.	कलजार	3.910
15.	रेहना	6.000
16.	हिगनघट	12.610
17.	गोरेवाड़ा	9.500
18.	मनसार	14.940
19.	परसोड़ी	9.250
20.	थाणे	4.980
		कुल=598.491

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

2635. श्री अर्जुन सिंह यादव:
 श्री हरि केवल प्रसाद:
 डा० लाल बहादुर रावत:
 प्रो० रासा सिंह रावत:

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) 1991-92 और 1992-93 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से राज्यवार कितने प्रस्ताव मिले हैं;
- (ख) स्वीकृत किए गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक प्रस्ताव के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के किन भागों को विकसित/मरम्मत की जायेगी; और
- (ग) शेष प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा दिये गये ऋण

2636. श्री यशवन्तराव पाटिल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय आवास बैंक ने आवास निर्माण हेतु कोई ऋण दिया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने लोगों को ऋण दिया गया है और इस प्रकार ऋण की कुल कितनी धनराशि दी गई है; और

(ग) उक्त ऋण की शर्तें क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) राष्ट्रीय आवास बैंक अलग-अलग व्यक्तियों को सीधे ही आवास वित्त प्रदान नहीं करता है। राष्ट्रीय आवास बैंक अपने मार्गनिर्देशों के अनुसार संवितरित किए गए पात्र ऋणों के संबंध में सभी पात्र प्राथमिक ऋणदाताओं (अर्थात् अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, आवास वित्त संस्थायें और राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी आवास वित्त समितियां) को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है।

(ख) राष्ट्रीय आवास बैंक की विभिन्न पुनर्वित्त योजनाओं (राज्य स्तरीय विकास बैंकों द्वारा चलाए गए विशेष ग्रामीण आवास डिवेंचर के लिए अंशदान सहित) के अंतर्गत 8.50 लाख आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए उसने जून 1992 तक कुल 1198.09 करोड़ रुपये का संवितरण किया।

(ग) राष्ट्रीय आवास बैंक नए आवास एककों के अधिग्रहण/निर्माण के लिए आवास ऋणों के संबंध में 100% पुनर्वित्त प्रदान करता है:— (I) 40 वर्ग मी० से अनाधिक के निर्मित क्षेत्रों के लिए 2 लाख रुपए तक (II) 40 वर्ग मी० से अधिक के निर्मित क्षेत्र लेकिन 2 लाख रुपए से अनाधिक की लागत वाले एककों के लिए ऋण राशि तक और (III) बड़ी मरम्मतों सहित उन्नयन के लिए 30,000/— रुपए तक। राष्ट्रीय आवास बैंक, आकार/लागत पैरामीटरों के संबंध में राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार, तैयार की गई उन समन्वित भूमि विकास एवं आश्रय परियोजनाओं के लिए, जो (I) सार्वजनिक एजेंसियों, (II) सहकारी समितियों, (III) व्यावसायिक विकासकों द्वारा और (IV) नियोजकों द्वारा किराया आवास के लिए शुरू की जा सकती हैं, भी 100% पुनर्वित्त प्रदान करता है।

[अनुवाद]

कामगार पुनर्वास निधि योजना के लिए धनराशि निर्धारित करना

2637. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कपड़ा मिलों के स्थायी रूप से बंद हो जाने के कारण बेरोजगार हो गये कामगारों को अंतरिम राहत पहुंचाने के लिए वर्ष 1991-92 और 1992-93 के लिए वर्ष-वार, कामगार पुनर्वास निधि योजना हेतु बजट में कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इसके अंतर्गत किन-किन मिलों को शामिल किया गया; और

(ग) अगले दो वर्षों में कितनी मिलों को इसमें शामिल किया जायेगा?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) वर्ष 1991-92 के लिए बजट प्रावधान के रूप में 40 करोड़ रु० की राशि आबंटित की गई। वर्ष 1992-93 के लिए 60 करोड़ रु० की राशि आबंटित की गई है।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) बंद पड़ी मिलों के उन सभी पात्र कामगारों को राहत प्रदान की जानी है जोकि नीति के अंतर्गत आते हैं, इसलिए यह एक सतत प्रक्रिया है। इसलिए उन मिलों की संख्या का अनुमान लगा पाना कठिन है जिन्हें अगले दो वर्षों के दौरान शामिल किए जाने की संभावना है।

विवरण

वस्त्र कामगार पुनर्वास निधि योजना के अंतर्गत पात्र मिलों की सूची

तमिलनाडु

1. मै० कावेरी स्पि० मिल्स, कोयम्बतूर।
2. मै० राधाकृष्णन मिल्स, कोयम्बतूर।

महाराष्ट्र

3. मै० मोडला टेक्स० इंडिया लि०, थाने।
4. मै० किस्को मिल्स प्रा० लि०, बम्बई।

दिल्ली

5. मै० डी०सी०एम०लि०

गुजरात

6. मै० बन्सीधर मिल्स, अहमदाबाद।
7. मै० नागारी मिल्स, -वही-
8. मै० पी०जी० टेक्स०, बडोदा।
9. मै० श्री यमना मिल्स, बडोदा।
10. मै० अजीत मिल्स, अहमदाबाद।
11. मै० भारत सुर्योदया, मिल्स, अहमदाबाद।
12. मै० प्रसाद मिल्स लि०, अहमदाबाद।
13. मै० अहमदाबाद श्री रामकृष्णा मिल्स लि०, अहमदाबाद।
14. मै० अरयोध्या स्पि० एंड वि० मिल्स, अहमदाबाद।
15. मै० न्यू गुजरात सिन्थेटिक लि०, नं० 1 अहमदाबाद।
16. मै० न्यू गुजरात सिन्थेटिक लि०, नं० 2 अहमदाबाद।
17. मै० अहमदाबाद कमरसियल मिल्स, अहमदाबाद।
18. मै० नवजीवन मिल्स (कालोल)।
19. मै० कालोल मिल्स (कालोल)।
20. मै० ओमक्स इनवेस्टर, अहमदाबाद।
21. मै० अमरुता मिल्स, अहमदाबाद।
22. मै० अहमदाबाद जुबिली मिल्स, अहमदाबाद।

23. मै० अरयोधया गंज० एंड मन्यू० कं० लि०, अहमदाबाद।

24. मै० विवेकानन्द मिस्स, अहमदाबाद।

[हिन्दी]

कपास के बिनौले की "खली" का निर्यात

2638. श्रीमती शीला गौतम: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान छिलके रहित कपास के बिनौले की "खली" के निर्यात में अत्यधिक कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसका निर्यात बढ़ाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) (क) बिनौला निस्सारण का निर्यात जो वर्ष 1989-90 में 36,637 टन हुआ था, वर्ष 1991-92 में घट कर 1,912 टन रह गया।

(ख) भारतीय बिनौला निस्सारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगी नहीं रह गया है। इसके कई कारण हैं जिनमें ये शामिल हैं:— बिनौले की ऊंची घरेलू लागत, ई ई सी की कीमतों में दीर्घकालीन गिरावट, एमलाटाक्सीन के संबंध में उनके कड़े विनियमन और चीन, अर्जेंटीना तथा केन्या से प्रतिस्पर्धा।

(ग) सरकार ने निर्यात के संबंध में नीतिगत वातावरण में सुधार लाने के लिए पहले ही अनेक उपाय किए हैं। इन्हें नई आयात निर्यात नीति द्वारा और भी आगे सुदृढ़ कर दिया गया है जो कि दिनांक 1 अप्रैल, 1992 से पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगी।

रूस को चमड़े के आयात हेतु ऋण

2639. डा० रवि मल्लू: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूस ने चमड़े के आयात हेतु ऋण मांगा है जैसाकि 28 जून, 1992 के "इकनामिक टाइम्स" के समाचार में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ग) चमड़े के आयात हेतु ऋण के लिए रूस का अनुरोध प्राप्त हुआ है। सरकार इस अनुरोध पर विचार कर रही है।

शिक्षित बेरोज़गार युवकों के लिए कॉफी बोर्ड योजना

2640. डा० बी० राजेश्वरनः क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कॉफी बोर्ड देश के शिक्षित बेरोज़गार युवकों के लिए कॉफी केन्द्र खोलने को प्रोत्साहित करने की किसी योजना पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में कॉफी बोर्ड द्वारा क्या प्रोत्साहन और सहायता दिये जाने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ग) कॉफी बोर्ड ने देश के विभिन्न भागों में लिक्विड कॉफी सेंटर खोलने के लिए एक योजना शुरू की है। ऐसे केन्द्र खोलने के लिए निजी उद्यमकर्ताओं को बोर्ड की तरफ से बिना किसी प्रकार की वचनबद्धता के विशेषाधिकार आधार पर प्रोत्साहित किया जा रहा है।

इसमें दी जाने वाली सहायता काफी बनाने, काफी केन्द्र प्रबन्ध, काफी को भूने तथा पीसने, पैकिंग करने आदि के सम्बन्ध में मुफ्त प्रशिक्षण देने तक ही सीमित है। इस योजना में यह भी व्यवस्था है, उन उद्यमकर्ताओं को स्वयं काफी केन्द्र स्थापित कर लेने के बाद काफी पाउडर बेचने के लिए एजेन्सी दी जाएगी।

[हिन्दी]

राज्य सड़क परिवहन निगमों को सहायता

2641. श्री देवी बक्स सिंहः क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार राज्य सड़क परिवहन निगमों को प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता देती है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार विभिन्न राज्य सड़क परिवहन निगमों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) केन्द्र सरकार, आर टी सी अधिनियम, 1950 के तहत स्थापित उन राज्य सड़क परिवहन निगमों को पूंजीगत ऋण सहायता प्रदान करती है जो निवल घाटे में नहीं चल रही हैं अथवा "ब्रेक-ईवन प्वाइंट" पर चल रही हैं।

(ख) ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

1989-90	लाख रु०
1. आंध्र प्रदेश	80.00
2. गुजरात	840.00
3. कर्नाटक	140.70
4. महाराष्ट्र	465.80

5.	उड़ीसा	39.40
6.	राजस्थान	159.70
7.	उत्तर प्रदेश	474.40
1990-91		लाख रु०
1.	गुजरात	1425.00
2.	केरल	30.70
3.	महाराष्ट्र	195.30
4.	राजस्थान	349.00
1991-92		लाख रु०
1.	गुजरात	372.50
2.	कर्नाटक	400.00
3.	मध्य प्रदेश	156.80
4.	राजस्थान	70.70

[अनुवाद]

सी०एस०डी० (आई) कैटीनें

2642. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री: क्या. रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी०एस०डी० (आई) कैटीनों में स्थानीय रूप से खरीदी गई ऐसी वस्तुएं बेची जा रही हैं जिन्हें ये सी०एस०डी० (आई) मुम्बई ने मंजूरी नहीं दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सेवानिवृत्त सिविल कर्मचारियों को भी यह सुविधा उपलब्ध नहीं दी जाती है जबकि सेवानिवृत्त सैनिकों को यह सुविधा दी गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सेवानिवृत्त सिविल कर्मचारियों को कैटीन सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो कब तक ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (च) कैटीन स्टोर्स विभाग का मुख्य उद्देश्य सैनिकों को अच्छी-किसम की उपभोक्ता वस्तुएं उनकी ड्यूटी के स्थान पर उचित दरों पर और जहां तक संभव हो बाजार दरों से कम मूल्य पर उपलब्ध करवाना है। कैटीन स्टोर्स विभाग द्वारा इन मदों की सप्लाई यूनिट द्वारा चलाई जा रही कैटीनों के माध्यम से की जाती है। यूनिट द्वारा चलाई जा रही कैटीनों को सामान्यतः स्थानीय मदों को खरीदकर बेचने की अनुमति नहीं है। यूनिट द्वारा चलाई जा रही कैटीनों में केवल वही मदें बेची जाती हैं जो कैटीन स्टोर्स विभाग, बम्बई द्वारा खरीदी गई हों। यूनिट द्वारा चलाई जा रही कैटीनों से रक्षा सेवा प्राक्कलनों से वेतन पाने वाले

सेवारत सिविलियन कर्मचारियों को भी शराब को छोड़कर, अन्य मदों की खरीद की अनुमति है। सेवानिवृत्त सेना के कार्मिकों को सेवा के दौरान उनके द्वारा किए गए त्याग के सम्मान-स्वरूप कैंटीन सुविधाओं का पूरा-पूरा लाभ उठाने की अनुमति है। आधारभूत सुविधाओं की कमी और धन के अभाव के कारण रक्षा सेवा प्राक्कलन से ज़ेहन पाने वाले सेवानिवृत्त सिविलियन कर्मचारियों को ये कैंटीन सुविधाएं उपलब्ध करना यवहार्य नहीं पाया गया है। अतः सेवानिवृत्त रक्षा सिविलियन कर्मचारियों को इस समय ये सुविधाएँ उपलब्ध करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय स्टेट बैंक और कैन बैंक म्यूचुअल फंड

2643. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय स्टेट बैंक और कैन बैंक म्यूचुअल फंड के अन्तर्गत योजनाओं की कुल सम्पत्ति का वर्तमान मूल्य कितना है;

(ख) म्यूचुअल फंड की इन योजनाओं के अन्तर्गत अकार्यशील पूंजी की प्रतिशतता कितनी है; और

(ग) इन योजनाओं के अन्तर्गत निवेश मूल्य में होने वाले घाटे के लिए क्या प्रावधान किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) भारतीय स्टेट बैंक और कैन बैंक म्यूचुअल फण्डों के अधीन विभिन्न स्कीमों की निवल सम्पत्ति मूल्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) भारतीय स्टेट बैंक म्यूचुअल फण्ड की स्कीमों के अधीन अकार्यशील पूंजी की प्रतिशतता नगण्य है। कैन बैंक म्यूचुअल फण्ड की किसी भी स्कीम के अन्तर्गत अकार्यशील पूंजी नहीं है।

(ग) कैन बैंक म्यूचुअल फण्ड ने विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत निवेश मूल्यों में किसी प्रकार के घाटे को पूरा करने के लिए 6.45 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है।

विवरण

भारतीय स्टेट बैंक और कैन बैंक म्यूचुअल फण्डों की विभिन्न स्कीमों की निवल सम्पत्ति मूल्यों के बारे में उल्लिखित विवरण

भारतीय स्टेट बैंक म्यूचुअल फण्ड

(रुपए)

स्कीम	अंकित मूल्य	निवल सम्पत्ति मूल्य (6.7.1992 तक की स्थिति)
एम०आर०आई०एस०—87	500.00	829.83
एम०आर०आई०एस०—89	100.00	133.00
एम०आर०आई०एस०—90	100.00	121.28

स्कीम	अंकित मूल्य	निवल सम्पत्ति मूल्य (6.7.1992 तक की स्थिति)
एम०एम०आई०एस०—89	100.00	122.22
एम०एम०आई०एस०—91	100.00	121.75
मैगनम ट्रिपल	100.00	111.39
एम०टी०एस०एस०—88 / 89	100.00	220.25
एम०टी०एस०एस०—90	100.00	124.65
एम०ई०एल०एस०—91	100.00	201.81
उपहार	100.00	101.52
एम०एम०एस०	10.00	19.24
मैक्स	10.00	11.43

केन बैंक म्यूचुअल फण्ड

स्कीम	अंकित मूल्य	निवल सम्पत्ति मूल्य (30.6.1992 तक की स्थिति)
केन शेयर	10.00	19.10
केन स्टाक	100.00	135.10
केन ग्रोथ	10.00	18.40
केन डबल	10.00	16.95
केन-80 ग ग(90)	10.00	16.10
केन स्टार	10.00	15.25
केन पेप (91)	10.00	15.12
बोनस	10.00	17.83
केन प्रीमियम	1,00,000.00	1,28,820.60
केन ट्रिपल	10.00	नई स्कीम
केन पेप (92)	10.00	नई स्कीम

संसद सदस्यों से पत्र

2644. श्री राम टड्डल चौधरी: क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत 6 माह के दौरान इनके मंत्रालय को संसद सदस्यों से कुल कितने पत्र/अभ्यावेदन/ज्ञापन प्राप्त हुए;

(ख) कितने मामलों में पत्र प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर प्राप्ति-सूचना भेज दी गई है और कितने मामलों में अभी तक अंतिम उत्तर नहीं दिए गए हैं; और

(ग) 15 दिन के अन्दर प्राप्ति-सूचना और तीन महीने के अंदर अन्तिम उत्तर न भेजे जाने के क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) पिछले छह मास के दौरान मंत्रालय द्वारा संसद सदस्यों से 232 पत्र/अभ्यावेदन/ज्ञापन प्राप्त किए गए हैं।

(ख) और (ग) लगभग सभी मामलों की प्राप्ति सूचना 15 दिन के भीतर भेज दी गई थी और 126 मामलों में अभी तक अन्तिम उत्तर नहीं दिए गए हैं। इस मंत्रालय का सदैव प्रयास रहा है कि संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों की प्राप्ति-सूचना 15 दिन के भीतर और 3 मास के भीतर अन्तिम उत्तर भेज दिया जाए। वर्तमान अनुदेशों के अनुसार संसद सदस्यों के पत्रों का उत्तर देने के कार्य को पूर्विकता दी जाती है। ऐसे मामलों के निपटारे को उच्चतम स्तर पर मानीटर किया जाता है और जहां आवश्यक हो उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है।

पश्चिम बंगाल में टी ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया के चाय बागानों का प्रबन्धन बदलना

2645. श्री जितेन्द्र नाथ दास: क्या वाणिज्य मंत्री 24 अप्रैल, 1992 के तारांकित प्रश्न सं० 756 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल स्थित टी ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया के चाय बागानों का प्रबंधन वेस्ट बंगाल टी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड को सौंपने के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

नाडकर्णी समिति की रिपोर्ट

2646. डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्दमः

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रहीः

डा० डी० वेंकटेश्वर रावः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बांडों तथा यूनियों के व्यापार में एक विशिष्ट प्रणाली की सिफारिश करने के लिए श्री एस० एस० नाडकर्णी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(घ) यदि हां, तो समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो समिति अपनी रिपोर्ट कब तक दे देगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में श्री एस० एस० नाडकर्णी, अध्यक्ष, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की अध्यक्षता में सरकारी क्षेत्र के बांडों और म्यूचुअल फण्डों की यूनियों में व्यापार करने संबंधी एक समिति गठित की है, जो अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी क्षेत्र के बांडों और म्यूचुअल फण्डों की यूनियों में लेन-देनों से संबंधित विद्यमान व्यापार करने की पद्धतियों की जांच करेगी और बुकिंग लेन-देनों की वैकल्पिक विशिष्ट प्रणाली की इन पद्धतियों और औपचारिकताओं में सुधार करने की सिफारिश करेगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) संपावना है कि समिति अपनी रिपोर्ट मध्य-अगस्त, 1992 तक प्रस्तुत कर दे।

राज्यों की ओवरड्राफ्ट स्थिति

2647. प्रो० के० वी० थॉमसः क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 जुलाई, 1992 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य की ओवरड्राफ्ट स्थिति क्या है;

(ख) क्या गत एक वर्ष के दौरान किसी राज्य को ओवरड्राफ्ट सुविधा बंद कर दी गई थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोटदुखे): (क) से (ग) विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) 1 जुलाई, 1992 की स्थिति के अनुसार आठ राज्य भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अपने खातों में ओवरड्राफ्ट में रहे जैसाकि नीचे दिया गया है:-

राज्य	ओवरड्राफ्ट की राशि (करोड़ रुपए में)
1. बिहार	43.64
2. गुजरात	60.08
3. हिमाचल प्रदेश	24.04
4. मध्य प्रदेश	20.96
5. मणिपुर	3.25
6. नागालैण्ड	3.59
7. त्रिपुरा	0.07
8. उत्तर प्रदेश	24.60

(ख) और (ग) ओवरड्राफ्ट विनियमन स्कीम के अन्तर्गत, किसी भी राज्य सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ सात लगातार कार्य दिवसों से अधिक समय तक ओवरड्राफ्ट में रहने की इजाजत नहीं है। यदि राज्य सरकार के खाते में ओवरड्राफ्ट सात लगातार कार्य दिवसों से अधिक समय तक बना रहता है तो भारतीय रिजर्व बैंक ओवरड्राफ्ट पूरा होने तक के लिए राज्य सरकार के खाते से भुगतान करना बंद कर देता है। पिछले एक वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा की राज्य सरकारों के खातों से भुगतान करना रोक दिया गया था क्योंकि उनके ओवरड्राफ्ट सात लगातार कार्य दिवसों से अधिक समय तक बने रहे थे और बाद में ओवरड्राफ्ट की राशि पूरी होने के बाद इन राज्य सरकारों के खातों से भुगतान पुनः शुरू कर दिया गया था।

रक्षा उत्पादन इकाइयों का उपयोग

2648. डा० वसंत पवार: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्ण क्षमता से चल रहे रक्षा उत्पादन इकाइयों तथा अपनी पूरी क्षमता का उपयोग न करने वाली इकाइयों की संख्या कितनी-कितनी है; और

(ख) क्या सरकार का विचार अपनी क्षमता का कम उपयोग कर रही इन इकाइयों को उन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सेवा में लगाने का है जिन्हें अतिरिक्त श्रम शक्ति की आवश्यकता है?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार): (क) कुछ रक्षा उत्पादन यूनिटों में उत्पादन के कतिपय क्षेत्रों में इतना कार्यभार उपलब्ध नहीं है कि पूर्ण क्षमता का उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। इस संबंध में और अधिक ब्यौर प्रकट करना लोकहित में न होगा।

(ख) रक्षा उत्पादन यूनिटें अपनी उपलब्ध अतिरिक्त क्षमताओं के उपयोग को ध्यान में रखते हुए गैर-रक्षा क्षेत्रों (जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिटें भी शामिल हैं) से वैकल्पिक कार्य प्राप्त करने का प्रयास कर रही हैं।

[हिन्दी]

व्यापार समझौते

2649. प्रो० रासा सिंह रावत: क्या वाणिज्य मंत्री उन देशों के नाम बताने की कृपा करेंगे कि जिनके साथ केन्द्रीय सरकार ने पिछले वर्ष के दौरान नये व्यापारिक समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं और उन समझौतों की शर्तों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) वर्ष 1991 के दौरान, भारत ने चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया तथा उजबेकिस्तान के साथ व्यापारिक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इन देशों के साथ किए गए व्यापार करार में सन्तुलित आधार पर अपरिवर्तनीय भारतीय रुपयों में व्यापार का प्रावधान है।

वर्ष 1991 के दौरान नेपाल के साथ भी एक व्यापार संधि पर हस्ताक्षर किए गए। अन्य बातों के साथ-साथ, इस संधि में दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार पर टैरिफ रियायतों, रियायती सीमाशुल्कों आदि का प्रावधान है।

[अनुवाद]

समुद्री उत्पाद का निर्यात

2650. श्री बी० एस० विजयराघवन: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या हाल ही में केरल से समुद्री उत्पाद के निर्यात में भारी गिरावट आई है; और
(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आई० एन० एस० विक्रान्त का आधुनिकीकरण

2651. श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई० एन० एस० विक्रान्त की नौसेना की गोदी मुम्बई में आधुनिकीकरण और पुनः फिटिंग की प्रक्रिया चल रही है;

(ख) यदि हां, तो इस पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी; और

(ग) इस कार्य के कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय आवास बैंक (स्वैच्छिक जमा) योजना के अंतर्गत संग्रहण

2652 श्री प्रवीन डेका: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समाज के कमजोर वर्गों के लिए मकानों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक (स्वैच्छिक जमा) योजना, 1991 के अंतर्गत जमा की गई राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान किए गए धनराशि के नियतन तथा जारी किये जाने तथा वर्ष 1992-93 के लिए निर्धारित की गई राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अब तक कितने मकानों का निर्माण किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) (क) राष्ट्रीय आवास बैंक (स्वैच्छिक जमा) योजना, 1991 के तहत एकत्रित राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) योजना के तहत एकत्रित राशि का 40% गंदी बस्तियों की सफाई और कम लागत के मकानों पर वित्तपोषण के लिए एक विशेष निधि में जमा किया जाता है। राष्ट्रीय आवास बैंक उक्त प्रयोजन के लिए परियोजनाओं के वित्तपोषण और धन के आबंटन हेतु मार्गनिर्देश तैयार करेगा और तदुपरान्त वे धन का उपयोग करेंगे।

विवरण

राष्ट्रीय आवास बैंक की स्वैच्छिक जमा योजना, 1991 के तहत एकत्रित राशि

क्रम संख्या	राज्य का नाम	जमा राशि (करोड़ रुपए में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	5.02
2.	असम	0.51
3.	बिहार	3.61
4.	गोआ	1.33
5.	गुजरात	6.57
6.	हरियाणा	0.60
7.	हिमाचल प्रदेश	0.68
8.	कर्नाटक	8.28
9.	केरल	4.77
10.	मध्य प्रदेश	2.15
11.	महाराष्ट्र	36.09
12.	मेघालय	0.45
13.	नागालैंड	0.01

क्रम संख्या	राज्य का नाम	जमा राशि (करोड़ रुपए में)
14.	उड़ीसा	2.84
15.	पंजाब	5.72
16.	राजस्थान	1.71
17.	तमिल नाडु	12.87
18.	उत्तर प्रदेश	17.93
19.	पश्चिम बंगाल	22.13
20.	निकोबार अंदमान द्वीपसमूह	0.01
21.	चंडीगढ़	0.38
22.	दमन एवं दीव	0.27
23.	दिल्ली	19.57
24.	पांडिचेरी	0.01
जोड़		153.51

कोचीन पत्तन के शिपिंग चैनल को गहरा करना

2653. श्री रमेश चेत्रितला: क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या कोचीन पत्तन के शिपिंग चैनल को गहरा करने का कोई प्रस्ताव है; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) जी, नहीं। कोचीन पत्तन के नौवहन चैनल को गहरा करने के लिए कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

- (ख) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटकों और अनिवासी भारतीयों द्वारा सीमाशुल्क का भुगतान

2654. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत आने वाले पर्यटकों और अनिवासी भारतीयों को सीमाशुल्क चुका कर विदेशी माल लाने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या वे लोग सीमाशुल्क का भुगतान भारतीय रुपयों में कर रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे शुल्कों का भुगतान केवल विदेशी मुद्रा में करने को अनिवार्य बनाने का है ताकि देश में विदेशी माल लाने पर रोक लगायी जा सके; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) यात्रियों (पर्यटकों और अनिवासी भारतीयों सहित) को संगत असबाब नियमों के उपबंधों के अधीन सीमाशुल्क चुकाकर विदेशी माल लाने की अनुमति दी गयी है।

(ख) सोने को छोड़कर, जिस पर शुल्क की अदायगी विदेशी मुद्रा में की जानी होती है, यात्रियों को अन्य वस्तुओं पर शुल्क की अदायगी विदेशी मुद्रा अथवा भारतीय मुद्रा में करने की छूट दी गई है।

(ग) और (घ) इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में कपड़े का उत्पादन

2655. श्री गया प्रसाद कोरी: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कपड़े के कुल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का हिस्सा कितना है;

(ख) उत्तर प्रदेश में इस समय राष्ट्रीय कपड़ा निगम की कितनी कपड़ा मिलें कार्य कर रही हैं; और

(ग) उत्तर प्रदेश में इस समय कितनी कताई मिलें कार्यरत हैं और इन मिलों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कुल कितनी मात्रा में कपड़े का उत्पादन किया गया है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) वर्ष 1991-92 के दौरान मिल क्षेत्र द्वारा देश में निर्मित कुल कपड़ा लगभग 2368 मिलियन मीटर था तथा उसमें उत्तर प्रदेश का अंशदान 99.4 मिलियन मीटर था जो कि लगभग 4.2 प्रतिशत बनता है।

(ख) 31 मार्च, 1992 की स्थिति अनुसार उत्तर प्रदेश में एन टी सी के अधीन 15 वस्त्र मिलें हैं।

(ग) उत्तर प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान कताई मिलों की संख्या तथा इन मिलों द्वारा निर्मित कुल मात्रा निम्नोक्त अनुसार है:—

वर्ष	कताई मिलों की संख्या	निर्मित कुल मात्रा (मिलियन कि० ग्रा०)
1989-90	39	116.99
1990-91	40	127.52
1991-92	42	106.33

[अनुवाद]

तिरुपुर (तमिलनाडु) में निटवीयर गारमेन्ट्स टेक्नालोजी इन्स्टीट्यूट की स्थापना

2656. श्री सी० के० कुप्पुस्वामी: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तिरुपुर, तमिलनाडु में निटवीयर गारमेन्ट्स फैशन टेक्नालोजी इन्स्टीट्यूट की स्थापना करने का है, ताकि तिरुपुर के हौजरी निर्यातक अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए नया डिजाइन तैयार कर सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) से (ग) तिरुपुर में निटवीयर गारमेंट फैशन टेक्नालोजी इन्स्टीट्यूट की स्थापना करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। फिर भी अप्रैल निर्यात संवर्धन परिषद ने निटवीयर मर्चें के निर्यातकों को प्रौद्योगिकीय सहायता प्रदान करने के लिए तिरुपुर में एक अप्रैल प्रशिक्षण तथा डिजाइन केन्द्र की स्थापना की है।

पटसन के बोरो के इस्तेमाल फिर से आरम्भ कराया जाना

2657. श्री प्रतापराव बी० भोंसले: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पटसन बोरो के इस्तेमाल पर लगाये गये प्रतिबंध को समाप्त करने के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में इस बीच कोई कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) से (घ) पटसन पैकिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत खाद्यान्न, चीनी और ठर्वरक के 100 प्रतिशत तथा सीमेंट के 65-70% तक के उत्पादन की पैकिंग पटसन की सामग्री में आरक्षित करने के बारे में जारी आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय सड़कों के विकास के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय की गई धनराशि

2658. श्री के० प्रधानी: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक महत्व की सड़कों के विकास के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी धनराशि खर्च की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): यद्यपि आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य सरकारों को निधियां, अन्तर्राष्ट्रीय अथवा आर्थिक महत्व की सड़कों के विकास के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता कार्यक्रम के तहत अनुमोदित कार्यों पर पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके द्वारा

किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए जारी की गई थीं जबकि कोई भी अनुमोदित परियोजना उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्यों की सीमा पर नहीं पड़ती।

[हिन्दी]

क्यूबा को चावल का निर्यात

2659. डा० डी० खेंकटेश्वर रावः

श्री संतोष कुमार गंगवारः

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने क्यूबा को चावल का निर्यात करने के संबंध में निर्णय ले लिया है;
- (ख) यदि हां, तो चावल की कितनी मात्रा का निर्यात करने का विचार है और तत्संबंधी शर्तें क्या हैं; और
- (ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्रशीद): (क) से (ग) सरकार ने क्यूबा को वाणिज्यिक आधार पर 10,000 मीट्रिक टन चावल उपलब्ध करने का निश्चय किया है।

भारत और रूस के बीच बैंकिंग लेनदेन डालर में करने हेतु समझौता

2660. श्री एन० जे० राठवा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार और रूस के बीच बैंकिंग लेनदेन अमरीकी डालर में करने के संबंध में कोई समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह समझौता किस तारीख को किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) और (ख) भारत सरकार और रूस संघ की सरकार के बीच 1992 में व्यापारिक करोबार और भुगतानों के विषय पर 22.2.92 को एक नयाचार पर हस्ताक्षर हुए। नयाचार में, नयाचार के परिशिष्ट I और II में विनिर्दिष्ट वस्तुओं की सूची के संबंध में एक केन्द्रीयकृत निपटान प्रणाली के माध्यम से संतुलित आधार पर प्रभावित होने वाले व्यापार का उल्लेख है। नयाचार में भुगतान की तारीख को भारतीय रुपए और निर्दिष्ट मुद्रा के बीच भारत में प्रचलित विनिमय दर के अनुसार भारतीय रुपयों में किए जा रहे भुगतानों के साथ मुक्त परिवर्तनीय अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राओं के मूल्य वर्ग दिए गए हैं। भारत में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंध प्रणाली के लागू होने के फलस्वरूप, नयाचार की केन्द्रीयकृत निपटान प्रणाली के अन्तर्गत व्यापार को सरल बनाने के लिए स्थापित किए गए बैंक खातों को अमरीकी डालरों में भी बनाए रखने का निर्णय लिया गया था। भारत और रूस के बीच इसे क्रियात्मक रूप देने के लिए 10.6.92 को एक बैंकिंग करार पर हस्ताक्षर किए गए।

नयाचार की केन्द्रीयकृत निपटान प्रणाली के दायरे से बाहर, भारत और रूस के बीच सभी प्रकार के व्यापार के लिए भुगतान किसी भी मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा अथवा मान्यताप्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक सहयोग के किसी भी रूप में करना होगा।

[अनुवाद]

‘येन बांड’

2661. श्री गुरुदास कामत: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान ने भारत को अपने बाजार में येन बांड जारी करने की अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) और (ख): अभी तक चार भारतीय ऋणकर्ताओं ने 14 निर्गमों के माध्यम से जापानी बाण्ड बाजार में सरकारी तथा निजी बाण्ड दोनों ही प्रकार से निधियां जुटाई हैं। ये ऋणकर्ता भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई एफ० सी० आई०), भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (आई सी आई सी आई) और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (ओ एन जी सी) हैं। कुल 175 अरब जापानी येन की राशि जुटाई गई है।

छावनियों में चुनाव

2662. श्री सैयद शाहाबुद्दीन: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विभिन्न छावनियों में पिछली बार किस तारीख को चुनाव हुए थे;

(ख) छावनी बोर्डों में, छावनी-वार, निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है;

(ग) इन बोर्डों में पदेन सदस्यों की संख्या कितनी है और चालू वर्ष के लिए प्रत्येक बोर्ड के बजट का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रत्येक छावनी बोर्ड को सरकार द्वारा कितनी रज सहायता दी जाती है?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (घ) देश में 62 छावनियां हैं। 56 छावनियों के लिए आम चुनाव 2.2.1992 को आयोजित किए गए थे। देहरादून और फतेहगढ़ छावनियों के लिए आम चुनाव 12.4.1992 को कराए गए थे। अम्बाला छावनी बोर्ड के लिए चुनाव 9.8.1992 को कराए जाने हैं। प्रशासनिक कारणों से जम्मू और बादामी ब्राग छावनी बोर्डों का गठन क्रमशः 31.1.1992 और 27.4.1992 को एक वर्ष के लिए परिवर्तित रूप से कर दिया गया।

चुनाव की तारीखें, चुने गए सदस्यों की संख्या, पदेन और मनोनीत किए गए सदस्यों की संख्या और वर्ष 1991-92 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक छावनी को दिए गए सहायता अनुदान के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

जहां तक चालू वर्ष के लिए प्रत्येक छावनी बोर्ड के बजट का संबंध है, इस बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

क्रम सं०	छावनी का नाम	पिछले चुनाव की तारीख	चुने गए सदस्यों की संख्या	संख्या		साधारण सहायता विरोध सहायता	
				(क) पदेन सदस्य	(ख) मनोनीत सदस्य	अनुदान 91-92 (लाख रुपये में)	अनुदान 91-92 (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आगरा	02 फरवरी, 92	07	03	04	8.00	शून्य
2.	अहमदाबाद	"	07	03	04	शून्य	शून्य
3.	अहमदनगर	"	07	03	04	38.00	शून्य
4.	अजमेर	"	01	01	01	5.00	शून्य
5.	इलाहाबाद	"	07	03	04	शून्य	शून्य
6.	अलमोड़ा	"	01	01	01	0.17	शून्य
7.	अम्बाला	26.07.87*	07	03	04	शून्य	शून्य
8.	अमृतसर	02.02.92	04	03	01	शून्य	शून्य
9.	औरंगाबाद	"	07	03	04	1.60	शून्य
10.	बबीना	"	07	03	04	1.50	शून्य
11.	बकसरीह	"	01	01	01	1.90	शून्य
12.	बदामीबाग अब 27.4.92 को बदल गई	18.05.86	01	01	02	.50	शून्य
13.	बैरकपुर	02.02.92	07	03	04	30.00	शून्य
14.	बरेली	"	07	03	04	शून्य	शून्य
15.	बैलगांव	"	07	03	04	शून्य	शून्य
16.	कन्नौर	02.02.92	04	03	01	शून्य	शून्य
17.	चकरगता	"	01	01	01	15.00	3.90
18.	क्लेमेन्ट	"	05	03	02	35.25	2.18
19.	डगशाई	"	01	01	01	14.00	शून्य
20.	डलहौजी	"	01	01	01	12.68	शून्य
21.	दिल्ली	"	07	03	04	शून्य	शून्य
22.	देहरादून	12.04.92	07	03	04	34.00	शून्य
23.	देवतली	02.02.92	07	03	04	51.00	50.00
24.	धनापुर	"	07	03	04	24.45	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	देहू रोड	"	07	03	04	शून्य	शून्य
26.	फैजाबाद	"	04	03	01	27.00	शून्य
27.	फतेहगढ़	12.04.92	06	03	03	15.00	शून्य
28.	फिरोजपुर	02.02.92	07	03	04	67.80	शून्य
29.	जबलपुर	"	07	03	04	शून्य	शून्य
30.	जलापहाड़	"	01	01	01	11.00	शून्य
31.	झांसी	"	07	03	04	शून्य	शून्य
32.	जम्मू	18.05.86 (31.01.92 से बदल गई)	—	01	02	13.92	शून्य
33.	जालंधर	02.02.92	07	03	04	60.00	शून्य
34.	जतोष	"	01	01	01	14.00	शून्य
35.	काम्पटी	02.02.92	05	03	02	16.45	शून्य
36.	कानपुर	"	07	03	04	43.50	शून्य
37.	कसौली	"	04	03	01	24.20	शून्य
38.	किरकरी	"	07	03	04	शून्य	शून्य
39.	खयौल	06.12.87	05	03	02	25.00	शून्य
40.	लंडौर	02.02.92	01	01	01	18.67	7.92
41.	लैनसडाऊन	"	04	03	01	24.60	शून्य
42.	लेबाँग	02.02.92	01	01	01.00	13.00	शून्य
43.	लखनऊ	"	07	03	04	शून्य	शून्य
44.	मथुरा	"	04	03	01	शून्य	शून्य
45.	मेरठ	"	07	03	04	शून्य	शून्य
46.	महू	"	07	03	04	51.00	शून्य
47.	मोरार	"	07	03	04	शून्य	शून्य
48.	नैनीताल	"	01	01	01	11.10	शून्य
49.	नसीरुबाद	"	07	03	04	24.30	शून्य
50.	पंचमढ़ी	"	05	03	02	12.60	शून्य
51.	पुणे	"	07	03	04	शून्य	शून्य
52.	रामगढ़	"	07	03	04	25.00	शून्य
53.	रानीखेत	"	07	03	04	31.50	शून्य
54.	रुड़की	02.02.92	05	03	02	9.73	शून्य
55.	सेम बोमस मार्केट	"	07	03	04	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8
56.	सागर	"	07	03	04	शून्य	शून्य
57.	सिकन्दरबाद	"	07	03	04	शून्य	शून्य
58.	शाहजहांपुर	"	07	03	04	1.00	शून्य
59.	शिलोंग	"	05	03	02	9.00	शून्य
60.	सुबोधू	"	04	03	01	11.00	शून्य
61.	वाराणसी	"	07	03	04	14.40	शून्य
62.	वेलिंगटन	"	07	03	04	37.10	शून्य

गोवा में ऋणराशि-जमाराशि का अनुपात

2663. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 1992 को गोवा के राष्ट्रीयकृत बैंकों में कुल कितनी जमा-राशि थी; और

(ख) विभिन्न संस्थाओं को इन बैंकों की उक्त जमा-राशि में से कितनी धन-राशि ऋण के रूप में दी गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ख): 31 मार्च, 1992 के आंकड़े अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, दिसम्बर, 1991 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार गोवा में 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों की बकाया राशि और ऋण राशि क्रमशः 1154 करोड़ रुपए और 350 करोड़ रुपए थी।

पटसन आधुनिकीकरण कोष

2664. श्री सनत कुमार मंडल: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पटसन आधुनिकीकरण कोष योजनाओं की रूप रेखा क्या है; और

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इनमें से कितनी राशि का उपयोग पटसन उद्योग द्वारा किया गया है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) पटसन आधुनिकीकरण निधि योजना की धन राशि 150 करोड़ रु० है।

(ख) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने पिछले तीन वर्षों के दौरान पटसन आधुनिकीकरण निधि में से पटसन उद्योग को निम्नलिखित राशि वितरित की है:—

वर्ष	राशि(करोड़ रु०)
1989-90	8.41
1990-91	8.45
1991-92	5.84

दिल्ली परिवहन निगम को गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपना

2665. श्री गोपीनाथ गजपति: क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली परिवहन निगम को गैर सरकारी क्षेत्र को सौंपने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत-स्पेन व्यापार

2666. श्री सुबास चन्द्र नायक: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का विचार भारत स्पेन व्यापार बढ़ाने का है;
- (ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच किन-किन क्षेत्रों में यापार तथा संयुक्त उद्यम स्थापित किए गए हैं;
- (ग) भारत-स्पेन व्यापार के विस्तार हेतु पहचाने गए नए क्षेत्र कौन-कौन से हैं; और
- (घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) सरकार का यह प्रयास है कि भारत-स्पेन व्यापार का विस्तार किया जाए। भारत से स्पेन को होने वाले निर्यात के प्रमुख क्षेत्र ये हैं:— समुद्री उत्पाद, चमड़ा, चमड़ा उत्पाद और वस्त्र एवं हस्तशिल्प। स्पेन से आयात होने वाली प्रमुख मर्दों में रसायन, लोहा एवं इस्पात, अलौह धातुएं और इंजीनियरी माल शामिल हैं।

भारत-स्पेन संयुक्त उद्यम के कुछ क्षेत्र ये हैं—चमड़ा परिष्करण रसायन, सर्किट ब्रेकर और समुद्री उत्पाद।

(ग) और (घ) साफ्टवेयर, हाथ के औजारों, बिजली के स्विचगियरों और पम्पों तथा कन्शरों जैसी मर्दों का और अधिक निर्यात किए जाने की गुंजाइश है।

शेयर बाजार में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका

2668. श्री श्रवण कुमार पटेल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत चार महीनों के दौरान शेयर बाजार में अचानक उछाल के बाद तेजी से आयी मंदी को रोकने के लिए सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): वित्तीय संस्थाएं, सामान्य नियम के अनुसार, स्टॉक बाजार में अपने निवेशकों के दीर्घकालीन हित में धनराशियों को सावधानीपूर्वक लगाती हैं ताकि उससे यह सुनिश्चित हो सके कि निवेशक की निधि सुरक्षित रह सके, उसकी नकद परिसम्पत्ति बनी रहे और उसे प्रतिलाभ मिल सके। उक्त संस्थाएं बाजार की स्थिति के आधार पर और सभी संबंधित कारकों अर्थात् किसी कम्पनी का ट्रैक रिकार्ड, प्रतिशेयर आय, शेयर का उचित मूल्य, शेयर के उच्च और निम्न बाजार मूल्य, आदि को ध्यान में रखकर चयनात्मक रूप से खरीद और बिक्री का कार्य करती हैं।

भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए समूह बीमा योजना

2669. श्री हाराधन राय: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए समूह बीमा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या कितनी है; और

(ख) इस योजना के अंतर्गत अब तक निपटाए गए दावों की संख्या और राशि का राज्यवार और वर्ष ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) देश में भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत लाभभोगियों की अनुमानित संख्या 1.5 करोड़ है।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(शशि रुपयों में)

क्रम सं० राज्य	भूमिहीन खेतीहर मजदूर			शशि निपटार गप मामले							शशि निपटार गप मामले	
	शशि निपटार गप मामले 1989-90	शशि निपटार गप मामले 1988-89	(अनुमान)	6	7	8	9	10	11			
उत्तरी जोन												
1. हरियाणा	+	436		419		375		971				
2. हिमाचल प्रदेश	£	—		2		0		—				
3. जम्मू तथा कश्मीर	+	23		2		2		12				
4. पंजाब		400000		607		560		193				547
5. राजस्थान		200000		655		650		354				496
6. चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	+	2		0		160		323				
7. दिल्ली-I	+	\$		0		—		55				
7क. दिल्ली-II	+	\$		0		142		97				
उत्तरी जोन		600000	1723	1723000	1633	1633000	1226	1226000	2501	2548000		
जोड़:—												
पूर्वी जोन												
8. अरुणाचल प्रदेश	+	0		0		0		—				
9. असम	+	0		+		59		99				
10. बिहार		1800000	70	78		197		402				

T	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11.	बैकलास		£		£		0				
12.	सिन्धुस		£		£		0				
13.	यकीपुर	+	10		23		9				
14.	नगारीक		£		£		0				
15.	यरीस	400000	4269		6976		1398		2054		
16.	सिक्किम		£		£		£				
17.	सिपु	800000	64		5		28		14		
18.	पश्चिम बंगाल	+	\$		356		8146		3748		
19.	अन्धमान तथा निकेतार डीपलसूह		£		£		0				
		पूर्वी जोन: जोड़:—	4413	4413000	7438	7438000	10337	10337000	7136	6317000	
<hr/>											
मध्य जोन											
20.	मध्य प्रदेश	1200000	654		601		215		1359		
21.	उत्तर प्रदेश	1300000	983		716		787		941		
		मध्य जोन: जोड़:—	1637	1637000	1317	1317000	1002	1002000	2300	2446000	
<hr/>											
पश्चिमी जोन											
22.	केरल	100000	1808		1389		932		1247		
23.	तमिलनाडु	1300000	9158		5034		6245		11947		
24.	लघाट्टीप		£		£		0				
25.	पश्चिमी	30000	86		24		0				
		पश्चिमी जोन: जोड़:—	1430000	11052	11052000	6447	6447000	7177	7177000	13194	14255000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	दक्षिण मध्य जोन									
26.	अजय प्रदेश	675000	3641		2772		3689		7003	
27.	कनिष्क	900000	1863		2044		1773		2075	
	दक्षिण मध्य जोन:									
	जोड़:—	1575000	5504	5504000	4816	4316000	5462	5462000	9078	9173000
	पश्चिमी जोन									
28.	गोसा	7000	177		46		249		395	
29.	गुजरात	800000	4839		7986		9945		10953	
30.	मकराष्ट्र	+	—		589		2581		3103	
31.	दादरा और									
	नगर हवेली	3000	—		0		0		—	
32.	अण्डमान और	\$—	\$		\$		0		—	
	रिदु									
	पश्चिमी जोन:									
	जोड़:—	810000	5016	5016000	8621	8621000	12775	12775000	14451	14585000
	कुल जोड़:—	9915000*	29345	29345000	30272	30272000	37979	37979000	47841	49324000
	‡ पूर्णतः खोला क्षेत्र नहीं									
	* उपलब्ध नहीं									
	\$ अनुदेस जरी नहीं किए गए									
	• अनुमानित लाभ योगी 1.5 करोड़									

गुजरात में बैंकों द्वारा पूंजी निवेश

2670. डा० अमृतलाल कालिदास पटेल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों के शाखा विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत गुजरात के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान क्या लक्ष्य रखा गया था;

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रामीण बैंकों की शाखाएं खोलने के लिये उक्त अवधि के दौरान कितने लाइसेंस जारी किये हैं; और

(ग) वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक गुजरात में किया गया प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश उनके द्वारा किये गये राष्ट्रीय पूंजी निवेश के औसत की तुलना में कितना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के साथ-साथ समाप्त होने वाली अवधि के दौरान शाखा लाइसेंसिंग नीति (1985-90) के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा शाखाएँ खोलने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। तथापि, पहचान किए गए केन्द्रों की सूची के आधार पर गुजरात में शाखाएँ खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 151 केन्द्र और सरकारी क्षेत्र के बैंकों को 102 केन्द्र आबंटित किए हैं।

(ग) वर्ष 1990 के लिए गुजरात में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश तथा राष्ट्रीय औसत निवेश क्रमशः 327 रुपए और 249 रुपए था।

[हिन्दी]

आम का निर्यात

2671. श्रीमती भावना चिखलिया: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जहां अधिकतम मात्रा में आम का निर्यात किया जाता है; और

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान आम के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) अधिकतम मात्रा में आम का निर्यात संयुक्त अरब अमीरात को किया जाता है।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान आम के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नलिखित है:—

1990-91*	—	3122 लाख रुपया
1991-92**	—	3600 लाख रुपया

*स्रोत — डी जी सी आई एस

**स्रोत — निर्यातकों की विवरणियों पर आधारित अनन्तिम

[अनुवाद]

इंजीनियरिंग उद्योग द्वारा निर्यात

2672. श्री दत्तात्रेय बंडारू: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इंजीनियरिंग उद्योग की निर्यात उपलब्धियां क्या रहीं; और
(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इंजीनियरिंग सामान के निर्यात के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) पिछले दो वर्षों के दौरान इंजीनियरिंग उद्योग का निर्यात निम्नादित निम्नलिखित है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	मूल्य
1990-91	3443
1991-92	4855 (अनन्तिम)

स्रोत: डी जी सी आई एण्ड एस

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान इंजीनियरिंग सामान के निर्यात के लिए अनन्तिम तौर पर 5910 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

रुपए की परिवर्तनीयता

2673. श्रीमती गीता मुखर्जी:

श्री आनन्द रत्न मोर्य:

श्री जार्ज फर्नांडीज:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रुपए की आंशिक परिवर्तनीयता की नीति के व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार व्यापार हेतु रुपए को पूर्णरूप से परिवर्तनीय बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से सरकार द्वारा रुपए की आंशिक परिवर्तनीयता की नई प्रणाली को लगातार मानीटर किया जा रहा है। मानीटरिंग के परिणामों से पता चलता है कि प्रणाली ठीक प्रकार से कार्य कर रही है। व्यापार लेखे पर पूर्ण परिवर्तनीयता

के समय और उसकी गति देश के अन्दर प्राप्त की गई बृहत् आर्थिक स्थिरता, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वातावरण और अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों की दशाओं जैसे अनेक कारकों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाएगी।

संयुक्त उद्यमों के लिए दिशानिर्देश

2674. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी:

डा० डी० वेंकटेश्वर राव:

श्री माणिकराव होडल्या गावीत:

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों में संयुक्त उद्यमों हेतु दिशानिर्देश बनाने हेतु किसी समिति का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा नये दिशानिर्देशों की पूरी तरह से जांच कर ली गई है और इनकी शीघ्र ही घोषणा किये जाने की संभावना है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) ये दिशानिर्देश कितने सहायक सिद्ध होंगे?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्रिदि): (क) जी, हां।

(ख) नीति को शासित करने वाले विदेश विनियोजन के संबंध में सिफारिशें करने के लिए अध्यक्ष, एक्विजम बैंक की अध्यक्षता में व्यापार बोर्ड के एक उप-समूह का गठन किया गया था।

(ग) जी, हां।

(घ) समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ विदेश में संयुक्त उद्यमों से संबंधित अंतर-मंत्रालयीय समिति को अत्यधिक शक्तियां देने, आवेदन पत्रों पर समय-बद्ध रूप से कार्रवाई करने, विदेशी उद्यमों को अत्यधिक क्रियात्मक स्वतंत्रता देने, कुछ विशेष मामलों में स्वतः अनुमोदन और कार्यनिष्पादन की समीक्षा करने के लिए बेहतर व्यवस्था की सिफारिश की थी।

(ङ) से (छ) विदेश में संयुक्त उद्यमों तथा संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों की स्थापना करने संबंधी दिशानिर्देशों के संशोधन का मामला विचाराधीन है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों का निर्माण

2675. श्री गया प्रसाद कोरी: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1992-93 के दौरान उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितने पुल बनाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के कितने पुलों की मरम्मत हो रही है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के पुलों की मरम्मत पर हुए खर्च का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) वर्ष 1992-93 के दौरान उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर बनाए जाने वाले प्रस्तावित पुलों की संख्या छ: है।

(ख) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर इस समय मरम्मत किए जा रहे पुलों की संख्या तीन है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों की मरम्मत पर किए गए व्यय के ब्यौरे इस प्रकार हैं:—

वर्ष	राशि (लाख रु०)
1989-90	11.23
1990-91	19.00
1991-92	2.23

[अनुवाद]

मिग-21 का दुर्घटनाग्रस्त होना

2676. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितने मिग-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए;

(ख) इन दुर्घटनाओं के कारण हुई जान व माल की क्षति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार): (क) वर्ष 1989-90 से 1991-92 तक 30 मिग-21 वायुयान दुर्घटनाग्रस्त हुए।

(ख) मारे गये विमान चालकों की संख्या	14
मारे गये सिविलियन	शून्य
सैनिक सम्पत्ति की हानि	64.75 करोड़ रुपये
सिविलियन सम्पत्ति की हानि	2.43 लाख रुपये

(ग) जी, हां।

(घ) दुर्घटनाएं मानव (विमान चालक दल की) भूल तकनीकी खराबी, पक्षियों के टकराने, प्राकृतिक तथा संक्रियात्मक जोखिमों, आदि के कारण हुई।

(ङ) दुर्घटनाओं की संख्या न्यूनतम रखने का प्रयास एक निरन्तर चलती रहने वाली प्रक्रिया है। प्रत्येक दुर्घटना की जांच-अदालत द्वारा जांच पड़ताल की जाती है, जिसमें विशेषज्ञ शामिल होते हैं। जांच अदालत की सिफारिशों के आधार पर, ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। जब कभी कोई प्रतिकूल स्थिति या कमजोर क्षेत्र का पता चलता है तो उत्पादकों तथा प्रयोक्ताओं के विशेषज्ञों की सहायता से उसका विशेष रूप से संयुक्त अध्ययन किया जाता है ताकि समस्या की गहराई से जांच की जा सके और उसमें सुधार लाने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जा सके। उड़ान सुरक्षा के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए गठित एक उच्च स्तरीय समिति की सभी सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कर ली हैं तथा उन पर कार्रवाई भी पूरी कर ली गई है।

तमिलनाडु में कॉफी की खेती

2677. श्री सी० के० कुप्पुस्वामी: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कॉफी बोर्ड का विचार तमिलनाडु सरकार के सहयोग से तमिलनाडु के कोयम्बटूर और नीलगिरी जिलों में बड़े पैमाने पर कॉफी की खेती करने का है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) कॉफी बोर्ड का कोयम्बटूर या नीलगिरी में बड़े स्तर पर कॉफी बागान लगाने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, VIII वीं योजना अवधि के दौरान, परम्परागत क्षेत्रों, जिनमें तमिलनाडु भी आता है, में 10,000 हेक्टेयर (2,000 हेक्टेयर प्रतिवर्ष की दर से) क्षेत्र में खेती के सामान्य विस्तार का प्रावधान किया गया है।

उर्वरकों और फार्मास्यूटिकलों के निर्यात में भारत को अधिमान देना

2678. श्री प्रतापराव बी० भोंसले: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीकी सरकार ने भारत को उर्वरकों और फार्मास्यूटिकलों के निर्यात में किसी प्रकार का अधिमान न देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्रवाई की है अथवा करने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ग) संयुक्त राज्य अमरीका सरकार ने दिनांक 29 अप्रैल, 1992 को इस आशय की घोषणा की कि अमरीका को होने वाले 60 मिलियन डालर मूल्य के भारतीय निर्यात की जी एस पी योजना के तहत मिलने वाला शुल्क मुक्त व्यवहार देना बन्द कर दिया जाए। इस निर्यात में टैरिफ अनुसूची की सुमेलित प्रणाली के अध्याय 28-38 में विहित मुख्यतया मेषजों, रसायनों, उर्वरकों और संबद्ध उत्पादों को कवर किया गया है। जी एस पी लाभों का स्थगन दिनांक 19 मई, 1992 से प्रभावी किया गया। इस कार्यवाही के फलस्वरूप, प्रभावित उत्पादों का जब भारत से आयात होगा तब वे शुल्क मुक्त व्यवहार के पात्र नहीं रहेंगे। किन्तु, ऐसे उत्पादों पर परम मित्र राष्ट्र के टैरिफ लगेगे जो 0.5 प्रतिशत से लेकर 17.5 प्रतिशत तक होंगे।

भारत सरकार का यह दृष्टिकोण अमरीकी प्राधिकारियों को सूचित कर दिया गया था कि अमरीका द्वारा की

गई उक्त कार्यवाही नाजायज, असामयिक और अवांछित है। इस पर अमरीका की यह प्रतिक्रिया रही कि यदि भारत एकस्व-संरक्षण के विषय पर अमरीका की चिन्ताओं पर ध्यान देता है तो उक्त कार्यवाही रद्द की जा सकती है।

उड़ीसा के गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में कॉफी की खेती

2679. श्री के० प्रधानी: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने उड़ीसा में गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में कॉफी की खेती के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक उड़ीसा में कितने हेक्टेयर भूमि में कॉफी की खेती की जाएगी; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्रिद): (क) से (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कॉफी बोर्ड कॉफी के अन्तर्गत नए क्षेत्रों को लाने में तरजीह देने के बजाए उन वर्तमान कॉफी क्षेत्रों को समेकित किया जाए जो गैर-परम्परागत क्षेत्रों में हैं। किन्तु सम्बन्धित गैर-परम्परागत कॉफी उपजकर्ता राज्य सरकारों द्वारा चलायी गई सामाजिक, आर्थिक/एकीकृत ग्रामीण विकास/आदिवासी विकास परियोजनाएं यदि कोई हों, तो उनके अन्तर्गत कॉफी विस्तार की जरूरतों को पूरा करने के लिए बोर्ड ने सम्पूर्ण गैर-परम्परागत क्षेत्रों के वास्ते समग्र रूप से 5000 हेक्टेयर भूमि विस्तार के लिए एक नाममात्र लक्ष्य का प्रावधान किया है। इस 5,000 हेक्टेयर भूमि के नाममात्र लक्ष्य का राज्य वारनिर्धारण इसलिए नहीं किया गया है त्किकि गैर-परम्परागत कॉफी उपजकर्ता राज्यों में आरम्भ होने वाली ऐसी परियोजनाओं पर विचार करते समय लोचशीलता रखी जा सके।

केरल को 'नाबाई' द्वारा सहायता

2680. प्रो० के० वी० धामस: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा केरल को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दी जाने वाली धनराशि का सेक्टर-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबाई) राज्यों के सभी जिलों के लिए कृषि और ग्रामीण विकास हेतु संपाद्यता से जुड़ी ऋण योजनाएं (पी एल पी) तैयार करता है जो उपलब्ध क्षमता और आधारभूत सुविधाओं के विकास पर आधारित होती हैं। इन योजनाओं में स्थानीय आवश्यकताओं और संपादनाओं तथा विकास एजेंसियों से संबंध परिलक्षित होता है। बुनियादी (ग्राउन्ड) स्तर के ऋण का प्रयोजन-वार प्रवाह और केरल राज्य के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजनाबद्ध ऋण के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की अनुमानित पुनर्वित्त सहायता संलग्न विवरण में दी गई है। यह अनुमान नाबाई द्वारा तैयार की गई संपाद्यता से जुड़ी ऋण योजनाओं पर आधारित है।

विकास

बुनियादी ढर पर प्रयोजना-वार ऋण और केल के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1992-93 से 1996-97) के दौरान नब्बार्ड की अनुमानित पुनर्वित्त सहायता ।

प्रयोजन	बुनियादी ढर का ऋण (लाख रुपये) पुनर्वित्त									
	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
रघु सिंचार्ड	2793	3235	3441	3621	3817	2367	2594	2794	2992	3055
विद्युतीकरण	486	551	556	565	599	139	318	309	295	336
ग्राम विकास	1272	1568	1707	1852	1994	220	1262	1373	1489	1685
कृषि मशीनीकरण	761	938	1022	1877	1168	303	609	664	699	761
रुक्क प्रमि पर खेती	5732	6248	6500	6895	7198	3000	5003	5213	5529	5774
डेरी विकास	799	2001	2089	2173	2265	811	1584	1652	1721	1794
मत्स्यन (समुद्र)	416	550	616	646	683	135	423	474	497	527
मत्स्यन (अन्तर्देशीय)	257	382	407	435	468	55	300	318	340	357
पाखरण/विपणन यार्ड	22	43	44	44	44	—	32	33	33	33
वानिकी	5	9	9	9	9	—	8	8	8	8
बायोगैस	212	244	251	257	254	87	184	197	202	205
कुञ्जट पालन	445	300	541	503	621	600	397	429	462	493
पेड़/बकरी/सुअर पालन	227	311	328	341	358	25	245	261	269	283
गैर-कृषि क्षेत्र	34820	40531	43690	40075	49532	2849	9892	18799	13411	13641
अन्य	46	60	63	67	72	152	45	49	51	54
योग	49233	57163	61264	64648	69892	10768	22896	24573	36929	28923
इसमें से आईआरडीपी	3053	3134	3134	3134	3134	1950	2507	2507	2507	2507

केरल सरकार को ऋण

2681. श्री टी० जे० अन्जलोः: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) केरल सरकार द्वारा गत दो वर्षों में कितने ऋण की मांग की गई, और इसके क्या प्रयोजन थे;
 (ख) उपर्युक्त प्रत्येक वर्ष में राज्य सरकार को कितनी धनराशि स्वीकृत की गई;
 (ग) क्या स्वीकृत किया गया ऋण राज्य सरकार द्वारा मांगे गये ऋण से काफी कम था; और
 (घ) यदि हां, तो इसके या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे): (क) वर्ष 1990-91 के दौरान केरल सरकार ने नवें वित्त आयोग द्वारा यथा मूल्यांकित राज्य के समग्र राजस्व घाटे के एक भाग को पूरा करने के लिये 100 करोड़ रुपये के विशेष ऋण की मांग की थी। राज्य ने वर्ष 1991-92 के दौरान अपनी वित्तीय कठिनाइयों से निपटने के लिये मध्यम अवधि ऋण के रूप में 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त विशेष सहायता देने के लिये भी अनुरोध किया था।

(ख) से (घ) 1990-91 में किये गये अनुरोध पर इस मंत्रालय में विचार किया गया था तथा उसे स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि नवें वित्त आयोग का वह अभिमत जिसके अन्तर्गत विशेष ऋण मांगा गया था, एक सुझाव की तरह था न कि सिफारिश और उसे भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया था।

वर्ष 1991-92 में राज्य सरकार के 100 करोड़ रुपये के मध्यम अवधि ऋण के लिये अनुरोध को भी केंद्र की संसाधनों की भारी कमी के कारण स्वीकार नहीं किया गया था।

[हिन्दी]

जीवन बीमा निगम द्वारा पूंजी निवेश

2682. श्री एन० जे० राठवा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम की वर्ष 1992-93 में पूंजी निवेश की कौन-कौन सी विभिन्न योजनाएं हैं; और

(ख) प्रस्तावित पूंजी निवेश पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक/कम होगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) वर्ष 1992-93 के दौरान निवेश करने के लिए जीवन बीमा निगम की विभिन्न योजनाओं के नाम निम्नानुसार हैं:—

- (1) भारत सरकार प्रतिभूतियां,
- (2) राज्य सरकार प्रतिभूतियां,
- (3) भूमि विकास बैंक ऋणपत्र,
- (4) बिजली बोर्ड बांड,
- (5) राज्य वित्त निगम बांड,

(6) इसके अलावा जीवन बीमा निगम सामाजिक आवास योजनाओं के लिए राज्य सरकारों, शीर्ष सहकारी आवास वित्त समितियों, आवास बोर्डों, नगर पालिकाओं, जिला परिषदों, राज्य बिजली बोर्डों, राज्य

सड़क परिवहन निगमों, औद्योगिक एस्टेट्स, चीनी सहकारिताओं और निगमित क्षेत्र की कम्पनियों को भी ऋण देता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए निवेश नीचे दिए गए हैं:—

	(करोड़ रुपए)		
	1989-90	1990-91	1991-92
	4028	4841	6032

वित्त वर्ष 1992-93 के दौरान जीवन बीमा निगम वारा लगभग 7400 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

विधायिका और न्यायपालिका का कार्यकरण

2683. श्री बी० राज रविवर्मा: क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पहले की अपेक्षा अब विधायिका और न्यायपालिका में मतभेद की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं या उठाये जाने का विचार है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) से (ग) दल परिवर्तन के कारण निरर्हता से संबंधित प्रश्न पर विधायिका और न्यायपालिका के बीच संभावित टकराव का विवाद हाल ही में उत्पन्न हुआ है। ऐसे टकराव की किसी भी गुंजाइश से बचने की दृष्टि से सरकार, संविधान की दसवीं अनुसूची में अंतर्विष्ट दल परिवर्तन विरोधी विधि में उपयुक्त संशोधन करने के प्रश्न की समीक्षा कर रही है। इस संबंध में एक अपील प्राधिकरण का उपबंध करने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है। ब्यौर तैयार किया जा रहा है।

धन का अभाव

2684. श्री श्रवण कुमार पटेल:

श्री बसुदेव आचार्य:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1992-93 का बजट पारित होने के बाद अब तक घोषित कर राहत राशि कुल कितनी है;

(ख) क्या इसके फलस्वरूप धन का अभाव हुआ है और क्या सरकार इस वर्ष कुछ सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए पिछले वर्ष के स्तर पर भी बजट आबंटन बनाये रखने में असमर्थ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं अथवा किये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) वित्त विधेयक, 1992 के 14 मई, 1992 को

अधिनियमित हो जाने के बाद, 21 जुलाई, 1992 तक दी गयी कर राहतों की राशि एक पूरे वर्ष में सीमाशुल्क के संबंध में 162.42 करोड़ रुपये और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में 321.40 करोड़ रुपये है।

(ख) वर्ष 1991-92 (संशोधित अनुमान) और वर्ष 1992-93 (बजट अनुमान) के दौरान सामाजिक दृष्टि से कुछेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए किये गये बजट आवंटनों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(करोड़ रुपयों में)

क्षेत्र	1991-92 (संशोधित अनुमान)	1992-93 (बजट अनुमान)
स्वास्थ्य	525.31	560.29
परिवार कल्याण	866.60	1010.41
शिक्षा	1678.98	1725.17
महिला तथा बाल विकास	404.65	489.63
ग्रामीण विकास	3021.24	3113.24
कल्याण	507.13	559.18

उपर्युक्त आंकड़ों से यह पता चल जायेगा कि सरकार ऊपर बताये गये सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए वर्ष 1992-93 के बजट आवंटनों को पूर्ववर्ती वर्ष के स्तर तक बनाये रखने में सफल रही है।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

नये मांडवी पुल का निर्माण

2685. श्री हरीश नारायण प्रभु झांड्ये: क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोवा में मांडवी नदी पर नये पुल का निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और ठेकेदार पर इस कारण से हुई क्षति के मुआवजे के रूप में किये गये जुर्माने का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पुल को पूरा करने के लिए क्या संशोधित समय-सीमा निर्धारित की गई है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) और (ख) गोवा में मांडोवी नदी पर नया पुल पूरा होने वाला है।

(ग) पुल के पूरा होने के विलम्ब अक्टूबर, 1990 में स्पेन सं०—11 के साथ-साथ "सैटरिंग टूस" के टूट जाने के कारण हुआ। परिनिधारित क्षति के तौर पर ठेकेदार पर अभी तक कोई जुर्माना नहीं किया गया है।

(घ) इस पुल के पूरा होने का संशोधित समय दिसम्बर, 1992 है।

उत्तर प्रदेश में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का एकक

2686. श्रीमती भावना चिखलिया: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का एकक खोलने का है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की गाजियाबाद और कोटद्वार स्थित मौजूदा यूनिटों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में और कोई नई यूनिट खोलने की फिलहाल आवश्यकता नहीं है।

पटसन उद्योग का वैविध्यीकरण

2687. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी:

डा० डी० वेंकटेश्वर राव:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पटसन के उत्पादों में ढांचागत परिवर्तन लाने की दृष्टि से पटसन उद्योग के वैविध्यीकरण हेतु कई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये कदम पटसन उद्योग के कार्य निष्पादन के सुधार में किस हद तक सहायक हुए हैं;

(घ) वर्ष 1991-92 में पटसन उत्पादन के लिए कुल कितनी राशि निर्धारित की गई है;

(ङ) उपर्युक्त अवधि के दौरान पटसन के कुल उत्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(च) वर्ष 1992-93 के दौरान इसमें किस हद तक वृद्धि होने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) से (ग) सरकार ने पटसन उद्योग में विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं, पटसन और वस्त्र मिलों को सभी प्रकार के फाईबर और यार्न का इस्तेमाल करने की छूट, रियायती शुल्क पर मशीनों का आयात, रियायती उत्पाद शुल्क/उत्पाद शुल्क की छूट, विकेन्द्रीकृत क्षेत्र को पटसन यार्न/फैब्रिक की सप्लाय पर उत्पाद शुल्क की छूट, अनुसंधान व विकास कार्यों का वित्त पोषण तथा विविधीकृत पटसन उत्पादों के लिए बाजार सहायता। अनुसंधान व विकास संस्थानों से प्रौद्योगिकी का उद्यमियों को अन्तरण करने में सहायता प्रदान करने तथा पटसन क्षेत्र में विविधीकरण को नई दिशा तथा ध्रष्ट देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पटसन विविधीकरण केन्द्र की स्थापना भी की गई है।

इन उपायों से नई श्रृंखला के पटसन उत्पादों का विकास, उत्पादन तथा खपत करने में सहायता मिली है। इसलिए पटसन उद्योग उन वस्तुओं के उत्पादन पर निर्भर नहीं है जो परम्परागत रूप से अपनी पैकिंग में पटसन का प्रयोग करते हैं। इसलिए पटसन के अन्त-प्रयोग में कुछ स्थिरता आ गई है।

(घ) से (च) सरकार पटसन के सामान के उत्पादन के लिए पृथक रूप से निधियां निर्धारित नहीं करती है।

यह निवेश पटसन उद्योग द्वारा किया गया है। वर्ष 1991-92 में 12.78 लाख टन पटसन के सामान का उत्पादन हुआ। वर्ष 1992-93 के दौरान पटसन के सामान का उत्पादन, उसकी घरेलू तथा निर्यात बाजार में मांग की मात्रा पर निर्भर होगा।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश को सहायता

2688. श्री गया प्रसाद कोरी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक ने उत्तर प्रदेश को कितनी-कितनी धनराशि दी; और

(ख) इस पर लगाई गई ब्याज दर कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) 1989-90 से 1991-92 के दौरान योजनाबद्ध ऋण के तहत उत्तर प्रदेश राज्य में वाणिज्यिक बैंकों/राज्य सहकारी समितियों/भूमि विकास बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दी गई पुनर्वित्त सहायता की राशि निम्नलिखित है:

वर्ष	(करोड़ रुपए)	
	राशि	
1989-90	273.29	
1990-91	339.47	
1991-92	381.76	

इसी अवधि के दौरान योजनाबद्ध ऋण से भिन्न उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियों को नाबार्ड द्वारा दिए गए पुनर्वित्त का संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) नाबार्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए पुनर्वित्त पर प्रभारित वर्तमान ब्याज की दर संलग्न विवरण-II में दी गयी है।

विवरण-I

वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 (मई 1992 तक) के दौरान उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियों को नाबार्ड द्वारा उपलब्ध पुनर्वित्त की राशि को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए)

प्रयोजन	पुनर्वित्त की राशि					
	1989-90		1990-91		1991-92	
	सीमा	आहरण	सीमा	आहरण	सीमा	आहरण
1. मौसमी कृषि कार्य (तिलहन उत्पादन कार्यक्रम सहित (सहकारिता वर्ष)	346.07	300.87	381.85	278.05	449.20	349.86
2. सहकारी बुनकर समितियों के उत्पादन और विपणन कार्य (वित्तीय वर्ष)	10.35	10.08	10.35	10.33	—	—
3. धागे की खरीद और बिक्री (वित्तीय वर्ष)	4.00	11.49	2.65	5.30	—	—
4. रासायनिक उर्वरक (कलैण्डर वर्ष)	36.40	37.90	47.40	88.03	70.00	43.29
5. कुटीर और लघु उद्योगों के विपणन कार्य (वित्तीय वर्ष)	0.25	—	—	—	—	—
6. मध्यावधिक (अनुमोदित कृषि प्रयोजन) (कलैण्डर वर्ष)	2.69	0.73	1.73	1.29	—	0.30
7. मध्यावधिक (परिवर्तित) (सहकारिता वर्ष)	8.67	5.75	12.10	4.18	—	—
8. दीर्घकालिक कार्य (वित्तीय वर्ष)	18.77	18.77	11.88	11.88	—	—

विवरण-II

नाबार्ड द्वारा एस०सी०बी०/राज्य सरकार को प्रदान की गई पुनर्वित्त सहायता पर वसूल की गई वर्तमान ब्याज दरों को दर्शाने वाला विवरण

क. प्रदान किए गए पुनर्वित्त पर वसूल की गई ब्याज दरें

(I) एस०सी०बी०

1. मौसमी कृषि परिचालन (एस०ए०ओ०)	3% से 6% तक जो अपने निवेश पर निर्भर करता है।
2. फसलों का विपणन	बैंक दर (12%)
3. बुनकर समितियों की उत्पादन और विपणन गतिविधियां	बैंक दर से 2.5% अधिक
4. शीर्ष विपणन समिति की वसूली और उसके विपणन परिचालन	बैंक दर से 2.5% कम
5. शीर्ष/क्षेत्रीय विपणन समिति द्वारा धागे का व्यापार	बैंक दर (12%)
6. रसायन उर्वरकों का वितरण	बैंक दर से 1% अधिक
7. कुटीर और लघु उद्योगों के विपणन कार्य	बैंक दर से 2.5% कम
8. गैर-योजनाबद्ध मध्यावधि — सावधि ऋण	8.5%
9. मध्यावधि परिवर्तन ऋण	वही ऋण ब्याज दर जो एस० ए० ओ० से वसूल की जाती है।
(II) सहकारी ऋण संस्थाओं की शेयर पूंजी में अंशदान के लिए राज्य सरकारों को ऋण	6%

ख. योजनाबद्ध ऋण के लिए पुनर्वित्त पर वर्तमान ब्याज दरें

अंतिम ऋणकर्ता को सीमा का आकार	राष्ट्रीय बैंक की पुनर्वित्त पर ब्याज दर
(1) 25,000/- रुपए तक	6.5%
(2) 25,000/- रुपए से अधिक और 2 लाख रुपए तक	10.5%
(3) 2 लाख रुपए से अधिक	

अंतिम ऋणकर्ता को सीमा का आकार

राष्ट्रीय बैंक की पुनर्वित्त पर ब्याज दर

क. कृषि क्षेत्र

क. बंजर भूमि का विकास, वर्षा से सिंचित खेती (मुक्त कृषि), 100% निर्यातमुख कृषि परियोजनायें (चाय, काफी, रबड़ और मसालों को छोड़कर) और सहकारी समितियों/सरकारी क्षेत्र के निगमों द्वारा कार्यान्वित लघु सिंचाई योजनाएं 10.5%

ख. नार्बाड द्वारा पुनर्वित्त पोषित अन्य सभी योजनायें (अर्थात् उपर्युक्त श्रेणी क को छोड़कर) 12%

ख. गैर-कृषि क्षेत्र

क. 2 लाख रुपए से अधिक और 7.5 लाख रुपए तक 12%

ख. 7.5 लाख रुपए से अधिक 13.5%

दक्षिण अफ्रीका के साथ व्यापार सम्बन्ध

2689. श्री एन० जे० राठवा: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण अफ्रीका ने भारत के साथ व्यापार सम्बन्ध स्थापित करने तथा भारत में लघु और मध्यम क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम लगाने में गहरी रुचि दिखाई है;

(ख) क्या दक्षिण अफ्रीका के वाणिज्य और उद्योग मंत्री मई, 1992 में अपने शिष्टमंडल के साथ भारत आये थे;

(ग) यदि हां, तो उन्होंने व्यापार संबंध स्थापित करने तथा संयुक्त उद्यम लगाने के लिए किन-किन क्षेत्रों में गहरी रुचि दिखाई है;

(घ) क्या इस संबंध में सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस समझौते को कब से कार्यान्वित कर दिया जायेगा?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ङ) इस समय दक्षिण अफ्रीका के साथ व्यापार पर व्यापक रोक लगी है। दक्षिण अफ्रीका की सरकार के व्यापार तथा उद्योग विभाग के महानिदेशक डा० एस० जे० नाउडे की अन्य व्यक्तियों के साथ मई, 1992 में भारत की यात्रा इस बात को प्रमाणित करती है कि दक्षिण अफ्रीका ने भारत के साथ व्यापार में रुचि दिखाई है। यह यात्रा उन्होंने गैर-सरकारी तौर पर की थी। यह प्रतिनिधिमंडल भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल परिसंघ तथा एसोसिएटिड चैम्बर्स आफ कमर्स एण्ड इंडस्ट्री आफ इंडिया से मिला। यह यात्रा अन्वेषणात्मक स्वरूप की थी। तथापि, व्यापार रोक में कोई ढील न होने की वजह से व्यापार सम्बन्ध तथा संयुक्त उद्यम स्थापित करने का प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

यूनिट योजना 1964

2690. श्री राम नरेश सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आय कर अधिनियम की धारा 80-एल और 80-एम में हाल ही में किए गये परिवर्तनों का यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया की यूनिट योजना, 1964 पर विपरीत प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट को हाल ही में आयकर अधिनियम की धारा 80-ठ में किए गए परिवर्तन के अनुसरण में यूनिट स्कीम, 1964 के अन्तर्गत यूनिटों की मांग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की कोई प्रत्याशा नहीं है। तथापि, बजट 1990-91 में आयकर अधिनियम की धारा 80-ड में परिवर्तन के परिणामस्वरूप यूनिटों की पुनः बिक्री के माध्यम से निगमित क्षेत्र द्वारा भारी निकासी की गई थी। निगमित क्षेत्र को की गई ताजा बिक्रियों में भी गिरावट आई है।

(ख) आयकर अधिनियम की धारा 80-ठ और 80-ड में किए गए परिवर्तनों के अनुसरण में इस समय यूनिट स्कीम, 1964 में कोई परिशोधन करना परिकल्पित नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

लौंग और दालचीनी के आयात हेतु लाइसेंस

2691. श्री एन० जे० राठवा: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लौंग और दालचीनी के आयात लाइसेंस जारी करने के लिए आधार वर्ष के बारे में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इस बारे में अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा; और

(ग) निम्नतम आयात सीमा (रुपयों में) कितनी रखे जाने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ग) जी हां, इस संबंध में विस्तृत ब्यौरा वाणिज्य मंत्रालय की दिनांक 30.6.1992 की सार्वजनिक सूचना संख्या 23-आई टी सी (पी० एन)/92-97 में दिया गया है। इसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

रुई का निर्यात

2692. श्री माणिकराव होडल्या गावीत: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने भारतीय रुई निगम, महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में चालू वर्ष के लिए निर्यात क्रेटा के अन्तर्गत रुई की कितनी गांठें जारी की हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष भारतीय रुई निगम ने महाराष्ट्र और गुजरात में महाराष्ट्र एकाधिकार रुई खरीद योजना के अंतर्गत कितनी मात्रा में रुई की गांठों की खरीद की है;

(ग) क्या सरकार को निर्यात हेतु और अधिक रुई की गांठों की स्वीकृति के लिए महाराष्ट्र की ओर से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री(श्री अशोक गहलोत): (क) सरकार ने चालू कपास मौसम के दौरान निर्यात के लिए बंगाल देशी कपास की एक लाख गांठ रिलीज की है जो कि सभी निर्यातकों के लिए खुली रखी गई है। हाल ही में सरकार ने द्विपक्षीय करारों के परिप्रेक्ष्य में नेपाल, बंगलादेश और श्रीलंका जैसे हमारे कुछ पड़ोसी देशों की 30,000 गांठ तक की कपास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय कपास निगम को अनुमति दी है।

(ख) ब्यौरा निम्नोक्त अनुसार है:—

कपास मौसम	खरीदी गई मात्रा लाख गांठ में		
	सी सी आई	महाराष्ट्र परिसंघ	गुजरात परिसंघ
1989-90	12.43	20.92	0.47
1990-91	10.19	13.50	0.56
1991-92	9.99	10.63	0.25
(18-7-92 तक)			

(ग) जी हां।

(घ) सरकार ने घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय कीमत स्थिति को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र परिसंघ को कोई निर्यात कोटा रिलीज करने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

राज्यों को धनराशि का आवंटन

2693. श्री बापू हरि चौरै:

डा० असीम बाला:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आयकर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निगमित कर, सम्पत्तिकर और सम्पदा शुल्क के रूप में अर्जित की गई धनराशि का राज्य / संघराज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य / संघराज्य क्षेत्र को इसके हिस्से के रूप में दी गई राशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह बंटवारा किस आधार पर किया जाता है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री शान्तराम पोद्दुखे): (क) वर्ष 1989-90, 1990-91 और

1991-92 के दौरान आयकर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, निगम कर, धन कर और सम्पदा शुल्क से राज्य / संघ राज्य क्षेत्र-वार संग्रहण दशनि वाले विवरण संलग्न हैं (विवरण-I, II, III और IV)।

(ख) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान राज्यों को दिए गए आय कर संघ उत्पाद शुल्कों आदि के राज्य-वार हिस्से दशनि वाले विवरण संलग्न हैं (विवरण-V, VI और VII)।

(ग) आयकर और संघ उत्पाद शुल्क का बटवारा राज्यों के साथ किया जाता है। यह बटवारा वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक राज्य के लिए प्रतिशत हिस्सा वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो न केवल राज्य में संग्रह को हिसाब में लेता है अपितु जनसंख्या, निर्धनता अनुपात, प्रतिव्यक्ति आय आदि को भी हिसाब में लेता है। नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1990-95 की अवधि के लिए आयकर, बुनियादी उत्पाद शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क का प्रतिशत हिस्सा दशनि वाला विवरण संलग्न है (विवरण-VIII)।

विवरण-I

वर्ष 1989-90 के दौरान निगम कर, आयकर, सम्पदा शुल्क और धन कर से संग्रहण

(करोड़ रुपये)

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	निगम कर	आयकर	संपदा शुल्क	धन कर
आन्ध्र प्रदेश	97.27	196.56	0.18	5.39
अरुणाचल प्रदेश	—	1.56	—	—
असम	30.17	42.93	0.01	1.13
बिहार	2.62	130.41	—	0.90
गोवा	13.87	17.36	—	1.04
गुजरात	117.75*	400.29*	0.31	15.85
हरियाणा	23.20	60.14	0.03	1.43
हिमाचल प्रदेश	1.69	18.09	—	0.21
जम्मू व कश्मीर	6.29	13.40	—	—
कर्नाटक	99.99	252.29	0.34	9.96
केरल	31.93	120.76	0.28	3.29
मध्य प्रदेश	24.43	150.01	0.26	3.01
महाराष्ट्र	1820.09	1483.82	1.17	70.56
मणिपुर	0.15	6.08	—	0.04
मेघालय	0.87	5.18	—	0.17
मिजोरम	—	0.03	—	—
नागालैण्ड	0.05	4.45	—	0.03
उड़ीसा	—	47.01	0.02	0.33
पंजाब	84.50	123.76	0.13	5.94

* इन आंकड़ों में दादरा और नागर हवेली शामिल हैं।

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	निगम कर	आयकर	(करोड़ रुपए)	
			संपदा शुल्क	धन कर
राजस्थान	18.67	105.06(-)	0.02	2.25
सिक्किम	—	0.02	—	—
तमिलनाडु	244.18	380.24	0.84	18.03
त्रिपुरा	0.04	4.11	—	0.01
उत्तर प्रदेश	477.36	318.42	0.08	6.68
पश्चिम बंगाल	447.29	364.96	0.08	12.52
संघ राज्य क्षेत्र				
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.21	0.53	—	—
चंडीगढ़	11.47	27.94	—	0.79
दमन	उ०न०	उ०न०	—	—
दीव	उ०न०	उ०न०	—	—
दादरा और नागर हवेली	उ०न०	उ०न०	—	—
नई दिल्ली	617.95	495.24	0.56	18.84
पांडिचेरी	1.39	4.00	—	0.11
लक्षद्वीप	—	—	—	—

उ०न०=उपलब्ध नहीं

विवरण-II

वर्ष 1990-91 के दौरान निगम कर, आयकर, सम्पदा शुल्क और धन कर से संग्रहण
(करोड़ रुपए)

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	निगम कर	आयकर	सम्पदा शुल्क	धन कर
आन्ध्र प्रदेश	119.79	222.55	(-) 0.07	6.58
अरुणाचल प्रदेश	—	1.77	—	—
असम	25.87	46.77	0.03	1.42
बिहार	12.24	143.00	0.03	1.43
गोवा	19.36	20.13	—	1.88
गुजरात	63.39	405.12	(-) 0.01	16.78
हरियाणा	32.21	68.81	0.01	1.74
हिमाचल प्रदेश	1.65	16.58	—	0.30
जम्मू व कश्मीर	16.64	23.12	—	—

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	निगम कर	आयकर	सम्पदा शुल्क	धन कर
कर्नाटक	78.88	273.47	0.13	11.33
केरल	75.23	140.68	0.17	4.03
मध्य प्रदेश	28.96	159.44	0.28	4.18
महाराष्ट्र	2196.40	1576.62	0.77	90.16
मणिपुर	0.08	5.84	—	0.03
मेघालय	1.03	5.68	—	0.19
मिजोरम	—	0.02	—	—
नागालैंड	0.07	4.67	—	0.02
उड़ीसा	23.85	58.69	—	0.35
पंजाब	89.18	145.81	0.02	7.60
राजस्थान	40.81	113.10	0.15	3.46
सिक्किम	0.11	0.06	—	—
तमिलनाडु	283.23	423.42	0.41	25.43
त्रिपुरा	0.05	4.02	—	0.23
उत्तर प्रदेश	119.52	345.35	0.15	8.72
पश्चिम बंगाल	526.06	423.26	0.12	15.91
संघ राज्य क्षेत्र				
अंडमान और निकोबार दीप समूह	0.92	0.62	—	—
चंडीगढ़	13.01	27.82	—	0.80
दमन	0.23	0.61	—	0.01
दीव	—	0.08	—	—
दादरा और नागर हवेली	0.01	0.18	—	—
नई दिल्ली	811.00	578.17	0.87	28.49
पांडिचेरी	1.55	5.91	0.01	0.12
लक्षद्वीप	—	—	—	—

विवरण-III

वर्ष 1991-92 के दौरान निगम कर, आयकर, सम्पदा शुल्क और धन कर से संग्रहण

(करोड़ रुपए)

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	निगम कर	आयकर	संपदा शुल्क	धन कर
राज्य				
आन्ध्र प्रदेश	115.93	265.94	—	9.50
अरुणाचल प्रदेश	—	0.22	—	—
असम	41.44	67.66	0.01	1.64
बिहार	22.25	171.56	—	1.90
गोवा	25.14	27.68	(-) 0.06	1.99
गुजरात	136.35	560.49	0.18	22.11
हरियाणा	25.27	84.95	—	3.55
हिमाचल प्रदेश	1.39	21.96	—	0.39
जम्मू व कश्मीर	21.78	27.65	—	—
कर्नाटक	118.26	341.79	0.09	15.13
केरल	70.90	187.05	0.11	5.13
मध्य प्रदेश	27.02	213.76	0.16	4.92
महाराष्ट्र	3375.01	1980.46	0.90	120.26
मणिपुर	0.05	2.11	—	0.06
मेघालय	0.48	4.21	—	0.19
मिजोरम	—	—	—	—
नागालैंड	0.04	2.63	—	0.02
उड़ीसा	20.49	79.00	—	0.48
पंजाब	138.88	199.36	0.02	9.34
राजस्थान	49.33	142.62	0.01	4.78
सिक्किम	0.16	0.30	—	—
तमिलनाडु	477.23	553.51	0.23	33.86
त्रिपुरा	0.03	4.80	—	0.05
उत्तर प्रदेश	284.42	427.81	0.08	9.72
पश्चिम बंगाल	872.82	424.80	0.07	20.65

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	निगम कर	आयकर	संपदा शुल्क	धन कर
संघ राज्य क्षेत्र				
अंदमान और निकोबार दीप समूह	2.91	0.48	—	0.01
चंडीगढ़	23.19	32.23	0.01	1.12
दमन	0.09	0.80	—	0.02
दीव	—	0.08	—	—
दादरा और नागर हवेली	0.01	0.24	—	—
दिल्ली	1039.72	729.06	1.05	39.18
पांडिचेरी	1.68	8.04	0.01	0.31
लक्षद्वीप	—	—	—	—

विवरण-IV

वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान संघ उत्पाद शुल्कों से संग्रहण (अनन्तिम)
(करोड़ रुपए)

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	1991-90	1990-91	1001-92 (अनन्तिम)
1. आन्ध्र प्रदेश	1411.56	1476.95	1855.34
2. असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश	745.72	696.54	720.94
3. बिहार	903.48	1024.48	1139.63
4. पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	527.34	535.97	639.50
5. हरियाणा और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली	1132.96	1344.06	1653.99
6. गोवा	104.69	122.44	148.84
7. गुजरात और दादरा तथा नागर हवेली और दमन और दीव	2428.30	2652.92	3085.88
8. कर्नाटक	1271.23	1403.88	1675.66
9. केरल और लक्षद्वीप संघ राज्य	489.99	543.53	649.76
10. मध्य प्रदेश	1079.97	1208.01	1471.61
11. महाराष्ट्र	6602.16	7205.56	7945.66
12. उड़ीसा	326.33	406.95	446.18
13. राजस्थान	612.63	675.84	833.51
14. तमिलनाडु और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र	1645.01	1798.26	2133.09

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	1991-90	1990-91	1001-92 (अनन्तिम)
15. उत्तर प्रदेश	1923.74	2173.59	2490.19
16. पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र	1284.00	1374.81	1493.04

टिप्पणी:—ये आंकड़े राज्य के कलकटरी से राजस्व के संग्रहण पर आधारित हैं; इससे अधिक विस्तृत विधानन तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

विवरण-V

वर्ष 1989-90 के दौरान राज्यों को अदा किए गए केन्द्रीय करों और शुल्कों का हिस्सा
(करोड़ रुपयों में)

राज्य	आयकर	मूल उत्पाद शुल्क	अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	कृषि सम्पत्ति पर धन कर
आंध्र प्रदेश	289.34	541.65	123.94	
अरुणाचल प्रदेश	2.46	65.28	1.46	
असम	98.35	308.25	42.18	
बिहार	477.52	934.20	132.57	
गोवा	3.36	19.34	3.35	
गुजरात	169.39	214.85	95.77	
हरियाणा	42.63	74.17	37.31	0.06
हिमाचल प्रदेश	19.98	123.77	10.30	
जम्मू और कश्मीर	27.01	215.79	14.23	
कर्नाटक	194.63	350.56	87.71	0.16
केरल	140.13	255.50	60.27	
मध्य प्रदेश	312.49	601.02	110.31	
महाराष्ट्र	398.28	388.94	185.96	
मणिपुर	7.11	71.75	3.00	
मेघालय	7.17	55.21	2.79	

राज्य	आयकर	मूल उत्पाद शुल्क	अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	कृषि सम्पत्ति पर धन कर
मिजोरम	2.20	73.74	0.89	
नागालैण्ड	2.55	74.39	1.95	
उड़ीसा	158.38	356.83	57.38	
पंजाब	62.03	90.18	55.41	0.02
राजस्थान	186.41	383.94	72.63	
सिक्किम	1.04	14.29	0.74	
तमिलनाडु	299.50	535.70	112.08	0.07
त्रिपुरा	10.53	91.37	4.35	
उत्तर प्रदेश	713.08	1367.57	220.32	
पश्चिम बंगाल	296.62	533.75	131.17	
जोड़	3922.19	7742.04	1568.07	0.31

विवरण-VI

वर्ष 1990-91 के दौरान अदा किए गए केन्द्रीय करों और शुल्कों का हिस्सा

(करोड़ रुपयों में)

राज्य	आयकर	बुनियादी उत्पाद शुल्क	अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	कृषि सम्पत्ति पर धन कर
आन्ध्र प्रदेश	338.21	627.38	128.40	
अरुणाचल प्रदेश	3.01	77.35	1.72	
असम	108.41	333.40	45.82	
बिहार	511.68	964.95	139.22	
गोवा	4.53	45.07	3.69	
गुजरात	187.48	278.16	98.78	0.07
हरियाणा	51.26	95.82	58.82	
हिमाचल प्रदेश	24.52	169.88	10.40	
जम्मू और कश्मीर	28.64	309.10	15.52	

राज्य	आयकर	बुनियादी उत्पाद शुल्क	अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	(करोड़ रुपयों में) कृषि सम्पत्ति पर धन कर
कर्नाटक	203.06	359.29	98.00	0.16
केरल	153.65	270.25	62.36	
मध्य प्रदेश	337.26	632.34	119.75	
महाराष्ट्र	337.51	453.70	198.65	0.01
मणिपुर	7.05	102.64	3.55	
मेघालय	8.57	77.98	3.17	
मिजोरम	3.01	95.60	1.09	
नागालैण्ड	3.95	117.83	2.00	
उड़ीसा	178.25	467.47	58.37	
पंजाब	70.29	118.81	59.14	0.02
राजस्थान	199.27	481.11	78.48	
सिक्किम	1.24	22.73	0.86	
तमिलनाडु	326.80	557.79	118.33	
त्रिपुरा	12.48	135.82	4.65	
उत्तर प्रदेश	691.70	1368.77	245.03	
पश्चिम बंगाल	328.65	578.66	136.73	
जोड़	4120.48	8741.90	1672.53	0.26

विवरण— VII

वर्ष 1991-92 के दौरान राज्यों को अदा किए गए केन्द्रीय करों और शुल्कों का हिस्सा

(करोड़ रुपए)

राज्य	आयकर	मूल उत्पाद शुल्क	अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	कृषि सम्पत्ति पर धनकर
आन्ध्र प्रदेश	419.08	729.57	147.58	
अरुणाचल प्रदेश	3.68	91.63	2.10	
असम	134.43	387.56	52.63	

(करोड़ रुपए)

राज्य	आयकर	मूल उत्पाद शुल्क	अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	कृषि सम्पत्ति पर घनकर
बिहार	633.84	1122.15	160.13	
गोवा	5.55	52.95	4.42	
गुजरात	232.23	323.43	113.57	0.07
हरियाणा	63.41	111.38	44.65	
हिमाचल प्रदेश	30.36	198.19	11.97	
जम्मू और कश्मीर	35.57	359.73	17.82	
कर्नाटक	251.65	417.83	112.60	0.16
केरल	190.42	314.27	71.74	
मध्य प्रदेश	418.03	735.37	137.62	
महाराष्ट्र	418.35	527.60	228.30	0.01
मणिपुर	8.76	119.80	4.08	
मेघालय	10.61	91.01	3.65	
मिजोरम	3.68	112.95	1.34	
नागालैण्ड	4.90	137.60	2.29	
उड़ीसा	220.80	542.59	67.14	
पंजाब	87.13	138.11	68.03	0.02
राजस्थान	246.74	559.23	90.25	
सिक्किम	1.51	26.53	0.99	
तमिलनाडु	404.72	648.61	136.13	
त्रिपुरा	15.45	158.40	5.35	

(करोड़ रुपए)

राज्य	आयकर	मूल उत्पाद शुल्क	अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	कृषि सम्पत्ति पर धनकर
उत्तर प्रदेश	857.81	1591.77	281.64	
पश्चिम बंगाल	407.13	671.00	157.29	
जोड़	5105.84	10169.26	1923.31	0.26

विवरण- VIII

नौवें वित्त आयोग (1990-91 से 1994-95 की दूसरी रिपोर्ट) की सिफारिशों के अनुसार आयकर, संघ उत्पाद शुल्क में राज्यवार प्रतिशत हिस्से को दर्शाने वाला विवरण

हिस्से की प्रतिशतता

क्रम सं०	राज्य	आयकर	मूल उत्पाद शुल्क	अतिरिक्त उत्पाद शुल्क
1.	आन्ध्र प्रदेश	8.208	7.170	7.680
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.073	0.897	0.107
3.	असम	2.631	3.810	2.743
4.	बिहार	12.418	11.028	8.317
5.	गोवा	0.110	0.523	0.228
6.	गुजरात	4.550	3.183	5.905
7.	हरियाणा	1.244	1.099	2.317
8.	हिमाचल प्रदेश	0.595	1.943	0.621
9.	जम्मू और कश्मीर	0.695	3.548	0.929
10.	कर्नाटक	4.928	4.104	5.865
11.	केरल	3.729	3.087	3.723
12.	मध्य प्रदेश	8.185	7.224	7.164

क्रम सं०	राज्य	हिस्से की प्रतिशतता		
		आयकर	मूल उत्पाद शुल्क	अतिरिक्त उत्पाद शुल्क
13.	महाराष्ट्र	8.191	5.185	11.886
14.	मणिपुर	0.171	1.174	0.213
15.	मेघालय	0.208	0.891	0.190
16.	मिजोरम	0.073	1.109	0.068
17.	नागालैण्ड	0.096	1.348	0.120
18.	उड़ीसा	4.326	5.358	3.486
19.	पंजाब	1.706	1.362	3.533
20.	राजस्थान	4.836	5.524	4.689
21.	सिक्किम	0.030	0.260	0.052
22.	तमिलनाडु	7.931	6.379	7.064
23.	त्रिपुरा	0.303	1.556	0.278
24.	उत्तर प्रदेश	16.787	15.638	14.657
25.	पश्चिम बंगाल	7.976	6.600	8.165
जोड़		100.00	100.00	100.00

रबड़ का उत्पादन, खपत और निर्यात

2694. प्रो० के० वी० धामसः क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान रबड़ का कितना उत्पादन हुआ और इसकी खपत कितनी हुई तथा चालू वर्ष के दौरान इसका कितना उत्पादन एवं खपत होने का अनुमान है;

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की रबड़ निर्यात की गई और चालू वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में निर्यात किये जाने का विचार है;

(ग) रबड़ की खेती के विकास हेतु क्या योजनायें बनाई गयी हैं; और

(घ) रबड़ से बने उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुरशीद) : (क) वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन और खपत (अनुमानित) निम्नलिखित हैं:—

(मी० टन में)

वर्ष	उत्पादन	खपत
1991-92	366,745	380,150
1992-93	407,000*	407,000*

* अनुमानित

(ख) वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान निर्यात की गई रबड़ की मात्रा और मूल्य निम्नलिखित हैं:—

वर्ष	एस टी सी द्वारा निर्यात की मात्रा (एम टी)	(मूल्य करोड़ रुपयों में)	गैर सरकारी कम्पनियों द्वारा निर्यात की गई मात्रा (एम टी)	मूल्य करोड़ रुपयों में
1991-92	5834	9.27*	—	—
1992-93 (6.6.92 तक)	5988.45	10.57*	11	0.03*

* लगभग

(ग) रबड़ की खेती के विकास के लिए निम्नलिखित उपाय लागू किये जा रहे हैं:—

- रबड़ रोपण विकास योजना के अन्तर्गत नवरोपण और पुनरोपण के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता देना, जैसे:—
 - परम्परागत क्षेत्रों में 5 हेक्टेयर तक के छोटी जोत वाले और गैरपरम्परागत क्षेत्रों में सभी उपजकर्ताओं को 5000/- रु० प्रति हेक्टेयर की दर से पूंजीगत इमदाद।
 - उच्च गुणवत्ता वाले पालीबैग पौध का प्रयोग करने के लिए सभी श्रेणी के उपजकर्ताओं को 6/- रु० प्रति पौध की दर से अधिकतम 2700/- रु० प्रति हेक्टेयर तक अतिरिक्त सहायता।

(iii) रोपण और परिपक्वता तक अनुरक्षण लागत के लिए नाबार्ड प्रोग्राम के तहत कार्यरत बैंकों से दीर्घावधि सहायता । ऐसे ऋणों पर परम्परागत क्षेत्रों में 5 हेक्टेयर तक के उपजकर्ताओं को और गैरपरम्परागत क्षेत्रों में सभी उपजकर्ताओं को बोर्ड 3% ब्याज का भुगतान करता है।

2. उच्च उपज वाली रोपण सामग्री का उत्पादन और वितरण करना।
3. परामर्शी, विस्तार और प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान करना।
4. छोटे धारकों में सामुदायिक प्रसंस्करण और विपणन को प्रोत्साहित करना।
5. रबड़ की खेती उत्पादन और प्रसंस्करण पर अनुसंधान करना।

(घ) टायरों सहित रबड़ पर आधारित उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए अनेकों उपाय किए गए हैं जैसे रबड़ विनिर्माण उत्पाद उद्योग से बिक्री दलों के दौरे, संयुक्त बिक्री-सह-अध्ययन दलों के दौरे, विदेशों में प्रदर्शनियों और मेलों में भागीदारी, विदेशी समाचार पत्रों में विशेष परिशिष्ट प्रकाशित करना, मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस शुरू करना, ई पी सी जी योजना आदि।

वातानुकूलकों का निर्यात

2695. श्री गोपीनाथ गजपति: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1991-92 के दौरान मध्य-पूर्व देशों को कितने मूल्य के वातानुकूलकों (एयरकंडीशनर्स) का निर्यात किया गया; और

(ख) 1992-93 के लिए कितने निर्यात आदेश प्राप्त हुए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुरशीद): (क) और (ख) इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् के निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर वर्ष 1991-92 के दौरान मध्य-पूर्व के देशों को 1.12 करोड़ रुपए मूल्य के वातानुकूलकों का निर्यात किया गया था। वर्ष 1992-93 के लिए मैसर्स एयर कमांड इंडिया लि०, बड़ौदा, मैसर्स एम्प्रेक्स लि०, अहमदाबाद और मैसर्स यूनी एयर रेफ्रीजेशन प्रा० लि० के पास 8.76 करोड़ रुपए मूल्य के आर्डर होने का पता चला है। इसके अलावा ऐसा पता चला है कि मैसर्स वोल्टास 200 वातानुकूलकों की सप्लाई करने के लिए एक संविदा कर रहा है।

नई कपड़ा मिलें

2696. श्री सुशील चन्द्र वर्मा: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी नई कपड़ा मिलें स्थापित की गईं और वे किन-किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ख) इनमें से श्रेणीवार कितनी मिलें कताई और बुनाई के लिये केवल रूई का इस्तेमाल कर रही हैं और कितनी रूई के साथ-साथ मानव निर्मित धागे का इस्तेमाल कर रही हैं; और

(ग) आठवीं योजना अवधि के दौरान कपड़ा क्षेत्र के विकास की योजना की मुख्य बातें क्या हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में

50 नई सूती/मानवनिर्मित फाइबर वस्त्र मिलों ने उत्पादन शुरू कर दिया है। राज्य-वार स्थापित मिलों की स्थिति संलग्न विवरण-I के अनुसार है।

(ख) उपरोक्त मिलों में से 25 मिलें यार्न विनिर्माण के लिये केवल कपास का प्रयोग कर रही थीं। बाकी 25 मिलें वस्त्र यार्न के उत्पादन के लिये कपास और मानव-निर्मित फाइबर का प्रयोग कर रही थीं।

(ग) आठवीं योजना के दौरान वस्त्र क्षेत्र के विकास के लिये योजना की मुख्य-मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:—

1. आठवीं योजना के अन्तिम वर्ष तक कुल 2525 मिलियन स्पन यार्न की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है जिसमें निर्यात और अन्य प्रयोगों के लिये कपड़े के उत्पादन की आवश्यकता को ध्यान में रखा गया है।

2. वर्ष 1996-97 तक लगभग 29600 मिलियन वर्ग मी० कपड़े के उत्पादन का अनुमान लगाया गया है।

3. वर्ष 1996-97 तक अपेक्षित तकुओं की स्थापित क्षमता 34.73 मिलियन होगी। मिलों में मशीनरी का पर्याप्त आधुनिकीकरण हो जाने की आशा है।

4. ऐसी आशा है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में मूल्य की दृष्टि से निर्यात 35568 करोड़ रु० तक पहुंच जायेंगे।

5. हथकरघा, विद्युत करघा का विकास और सार्वजनिक क्षेत्र का पुनः निर्माण करने का भी प्रस्ताव है।

विवरण-I

लोक सभा में दिनांक 24.7.1992 को पूछे जाने वाले अतारंकित संख्या 2696 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

तमिलनाडु	मिलों की संख्या
1. पुदुचेरी	1
2. डीडीगुल	4
3. वीरपण्डी	1
4. कानमपलयम	1
5. अरुप्पकोट्टई	1
6. कोयमबूर	3
7. पेरीयार	1
8. उदमलपेट	1
9. पलायम	1
10. मदुरै	1
11. करईकुडी	1
12. अवानाशी	2
13. विलाची	1
14. मनगुडी	1
15. तिरुमाचोर्नई	1
16. चिंतामनि पुदूर	1
17. धर्मपुरी	1
18. कोलापटी	1

	मिलों की संख्या
19. उदमालापेट	1
20. वेलामदैइ	1
	<hr/>
	26
	<hr/>
महाराष्ट्र	
21. अमरावती	1
22. बुलघाना	3
23. यवतमाल	1
24. वर्धा	1
	<hr/>
	6
	<hr/>
पांडिचेरी	
25. विलियानूर	1
26. नीतापक्कम	1
	<hr/>
	2
	<hr/>
आन्ध्र प्रदेश	
27. प्रकाशम	1
28. चित्तूर	1
29. गंडूर	1
30. कामम	1
31. नालगोंडा	1
	<hr/>
	5
	<hr/>
मध्य प्रदेश	
32. राजगढ़	1
33. धार	1
34. रंजना	1
	<hr/>
	3
	<hr/>

पंजाब	मिलों की संख्या
35. लुधियाना	2
	2
हिमाचल प्रदेश	
36. सोलन	1
	1
उत्तर प्रदेश	
37. गजियाबाद	2
38. मथुरा	1
	3
कर्नाटक	
39. धारवाड़	1
	1
झारखण्ड	
	1
	1

अलौह-धातुओं के आयात को गैर-सरणीकृत करना

2697. श्री गुरुदास कामत: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अलौह-धातुओं के आयात को गैर-सरणीकृत किया है अथवा करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुरशीद): (क) और (ख) अलौह-धातुओं के आयात का सरणीकरण 29-2-1992 को व्यापार नीति के उदारीकरण के भाग के रूप में किया गया था ताकि कच्चे माल, मध्यवर्ती, संघटक, उपभोज्य सामग्री, आदि की पहुंच को सुगम बनाकर भारत के निर्यातों को बढ़ाया जा सके।

[हिन्दी]

अनिवासी भारतीयों से प्राप्त विदेशी मुद्रा

2698. श्री भगवान शंकर रावत: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1991-92 के दौरान तथा 1 अप्रैल, 1992 से 30 जून, 1992 तक अनिवासी भारतीयों से उपहार के रूप में तथा अन्यथा देशवार कुल कितनी विदेशी मुद्रा माहवार प्राप्त हुई;

(ख) क्या सरकार का विचार अनिवासी भारतीयों से विदेशी मुद्रा प्राप्त करने हेतु कोई अन्य उपाय करने अथवा नई योजना शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) से (घ) अनिवासी भारतीय निवेश के लिए नीतियां और योजनाएं निरन्तर समीक्षाधीन हैं। 4 जून, 1992 को सरकार ने एक अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया जमा योजना की घोषणा की है, जिसके अन्तर्गत अनिवासी भारतीयों द्वारा राशि विदेशी मुद्रा में भेज कर सावधि जमाओं के रूप में जमा की जा सकती है। बैंक इस प्रकार की सावधि जमा राशियों पर ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है। यह आशा की जाती है कि यह योजना अप्रत्यावर्तनीय आधार पर भारत में निवेश करने के लिए अनिवासी भारतीयों को अत्यधिक प्रोत्साहित करेगी।

सरकार ने फेरा, 1973 की धारा 14 के अन्तर्गत कतिपय रियायतों की भी घोषणा की है, जिसके द्वारा अनिवासी भारतीय यदि लगातार कम से कम एक वर्ष विदेश में रहने के बाद भारत वापिस लौटते हैं तो विदेश में उनके द्वारा धारित सार्वभौमिक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों को घोषित करने या समर्पण करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इससे भारत में अनिवासी भारतीय निवेशों के अन्तःप्रवाह में सहायता मिलेगी।

[अनुवाद]

त्रिपुरा में भारतीय पटसन निगम का कार्य निष्पादन

2699. श्री सैफुद्दीन चौधरी: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पटसन निगम ने त्रिपुरा में अपना कार्य बन्द कर दिया है; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या त्रिपुरा के पटसन उत्पादकों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य से भी वंचित करने वाले धोखेबाज बिचौलियों की दया पर छोड़ दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो पिछले पटसन सत्र के दौरान भारतीय पटसन निगम की त्रिपुरा में मात्रावार तथा कोषवार क्या कार्यनिष्पादन रहा?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय पटसन निगम ने अपने सहकारी एजेंटों के सहयोग से वर्ष 1991-92 के पटसन मौसम के दौरान त्रिपुरा से लगभग 90 लाख मूल्य के 28,548 विंटल कच्चे पटसन की खरीद की।

करों का समान कोड

2700. श्री बी० देवराजन:

श्री एस० बी० थोरात:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और केन्द्रीय उत्पाद कर और नमक अधिनियम, 1944 और इससे संबंधित अन्य अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों को सम्मिलित करते हुए अप्रत्यक्षकरों का एक समान कोड तैयार करने हेतु विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के गठन और कार्यों का ब्यौर क्या है और यह अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगी;

(ग) क्या प्रत्यक्ष करों के लिए भी कोई ऐसा प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) जी, हां।

(ख) समिति के गठन का ब्यौर निम्नानुसार है:—

(1) श्री के० एल० रेखी, के०उ०शु०सी०शु० बोर्ड के सेवामुक्त अध्यक्ष	— अध्यक्ष
(2) श्री रविन्द्र नारायण, अधिवक्ता,	— सदस्य
(3) श्री सुभाष एन० पारिख, अधिवक्ता,	— सदस्य
(4) श्री एल० पी० अस्थाना, के०उ०शु०सी०शु० बोर्ड के सेवामुक्त समाहर्ता	— सदस्य
(5) श्री टी० एस० सुन्दरम, पी०एच०डी० चैम्बर आफ कांमर्स, नई दिल्ली के सहायक महासचिव	— सदस्य सचिव

समिति सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं नमक अधिनियम 1944 और उनसे संबंधित अन्य किन्हीं अधिनियमों अथवा नियमों के प्रावधानों को सम्मिलित करते हुए अप्रत्यक्ष करों का एक समान कोड तैयार करेगी। कोड का प्रारूप तैयार करते समय समिति विद्यमान विधियों और प्रक्रिया के सरल और कारगर बनाने के उद्देश्य को ध्यान में रखेगी।

समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट छः महीने के भीतर प्रस्तुत करने की सम्भावना है।

(ग) जी, हां,

(घ) प्रत्यक्ष करों के संबंध में एक समान कोड तैयार करने का कार्य एक प्रख्यात अधिवक्ता को सौंपा गया है, जिनकी सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है।

भारतीय सामाजिक सुरक्षा तंत्र कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक का ऋण

2701. श्री श्रावण कुमार पटेल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सामाजिक सुरक्षा तंत्र कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ऋण हेतु समझौता हो गया है;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक द्वारा पोषित किए जाने वाले इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह समझौता फिलहाल किस स्थिति में है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) और (ख) : जी, नहीं।

(ग) प्रस्तावित सामाजिक सुरक्षा तंत्र कार्यक्रम के अंतर्गत क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं पर इस समय विभिन्न मंत्रालयों में चर्चा चल रही है। इन योजनाओं के बारे में अंतिम निर्णय हो जाने के बाद इस मामले पर विश्व बैंक के साथ आगे बातचीत की जाएगी।

विदेशी ऋणों का उपयोग

2702. डा० महादीपक सिंह शाक्य:

श्री नीतीश कुमार:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विश्व बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों का उपयोग नहीं कर पा रही है जैसाकि 13 जून, 1992 के "फाइनेंसियल एक्सप्रेस" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में किए गए कुल ऋण में से कुल कितनी ऋण राशि उपयोग नहीं की जा सकी है;

(ग) क्या सरकार विदेशी ऋणों का पर्याप्त रूप से उपयोग करने हेतु कदम उठा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) यह समाचार पत्र—रिपोर्ट विश्व बैंक की उन सिफारिशों के संदर्भ में है जो पेरिस में हुई भारत सहायता संघ की बैठक में जून, 1992 में की गई थीं। इस रिपोर्ट में, भारत के मध्यावधिक आर्थिक कार्यक्रम के समर्थन में वांछनीय उपायों के विषय में विश्व बैंक द्वारा की गई सिफारिशों का उल्लेख किया गया है।

(ख) से (ङ) 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार, विश्व बैंक से लिए गए ऋणों का उपयोग में न लाई गई कुल शेष राशि 1111.6 करोड़ अमेरिकी डालर थी। सहायता के संबंध में की जाने वाली बातचीत एक सतत् प्रक्रिया है और विदेशी सहायता का पूरा उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, जब कभी आवश्यक होता है, उपयुक्त सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

ग्रामीण ऋणग्रस्तता

2703. श्री शिवाजी पटनायक: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 1992 को प्रत्येक राज्य में ग्रामीण ऋणग्रस्तता का ब्यौरा क्या था;

(ख) ऋण माफी योजना का इस पर क्या प्रभाव पड़ा; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) से (ग): कृषि तथा ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के पात्र ऋणकर्ताओं पर लागू होती थी। यह योजना 31 मार्च, 1991 को समाप्त हो गयी है। इस योजना के तहत बैंकों द्वारा बट्टे-खाते डाले गये ऋणों के अंतरिम आंकड़े निम्नानुसार हैं:—

सरकारी क्षेत्र के बैंक	2858.42 करोड़ रुपए
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	803.50 करोड़ रुपए
सहकारी बैंक	4155.00 करोड़ रुपए
	—————
जोड़	7816.92 करोड़ रुपए
	—————

ए०आर०डी०आर० योजना के कार्यान्वयन में, इस योजना के तहत केवल पात्र संस्थाओं से लिए गये बकाया ऋणों के सशर्त अतिदेय हिस्से को ही शामिल किया गया था। जून, 1991 की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों से बकाया ऋणों का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और ऋण संस्थाएं, क्षेत्र में वसूली संबंधी वातावरण में सुधार लाने तथा निधियों का पुनः उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करती हैं। किसी भी ऋण को आमतौर पर बट्टे खाते डालने के लिए किसी ऐसी अन्य कार्रवाई का सहारा लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है जिससे ऋण की वसूली संबंधी स्थिति दूषित हो जाये। इस संबंध में किये गये कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं—

1. नियंत्रक कार्यालयों एवं क्षेत्र स्तरों पर संगठनात्मक ढांचे को मजबूत और अनुकूल बनाना।
2. ऋणों के लिए योजनाबद्ध दृष्टिकोण अपनाना।
3. अन्य बातों के साथ-साथ हिताधिकारियों से निरंतर संपर्क स्थापित करके ऋण देने से पहले की मूल्यांकन प्रणाली एवं ऋण देने के बाद पर्यवेक्षण तकनीक में तेजी लाना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चूके कम से कम हों।
4. ब्लाक स्तर पर राज्य सरकार के अधिकारियों की मदद से वसूली अभियान चलाना।
5. बैंकों और सहकारी अधिकारियों की जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय बैठकों में वसूली निष्पादन पर एक मद के रूप में विचार-विमर्श किया जाना।
6. बैंकों से अपनी ग्रामीण शाखाओं में सप्ताह में एक दिन गैर-बैंकिंग कारोबार दिवस के रूप में रखने के लिए कहा गया है।
7. शाखा प्रबंधकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि देय राशियों की वसूली के लिए फसल कटने के मौसम का कारगर ढंग से उपयोग किया जाए।

विवरण

जून, 1991 के अन्त की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय प्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों से राज्यवार बकाया ऋण को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपयों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र के बैंक	क्षेत्रीय प्रामीण बैंक	सहकारी बैंक (प्राथमिक भूमि विकास बैंक स्तर पर)
1	2	3	4
हरियाणा	529.12	111.64	271.91
हिमाचल प्रदेश	332.06	19.76	2.99
जम्मू व कश्मीर	42.80	23.30	15.21
पंजाब	1227.13	50.34	318.80
राजस्थान	595.94	128.97	175.39
गुजरात	10.67	—	—
दिल्ली	62.91	—	—
अरुणाचल प्रदेश	23.52	0.83	—
असम	253.73	74.44	11.62
मणिपुर	17.10	2.03	—
मेघालय	20.82	5.23	—
मिजोरम	5.25	2.80	—
नागालैंड	1819.	0.28	—
त्रिपुरा	24.95	47.34	2.09
बिहार	1109.11	330.27	148.21
उड़ीसा	506.63	178.15	55.11
सिक्किम	5.64	—	—
पश्चिम बंगाल	770.68	182.98	74.04
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	4.29	—	—
मध्य प्रदेश	1027.50	261.30	277.52
उत्तर प्रदेश	2052.98	661.72	577.78
गोवा	100.98	—	—
गुजरात	1126.19	58.80	189.96
महाराष्ट्र	1165.12	118.58	605.50

1	2	3	4
दादर और नागर हवेली	8.37	—	—
दमन और दीप	.40	—	—
आन्ध्र प्रदेश	1366.47	366.10	532.03
कर्नाटक	1122.97	308.15	386.09
केरल	195.50	85.84	305.56
तमिलनाडु	1483.84	56.18	195.27
लक्षद्वीप	1.52	—	—
पाण्डिचेरी	26.48	—	3.84

[हिन्दी]

चावल तथा गेहूँ का निर्यात

2704. श्रीमती शीला गौतम:

श्री दत्तात्रेय बंडारू:

श्रीमती कुञ्जोन्न कौर:

श्री राजेश कुमार:

श्री तेज नारायण सिंह:

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान रबी तथा खरीफ फसलों के अत्यधिक उत्पादन को देखते हुए चावल तथा गेहूँ के निर्यात में वृद्धि करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान चावल तथा गेहूँ का कितनी-कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का निर्यात किये जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) (क) से (ग): मांग और पूर्ति की स्थिति को देखते हुए यह अनुमान है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 760 करोड़ रुपये मूल्य का 5,00,00 एम टी बासमती और गैर-बासमती चावल तथा 2.66 करोड़ रुपये मूल्य का 10,000 एम टी गेहूँ निर्यात किया जाएगा।

बैंकों में वकीलों का पैनाल

2705. श्री राजेश कुमार:

श्री तेजनारायण सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान दिल्ली क्षेत्र में पंजाब नेशनल बैंक, न्यू बैंक आफ इंडिया, ओरियंटल बैंक आफ कॉमर्स, यूको बैंक, भारतीय स्टेट बैंक तथा बैंक आफ बड़ौदा के पैनाल में वकीलों की संख्या कितनी थी;

(ख) इनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदायों के कितने वकील थे; और

(ग) इन वकीलों को कितनी धनराशि दी गयी तथा उक्त अवधि के दौरान उन्होंने कितने मामलों को निपटाया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) (क) से (ग): पंजाब नेशनल बैंक, न्यू बैंक आफ इण्डिया, ओरियंटल बैंक आफ कामर्स, यूको बैंक और बैंक आफ बड़ौदा द्वारा दी गई सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

भारतीय स्टेट बैंक के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

दो वर्षों अर्थात् अप्रैल 1990 से मार्च, 1992 के दौरान दिल्ली क्षेत्र में बैंकों के पैनाल में अधिवक्ताओं के बारे में सूचना

क्रम सं०	बैंक	अधिवक्ताओं की संख्या	अनु०जाति/अनु० जनजाति/पिछड़ी सभी जातियों और अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित अधिवक्ताओं की संख्या	सुपुर्द किए गए अनु० अधिवक्ता	गए मामलों की संख्या केवल अनु० जाति/अनु० जनजाति से संबंधित	मुगतान की गई राशि	केवल अनु० जाति/अनु० जनजाति से सम्बन्धित (रुपए)
1.	पंजाब नेशनल बैंक	123	15	198	41	4,13,352.45	19,470.00
2.	न्यू बैंक आफ इंडिया	155	16	449	36	4,86,037.00	32,185.00
3.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	48	4	389	52	3,24,253.95	36,647.00

क्रम सं०	बैंक	अधिवक्ताओं की संख्या	अनु०जाति/ अनु० जनजाति/ पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित अधिवक्ताओं की संख्या	सुपुर्द किए गए कर्मी केवल अनु० जाति/ अनु० जनजाति से संबंधित	मामलों की संख्या केवल अनु० जाति/ सभी अधिवक्ता (रुपए)	भुगतान की गई राशि	केवल अनु० जाति/ अनु० जनजाति से सम्बन्धित (रुपए)
4.	यूको बैंक	32	3	49	1	6,64,103.35	24,404.75
5.	बैंक ऑफ बड़ौदा	17	3	42	15	2,93,800.45	35,045.00

[अनुवाद]

आयकर अपवंचन के मामले

2706. श्री सत्य देव सिंह:

श्री विलासराव नागनाथराव गूण्डेवार:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान आयकर अपवंचन के समाहर्तालय-वार कितने मामले पकड़े गए;

(ख) अब तक कितने मामले निपटाए गए हैं;

(ग) समाहर्तालय-वार इन कर-अपवंचकों से आयकर और दण्ड के रूप में कितनी राशि वसूल की गई; और

(घ) आयकर अपवंचन को रोकने के लिए क्या कारगर उपाय किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) से (घ) आयकर की चोरी विविध कार्यवाहियों के दौरान अर्थात् धारा 133 ए(1), 133ए(5) तथा 133बी के अधीन किए गए सर्वेक्षणों, धारा 132 के अधीन ली गई तलाशियों तथा कर-निर्धारण की कार्यवाहियों के दौरान पकड़ी जाती हैं। इन विविध कार्यवाहियों के दौरान पकड़ी गई कर की चोरी के बारे में प्रभारवार किसी भी प्रकार के संयुक्त आंकड़े नहीं रखे जाते हैं और अधिकांश ऐसे मामलों को संप्रवतया अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है, जिनमें वर्ष 1991-92 के दौरान कर की चोरी पकड़ी गई थी। कर की चोरी के लिए दण्ड को कर-निर्धारण के खिलाफ की गई अपील पर निर्णय हो जाने के पश्चात् ही सामान्यतया आयद किया जाता है और इसलिए वर्ष 1991-92 के दौरान पकड़ी गई कर की चोरी के संबंध में अधिकांश मामलों में दण्डिक कार्यवाहियां अभी भी अनिर्णित पड़ी हुई हो सकती हैं।

वर्ष 1991-92 के दौरान ली गई तलाशियों के दौरान अभिगृहीत की गई अघोषित परिसम्पत्तियों तथा धारा 132(4) के अधीन घोषित की गई आय के आंकड़े निम्नानुसार हैं:—

वित्त वर्ष 1991-92 के लिए आयकर निदेशालय-वार तलाशी तथा अभिग्रहण के आंकड़े
(लाख रुपयों में)

आयकर निदेशालय (जांच)	ली गई तलाशियों की कुल संख्या	अभिगृहीत की गई अघोषित परिसम्पत्तियों का मूल्य	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132(4) के अधीन घोषणा
1	2	3	4
दिल्ली	304	2033.62	1648.78
चण्डीगढ़	257	453.06	597.23
कानपुर	364	1336.14	329.97
कलकत्ता	631	1663.82	800.19
अहमदाबाद	320	1994.46	4142.68
पुणे	177	711.75	1542.57
हैदराबाद	263	1360.95	1120.55
मद्रास	346	1324.54	1819.16
बंगलौर	181	1019.90	2372.32
बम्बई	625	6086.54	4461.98

हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के विमानपत्तन को पट्टे पर देना

2707. श्री जी० माडेगौड़ा: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के प्राधिकारियों ने बंगलौर में हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के विमानपत्तन को इण्डियन एयरलाइन्स को पट्टे पर दिया था;

(ख) क्या पट्टे की अवधि समाप्त हो गयी है;

- (ग) यदि हां, तो क्या हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने पट्टे का नवीकरण कर दिया है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ): प्रश्न नहीं उठते।

मुद्रै में मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ

2708. श्री बी० राज रविवर्मा: क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को तमिलनाडु सरकार की ओर से मुद्रै में मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यह खंडपीठ कब तक स्थापित हो जाएगी?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी): (क) से (ग) तमिलनाडु सरकार इस बात के लिए उत्सुक है कि मुद्रै में मद्रास उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित की जाए। किन्तु उन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के साथ कानूनी परामर्श पूरा नहीं किया है यदि, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के साथ पूर्ण परामर्श के पश्चात्, राज्य सरकार से कोई निश्चित प्रस्ताव प्राप्त होता है तो मामले में केन्द्रीय सरकार आवश्यक कार्रवाई कर सकती है। यह बताना संभव नहीं है कि न्यायपीठ की स्थापना कब तक की जा सकती है।

बैंकों का कार्यनिष्पादन

2709. श्री हरीश नारायण प्रभु झांद्ये: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक की लाभ/हानि, कार्यशील निधि, जमा और पेशगी दिए गये धन की राशि कितनी-कितनी थी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के लाभ/हानि, कार्यशील निधियों, जमा राशियों और अभिनों की राशियों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

विवरण

(करोड़ रुपए)

क्र.सं०	बैंक का नाम	वर्ष 1989-90					वर्ष 1990-91					वर्ष 1991-92				
		जमा- राशियां	अग्रिम हाप/ हानि (-)	कार्ब- शील पूंजी												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1.	इलाहाबाद बैंक	5253.63	2442.55	14.03	5911	6422.86	3016.87	21.04	7372	6653.64	3433.97	28.11	7757			
2.	बैंक आफ बड़ौदा	13033.47	8055.11	25.00	14582	14676.22	8977.04	35.05	16358	19049.51	10467.32	95.10	21399			
3.	बैंक आफ इडिया	15508.48	10120.08	18.11	17011	17510.90	11251.76	22.46	19602	19209.55	12572.07	56.63	23214			
4.	बैंक आफ महाराष्ट्र	3234.25	1649.61	3.02	3520	3432.23	1836.17	4.10	3939	3373.62	1817.66	4.04	4150			
5.	केनरा बैंक	10922.67	6498.48	61.27	14090	12578.49	7073.05	76.04	15127	14238.15	7999.85	156.59	16457			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	11456.63	5827.40	10.24	12613	12787.31	6460.43	12.53	14333	13027.64	6703.44	30.49	14409
7.	देता बैंक	3000.91	1495.13	1.50	3381	3271.95	1665.18	8.51	3697	3423.69	1675.60	9.10	4106
8.	इंडियन बैंक	7058.55	4914.13	16.08	8365	7948.34	5543.75	21.00	9909	8980.66	6469.69	36.50	11042
9.	इंडियन ओवरसीय बैंक	6653.26	4032.81	7.01	7598	7268.09	4574.86	10.41	8546	7851.07	5159.34	9.05	9395
10.	पंजाब नेशनल बैंक	12560.96	6478.62	28.67	14101	14851.60	7660.39	43.69	16716	16231.08	8349.61	112.44	19220
11.	सिटीकोट बैंक	6791.62	3886.26	8.22	7505	7377.19	3946.25	5.25	8006	7579.76	3851.77	4.46	8437
12.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	6301.07	3048.00	21.96	6862	7190.62	3572.39	11.56	7873	7928.75	3672.65	29.45	8783
13.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	4573.96	2287.06	1.15	5368	5067.04	2593.44	5.78	6146	5369.87	2811.49	6.68	6453

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14. यूको बैंक		8582.51	4974.32	4974.32	-54.59 (Loss)	9438	9176.64	5914.32	-42.96 (Loss)	10830	9607.31	6472.57	-20.99 (Loss)	11861
15. आन्धा बैंक		3225.70	1683.41	1683.41	7.75	3587	3534.47	1887.68	8.21	3978	3860.54	1904.38	8.42	4354
16. काशीराम बैंक		1530.62	898.51	898.51	4.60	1776	1888.50	934.26	4.65	2143	2346.99	1010.84	5.20	2677
17. न्यू बैंक आफ इंडिया		2042.61	1171.30	1171.30	-9.89 Loss	2296	2053.14	1057.62	-45.00 Loss	2408	2134.31	987.17	-41.52 Loss	2457
18. ओरियंटल बैंक आफ कामर्स		2470.84	1203.07	1203.07	12.85	2679	3028.49	1455.33	23.68	3292	3599.10	1763.27	26.78	2994
19. पंजाब एंड सिंध बैंक		2440.60	1222.78	1222.78	0.24	2681	2712.00	1405.00	-5.45 Loss	3105	*	*	*	*
20. बिजया बैंक		2357.13	1486.02	1486.02	7.24	2768	2541.48	1657.26	0.25	3322	2734.76	1539.58	1.84	3118

* Annual Accounts not yet finalised.

आर्थिक सुधार

2710. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत से और अधिक आर्थिक सुधार करने को कहा है जैसा कि 26 जून, 1992 के "टाइम्स आफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार कुछ और अधिक आर्थिक सुधार करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) 25-26 जून, 1992 को पेरिस में हुई भारत सहायता संघ की बैठक में कई दाता देशों और अन्य बहुपक्षीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों की तरह विश्व बैंक के उपाध्यक्ष ने भी भारत सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों की बहुत प्रशंसा की थी। लेकिन, उन्होंने यह आशा भी प्रकट की कि मध्यावधि में अन्तःसंबद्ध सुधारों को और अधिक गहन एवं व्यापक बनाकर इस सुधार-प्रक्रिया को आगे भी जारी रखा जाएगा। तथापि, विश्व बैंक द्वारा कोई विशिष्ट कार्ययोजना तैयार नहीं की गई।

(ग) से (ङ) आर्थिक सुधारों के और अधिक निर्देशन, 16 दिसम्बर, 1991 और 10 जुलाई, 1992 को सदन के पटल पर रखे गए आर्थिक संकटों के प्रबंधन विषयक वित्त मंत्री के वक्तव्य में और वर्ष 1992-93 के लिए आर्थिक नीतियों के ज्ञापन में पहले ही इंगित किए जा चुके हैं।

चावल और दाल के मूल्यों में वृद्धि

2711. श्री के० पी० रेड्डीय्या यादव: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चावल और दाल के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान चावल और दालों के निर्यात से कितनी अतिरिक्त आय हुई?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीदि) : (क) और (ख) बैंकाक बाजार में सफेद चावल (10% टूटा हुआ) के जो दाम बोले गये उसके अनुसार कीमत 12.7.91 को 302 अमरीकी डालर थी जो 10.7.92 को घटकर 290 अमरीकी डालर रह गयी। दालों की अनतर्राष्ट्रीय कीमत निम्नवत रही:—

किसम	कीमत अमरीकी डालर प्रति एम० टी० कीमत	
	20.7.91 को	13.7.91 को
1. अरहर (तूवर)	400 सी ऐण्ड एफ डी बम्बई (केनियन/तंजानियन)	325 सी आई एफ बम्बई (बर्मा क्री)
2. टायसन चिकपीज (काबुली चना)	300 सी आई एफ एफ ओ बम्बई (आस्ट्रेलियन)	225 सी आई एफ ओ बम्बई (आस्ट्रेलियन)
3. हरी मटर	295-300 सी आई एफ बम्बई (हंगारियन)	280 सी आई एफ बम्बई (हंगारियन)

स्रोत: साप्ताहिक बाजार सर्वेक्षण, कमोडिटीज (इण्डिया) प्रा० लिमिटेड, बम्बई।

(ग) वर्ष के दौरान (स्थानीय रूप से उत्पादित) दालों का कोई निर्यात नहीं हुआ। वर्ष 1991-92 के दौरान चावल निर्यात से 755 करोड़ रुपये प्राप्त हुए जबकि इससे पिछले वर्ष इससे 461 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे।

“फिक्की” और यू० एस० ए० आई० डी० के बीच बाजार सुधार संबंधी परियोजना हेतु करार

2712. श्री शरत् चन्द्र पटनायक: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फिक्की और यू० एस० ए० आई० डी० के बीच बाजार सुधार संबंधी परियोजनाएं शुरू करने के लिए कोई करार हुआ है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय विकास संयुक्त राज्य अभिकरण द्वारा इंडियन चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री “फिक्की” को 1,137,000 अमेरिकी डालर का अनुदान देने के लिए फिक्की और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संयुक्त राज्य अभिकरण के बीच 11.6.1992 को एक करार पर हस्ताक्षर हुए थे। इस करार में व्यवस्था है कि इस अनुदान का प्रयोजन, नई आर्थिक नीतियों के उद्देश्य और लाभों को केन्द्रित करते हुए सम्मेलन/कार्यशालाएं आयोजित करके भारत सरकार द्वारा घोषित विभिन्न आर्थिक सुधारों के कार्यान्वयन में सहायता देने के लिए प्रेरक वातावरण बनाने हेतु फिक्की की सहायता करना है। करार के अंतर्गत अनुदान का उद्देश्य वाणिज्यिक गतिविधियों में भारत अमेरिकी सहयोग के आम हित के क्षेत्रों का पता लगाना और भारतीय तथा अमेरिकी संगठनों के बीच संपर्क स्थापित करना है। फिक्की की प्रस्तावित गतिविधियों, जिनके लिए अनुदान दिया जाना है, की अनुमानित अवधि करार पर हस्ताक्षर होने की तारीख (अर्थात् 11.6.1992) से 18 महीने की है।

अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध विषय पर भारतीय अनुसंधान परिषद् का सम्मेलन

2713. डा० डी० वेंकटेश्वर रावः क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भारतीय अनुसंधान परिषद् ने अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास केन्द्र के साथ मिलकर नई दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध विषय पर कोई सम्मेलन आयोजित किया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई; और

(ग) सम्मेलन किन निष्कर्षों पर पहुंचा।

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्रिदी) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्ध अनुसंधान परिषद् तथा अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास केन्द्र द्वारा 25 से 27 मई, 1992 तक नई दिल्ली में "साउथ एशिया एस ए डायनामिक पार्टनर प्रासपेक्ट्स फार फ्यूचर" विषय पर संयुक्त रूप से एक सम्मेलन आयोजित किया था। इस सम्मेलन में जिन मुख्य विषयों पर चर्चा की गई वे थे; दक्षिण एशिया में नीति सुधार तथा गतिशील विकास; विश्वव्यापी तथा क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में दक्षिण एशिया; दक्षिण एशिया में उप-क्षेत्रीय सहयोग तथा सार्क एवं शेष एशिया प्रशान्त क्षेत्र के बीच सहयोग।

(ग) इस बात पर आम सहमति थी कि इस समय चल रही आर्थिक सुधारों की गति को इस क्षेत्र के सभी देशों में बनाये रखा जाए। इस बात पर भी सर्वसम्मति थी कि आर्थिक सुधारों के लाभ अब महसूस किए जा रहे हैं। भागीदारों का यह विचार था कि दक्षिण एशियाई राष्ट्रों में किए जा रहे उदारिकरण एवं आर्थिक सुधारों से सार्क की संरचना में क्षेत्रीय सहयोग के लिए अनुकूल वातावरण बनेगा। यह भी महसूस किया गया कि इन सुधारों से एक ओर सार्क तथा उसके सदस्य देशों के बीच तथा दूसरी ओर अभियान क्षेत्र, उसके सदस्यों तथा पूर्व एशियाई देशों के बीच सहयोग में भी वृद्धि होगी। इस सम्मेलन में यह निष्कर्ष निकला कि इस समय एशियाई पुनरुत्थान, जो दक्षिण एशिया के पास हो रहा है, यह दक्षिण एशियाई देशों का महत्वपूर्ण घटना क्रम है और इन देशों को शेष एशिया प्रशान्त क्षेत्र के साथ अपने सम्बन्ध विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिये ताकि वे एशियाई अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान में और अधिक सक्रिय भागीदार बन सकें।

व्यवधान

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा सोमवार 27 जुलाई, 1992 को 11 म० पू० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

11.04 म० पू०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 27 जुलाई, 1992/5 श्रावण, 1914 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2003 BY LOK SABHA SECRETARIAT

nder Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha
Tenth Edition) and Printed by The Indian Press, G.T. Karnal Road, Delhi-110033.